

(1100/RAJ/PS)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 61- डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता जी।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमें बोलने का मौका दिया जाए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन आपका है। मैं आपको हमेशा बोलने का मौका देता हूँ, लेकिन अभी प्रश्न काल चल रहा है। कृपया आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, कृपया हमें प्रश्न काल के बाद बोलने का मौका दीजिए...(व्यवधान)

(Q.61)

DR. VENKATESH NETHA BORLAKUNTA (PEDDAPALLE): Hon. Speaker, Sir, thank you very much. I would like to wish belated Happy Returns of the day to the hon. Minister of Youth Affairs and Sports. ...(*Interruptions*)

1101 hours

(At this stage, Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and stood near the Table.)

As per the answer given by the hon. Minister, for 2017-18, 2018-19 and 2019-20, funds were not allotted to school games. Schools are the foundation. Schools give mental and physical development to the kids. For girls, particularly, sports act as a defensive mechanism. ...(*Interruptions*)

In this context, through you, I would like to ask the hon. Minister as to what are the infrastructural facilities being provided in the State of Telangana and pan-India as well. What would be the plan of action for improving the facilities so as to have better standing in the sports arena in international games? ...(*Interruptions*)

श्री किरन रिजीजू : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य वेंकटेश जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने स्कूल गेम्स के बारे में सवाल पूछा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक स्कूल गेम्स ठीक नहीं होंगे तब तक फ्यूचर टैलेंट आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा...(*व्यवधान*) आज मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से इस देश में स्कूल गेम्स का आयोजन सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम ने मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा कर ली है और आने वाले दिनों में व्यापक रूप से पहली बार भारत में स्कूल गेम्स के आयोजन करने का निर्णय किया जा चुका है...(*व्यवधान*) इससे पूरे देश में खेल को ले कर एक अच्छा माहौल बनेगा...(*व्यवधान*) जहां तक तेलंगाना का सवाल है, तो हम ने तेलंगाना को सपोर्ट किया है...(*व्यवधान*) मैंने तेलंगाना राज्य को खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो दिया है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक की जरूरत पड़ती है। In Medak, about Rs. 5.5 crore has already been allocated for the same. About Rs. 7 crore has already been sanctioned for synthetic track in Karimnagar, but the progress is slow. So, I would like to request the hon. Member to pursue and to speed up the matter with the State Government so that they can look for more support in future.

Another synthetic athletic track at Warangal at a cost of Rs. 7 crore has also been sanctioned. Besides that, the Pullela Gopichand Badminton Academy,

located at Hyderabad, has also been funded by the Ministry through Sports Authority of India.

So, we are doing everything to support and we will work together. Hyderabad has also become a very important sports city. So, we will further encourage the same.

(1105/SNB/VB)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

DR. VENKATESH NETHA BORLAKUNTA (PEDDAPALLE): Sir, under Pandit Deen Dayal Upadhyay National Welfare Fund, the sportspersons are getting a monthly pension of Rs. 8000. Most of the sportspersons in India are leading a very miserable and pathetic life because this amount of pension is not at all sufficient to meet the minimum necessities of life ...(*Interruptions*)

Sir, I would like to know from the hon. Minister if the Government is going to enhance this amount of pension for the sports persons. Does the Government have any proposal to increase this monthly pension of Rs. 8000 for the sportspersons? ...(*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJJU: Sir, last year only the pension for athletes who represented India in Olympics and World Championships has been enhanced as provided for in the rules. ...(*Interruptions*) Further, if there are any important issues relating to the welfare of the former athletes, the Government is always ready to support them under the Deen Dayal Upadhyay Special Scheme which we have for the former athletes. Enough support is already being given. If specific cases are brought to our notice, we will personally take care of the interests of those athletes. ...(*Interruptions*)

SHRI DAYAKAR PASUNOORI (WARANGAL): Hon. Speaker, Sir, the hon. Minister may kindly state whether the Government is providing financial assistance to sportspersons and details of such assistance for the last five years. What are the steps being taken to increase financial assistance to national and international sportspersons and also steps taken to attract sportspersons by providing incentives in keeping with the needs of the present times? ...(*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJJU: Sir, we definitely provide assistance to all the sportspersons through Sports Federations. Government of India has a

comprehensive policy to support sporting activities and the sportspersons. All Olympic sports, including some of which are recognised by the Government are being given sufficient financial support. ...(*Interruptions*)

सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जो टॉप स्कीम है, उसमें टारगेट ओलम्पिक पोडियम के तहत, जो स्पेशियलाइज्ड एथलिट्स हैं, जिनको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं और जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके आने-जाने के खर्च से लेकर एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर के अनुसार व्यापक रूप से सरकार सपोर्ट देती है।...(*व्यवधान*) इसलिए सारे फेडरेशंस भी सरकार से खुश हैं।...(*व्यवधान*) जिस तरह से हम खेल और खिलाड़ियों के लिए सपोर्ट दे रहे हैं, उससे इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन भी संतुष्ट है।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, एक मिनट बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सेशन और इस सेशन को मिलाकर मुझे आपने पहली बार सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Belated Happy Birthday to Hon'ble Sports Minister, Mr. Rijju.

(1110/PC/RU)

महोदय, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। ...(*व्यवधान*) आपके प्रेडिसेसर, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, मेरे दोस्त ने 'खेलो इंडिया' के माध्यम से स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। ...(*व्यवधान*)

महोदय, मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि इस साल 'खेलो इंडिया' का कितना बजट है? ...(*व्यवधान*) 'खेलो इंडिया' में जो टीम चुनी जाती है, क्या उस टीम सलेक्शन का कोई क्रायटेरिया आपने फिक्स किया है? ...(*व्यवधान*) टीम गलत ढंग से चुनी जाती है। ...(*व्यवधान*) उसमें बहुत धांधली होती है। ...(*व्यवधान*) इसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। ...(*व्यवधान*) क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने टीम सलेक्शन का कोई क्रायटेरिया फिक्स किया है? धन्यवाद। ...(*व्यवधान*)

श्री किरन रिजिजू : सर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है। ...(*व्यवधान*) 'खेलो इंडिया' का हमारा अलग से 500 करोड़ रुपये का बजट इस बार का बना हुआ है। ...(*व्यवधान*) इससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट उन्होंने सलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूछा है। ...(*व्यवधान*) अगर खिलाड़ियों का सलेक्शन सही नहीं होगा तो फिर खेल क्षेत्र में अच्छा माहौल भी नहीं बनेगा। ...(*व्यवधान*)

सर, इस वक्त हम लोगों ने खेल मंत्रालय के माध्यम से सारे फेडरेशन्स से कहा है कि सलेक्शन प्रोसेस साफ होना चाहिए, सही तरह से होना चाहिए, नियम के तहत होना चाहिए। ...(*व्यवधान*) इसलिए, इस वक्त किसी भी खिलाड़ी का चयन, चाहे वह 'खेलो इंडिया' के गेम्स के लिए हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चैंपियनशिप्स होती हैं, उनके लिए हो, सलेक्शन प्रोसेस बिलकुल ट्रांसपेरेंट है। ...(*व्यवधान*) इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। ...(*व्यवधान*) अगर ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास आती है तो हमने फेडरेशन से कहा है कि हम कार्रवाई भी करेंगे। ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : श्री एम. के. राघवना।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री बैन्नी बेहनना

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापना

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, देश के खिलाड़ी और युवाओं जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। मैं आपको हमेशा बोलने का मौका देता हूँ। देश के नौजवान खिलाड़ियों जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में आप वेल में आकर जिंदाबाद, मुर्दाबाद कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सदन की अच्छी प्रक्रिया नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह गलत है।

...(व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से फिर आपसे आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ कि इस सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। कभी भी वेल में खड़े होकर आसन से बातचीत नहीं करें। अगर आपने यह नहीं पढ़ा हो, यह नियम-प्रक्रिया आपने बनाई है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह अच्छी बात नहीं है, गलत बात है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सब अपनी सीट पर जाएं। मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

1113 hours

(At this stage, Shri Hibi Eden and some other hon. Members went back to their seats.)

माननीय अध्यक्ष : प्रथापन जी, आप अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण काल होता है। यह सभी सदस्यों का, सदन का महत्वपूर्ण प्रश्नकाल माना जाता है। मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव पर अभी कोई व्यवस्था नहीं दी है। आपको स्थगन प्रस्ताव पर मैं व्यवस्था दूँ, तब आपको वेल में आना चाहिए। यह संसद की परंपरा है।

आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप सीनियर सदस्य हैं। मैं नया सदस्य हूँ। मैं इस सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना चाहता हूँ। मैंने हर विषय पर संसद में हमेशा डिबेट और चर्चा करने का आप लोगों से आग्रहपूर्वक कहा कि मैं मौका दूँगा। मैं अगर आपको स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देता, तब आप वेल में आते। यह न्यायोचित बात है या नहीं है? मैंने आपको व्यवस्था नहीं दी, मैंने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय नहीं किया, परंतु आप वेल में आ गए। फिर वेल में आकर आप आसन से चर्चा कर रहे हैं।

आप सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वेल में आकर आसन से चर्चा न करें। यह परंपरा रही होगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिये। मैं पूरी बात कह दूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वर्ष 1952 से लेकर अभी तक परंपरा रही होगी। इस सदन में वेल में खड़ा होकर कोई माननीय सदस्य आसन से चर्चा न करे। यह मेरा आपसे आग्रह है। अगर सदन की इस पर सहमति है तो सहमति दे और सदन कहता है कि नहीं, हम वॉक-आउट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।

(1115/KDS/NKL)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, जब आप चेयर पर बैठे हैं तो आप नए-पुराने नहीं हैं। आप हमारे स्पीकर हैं। आपने खुद इस चेयर पर बैठते हुए यह माना था कि हमें विपक्ष पूरा सहयोग करेगा, इसलिए मैं सदन को प्रोडक्टिव बनाना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: मैं अभी भी यह बात कह रहा हूँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, इसका मतलब यह है कि हम बराबर आपको समर्थन और सहयोग करते हैं। अभी बात यह है कि ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है, जहां देश का बड़ा हित सम्मिलित हो जाता है। सर, हमने आपको एडजर्नमेंट मोशन क्यों दिया? इसका कारण यह है कि यह इतना गंभीर मुद्दा है कि इसके लिए हमें मजबूरन स्थगन प्रस्ताव देना पड़ा। हमें मजबूरन इसके लिए जाना पड़ा। सर, आपका अपमान करने के लिए, आपको छोटा करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूरन हमें जाना पड़ा, क्योंकि देश लूटा जा रहा है। ... (व्यवधान)। इलेक्टोरल बाँड में देश लूटा जा रहा है। यह एक बड़ा घोटाला है। इस घोटाले को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है।

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन जी, एक मिनट। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। श्री संजय जायसवाल जी, नहीं। आप पहले इनको पूरा विषय बोलने दीजिए। मैं आपको प्रश्नकाल के पश्चात समय दूंगा। पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, एक मिनट, मैं कोई उल्टी-सीधी बात नहीं करने वाला हूँ। मैं जोशी जी को और जायसवाल जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि टू जी घोटाले को लेकर, कोयला घोटाले को लेकर, कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर यहां बैठ-बैठकर आप लोग क्या करते थे? इस सदन को कितने दिनों तक बंद किया था? कितनी बार वॉक आउट किया था? अभी आप लोग ज्ञान दे रहे हैं। ... (व्यवधान)। हमने तो कुछ नहीं किया। हम जवाब मांग रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): उस समय घोटाला हुआ था। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री जी के अलावा कोई नहीं बोलेगा। श्री मेघवाल जी, आपको मैंने अलाउ नहीं किया है। कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हों तो आप सदन में बीच में ऐसे मत उठिए। संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया बताएं।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): माननीय अध्यक्ष जी, जब से आप यह पद संभाल रहे हैं, तब से चेयर के नाते आप सबको मौका दे रहे हैं। आपने आज तक कितना जीरो ऑवर लिया है, वह इतिहास बन गया है। आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी इनको उठाना है, 'जीरो ऑवर' में उठाने दें। अधीर रंजन जी, एक मिनट। आप डेली एक एडजर्नमेंट मोशन देते हैं और यह वेल में आकर कह रहे हैं ... (व्यवधान)। अधीर रंजन जी, मैंने आपको सुना। Did I not listen to you? Please listen to me. ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सुरेश जी, आप कृपया बैठ जाइए। आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री प्रहलाद जोशी: यह कह रहे हैं कि हम उस समय बहुत बार वेल में आए। उस समय सी.ए.जी. रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दखल के कारण हम उन मुद्दों पर वेल में आए थे। इस समय तो भ्रष्टाचार

का एक भी मुद्दा नहीं है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ किसी ने भी उंगली नहीं उठाई है। इनको जो भी मुद्दा उठाना है, उसे 'जीरो ऑवर' में उठाएं। हम इसके लिए सहमत हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): जोशी जी, मैंने आपसे दरखास्त नहीं की थी, बल्कि स्पीकर साहब से दरखास्त की थी कि हमारा 'स्थगन प्रस्ताव' है। कृपया हमें बोलने का मौका दें।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल के बाद मैं यह व्यवस्था कर रहा हूँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): जोशी जी, आप कठोर हो सकते हैं, लेकिन हमारे स्पीकर साहब कठोर नहीं, नरम हैं। ... (व्यवधान)। इसलिए मैं स्पीकर सर से यह इजाजत चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 62- श्री डीन कुरियाकोसा सभी माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट से बोलें। मेरा सदन में यह आग्रह है कि माननीय मंत्री जी भी अपनी सीट से बोलें, क्योंकि स्क्रीन पर नाम आता है। श्याम जी, आप 'शून्य काल' में बोल दीजिएगा। आपका जवाब हो गया है। श्याम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अलाओ कर दिया गया है, प्लीज।

माननीय सदस्य, आप कृपया बोलिए। क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? We have taken up the next question – Question No. 62.

(1120/MM/SRG)

(Q. 62)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): As far as Mullaperiyar dam is concerned, safety is the ultimate issue. We have passed Dam Safety Bill during the last Session and I also took part in that discussion. Thirty-six dam failure cases have been reported in our country. Every man-made structure has its own life span. Nineteen year old Tiware dam has been destroyed in the last flood. So many people have lost their lives. The worst dam failure was reported from Gujarat in 1979. Two thousand people have lost their lives. As per the Supreme Court verdict, a Supervisory Committee has been constituted, headed by the Chief Engineer (Dam Safety), Central Water Commission, to oversee the safety issues of Mullaperiyar. In my understanding, the Committee is not at all working properly towards maintaining the safety. My question is whether the Government has any effective full-fledged mechanism for day-to-day monitoring to ensure the safety of the people.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है कि देश में अब तक 36 बांध टूटने की घटनाएं रजिस्टर हुई हैं। यह सर्वथा सत्य भी है और इसी दृष्टिकोण से मैं सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बांध की सुरक्षा के बिल को सर्वसम्मति से पारित किया था। जहां तक मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा का प्रश्न है, यह प्रश्न पिछले चार दशक से देश के सामने खड़ा है। विभिन्न प्रकरणों और वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इसके अधीन व्यवस्था दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के तहत जो कमेटीज़ बनी हैं, उन्होंने अनेक अवसरों पर जाकर इस बांध की सुरक्षा का जायजा लिया है, सुरक्षा के हालात का जायजा लिया है। जिस सुपरवाइज़री कमेटी की मीटिंग के बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उस सुपरवाइज़री कमेटी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत प्री-मानसून और पोस्ट मानसून, दो बार बांध की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययन करना, ऐसा निर्देशित है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि सुपरवाइज़री कमेटी के चेयरमैन सीडब्ल्यूसी के चीफ इंजीनियर होते हैं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि उसका चेयरमैन सीडब्ल्यूसी का चेयरमैन होता है और चेयरमैन उस कमेटी का सीडब्ल्यूसी का चीफ इंजीनियर है, साथ में दोनों राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वॉटर रिसोर्सेस जो सदस्य हैं, वह तमिलनाडु और केरल के हैं। इसी वर्ष 4 जून को तीनों ने जाकर बांध की सुरक्षा के सामान्य हालात का जायजा भी लिया है और साथ में बैठक भी की है। इससे पूर्व में जो कमेटी बनायी गयी थी, उस कमेटी ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया था कि बांध सुरक्षा के सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तरह के लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और अर्जेंट, ऐसे तीन तरह के मैज़र्स इस बांध की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित

किए थे जो अर्जेंट नेचर के थे, उनको पूरा किया जा चुका है। मीडियम टर्म के भी पूरे किए जा चुके हैं। लॉन्ग टर्म के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर मैजर्स लिए जाने थे, उसमें से बांध के ऊपर दस मीटर तक की थिकनेस की कंक्रीट की एक लाइन डालने का विषय था, वह भी समाप्त हो चुका है। केवलमात्र लांग टर्म मैजर्स हैं, उसमें बेबी डैम साइड में बना हुआ है, उसकी स्ट्रैन्थनिंग के लिए आवश्यकता थी, वह काम अभी शेष है और उसके लिए केरल की सरकार का सहयोग अपेक्षित है। केरल की सरकार अगर सहयोग करेगी तो निश्चित रूप से समयवधि में उसको भी पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और सदस्यों को आगाह करना चाहता हूँ कि इस बांध की सुरक्षा को लेकर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बांध में इलेक्ट्रिसिटी का पावर कनेक्शन भी आज तक नहीं हुआ है। केरल सरकार से मेरा इस सदन के माध्यम से आग्रह रहेगा और मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि बांध तमिलनाडु की सम्पत्ति होने के अतिरिक्त इसके नीचे डाउन स्ट्रीम में जो तीन बांध बने हुए हैं, उसके साथ-साथ बहुत बड़े जनमानस पर भी प्रभाव इसके कारण से हो सकता है।

(1125/GG/RP)

इसलिए उसकी प्राथमिकता को देखते हुए, उसकी अर्जेंसी को देखते हुए, बचे हुए मेजर्स में केरल सरकार का जो सहयोग अपेक्षित है, उस पर जाने के लिए जो रास्ता है, वह रास्ता फॉरेस्ट एरिया से जाता है, वह भी आज तक ठीक से रास्ता नहीं मिला है। वह सब दिलाने में सहयोग करेंगे, ऐसा मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने आपको एलाऊ तो नहीं किया है न? अभी इनका उनका सप्लिमेंट्री है। ... (व्यवधान)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, if anything happened to that dam, surely, we can say that Kerala will be divided into two parts. Lakhs and lakhs of people will be the victims. Already, there are so many reports, including the report of IIT Roorkee, saying that the dam is situated in an earthquake zone. That means, if an earthquake of the magnitude of 6 and above on the Richter scale occurs, the dam cannot sustain. That is the report. In this context, there are so many recommendations from the Central Water Commission from 1980. I would like to know as to why the supervisory committee has not implemented the procedures recommended by the Central Water Commission.

As far as installation of dam instrumentation equipment for safety is concerned, I would like to know whether the Government has any plan to install a highly sensitive oscillograph to assess the impact of earthquake.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि यह विवाद पिछले चार दशकों से चल रहा है। जैसा मैंने अभी विस्तार से निवेदन किया ... (व्यवधान) सदन को आपके माध्यम से कि इसमें तीन स्तरीय मेजर्स लेने की जो प्रस्तावना की गई थी, उनमें दो स्तर पर जो मेजर्स लिए जाने थे, वे

पूरे हो चुके हैं। तीसरे स्तर पर जो मेज़र्स लिए जाने हैं, उसमें जो काम बाकी है, उसमें केरल सरकार का सहयोग अपेक्षित है। लेकिन साथ ही साथ माननीय सदस्य ने जो हाई सीसमिक जोन की चर्चा की है, उसके बारे में सेंट्रल वॉटर कमीशन के चेयरमैन की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, उस समिति ने और इससे पहले पिछले वर्ष जब बाढ़ की स्थिति आई थी, जब इस बांध का मानक जल स्तर, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित 142 फीट का है, उससे ऊपर जब जाने लगा था, उस समय जो चर्चा हुई थी, उसके आधार पर दोनों ही कमेटीज़ ने टैक्नीकल सर्वे में इस बांध को सीसमिक थ्रेट्स के हिसाब से भी सर्वाधिक, सर्वथा, सुरक्षित पाया गया है।

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Sir, I would like to know whether the Government of India has noticed that the new dam in Mullaperiyar, proposed by Kerala, is essential keeping in view the safety and security of people living in the command area of the dam. I would also like to know whether the Government has taken any measure for the safety inspection of the existing Mullaperiyar dam.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: महोदय, मुझे लगता है कि उसी प्रश्न को माननीय सदस्य ने पूछा है। मैंने इससे पहले उत्तर में कहा है कि उसके बारे में अनेक स्तरों पर, अनेक बार चर्चा हुई है। जहां तक नए बांध का प्रश्न है, इस बांध की सुरक्षा को ले कर, यह कि अभी तक इस बांध की सुरक्षा को खतरा हो और इसको नया बनाया जाए, ऐसा केरल राज्य का एप्रिहेन्शन है। इस तरह का कोई भी प्रकरण भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। लेकिन सरकार के दूसरे मंत्रालय – वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में केरल सरकार के प्रतिवेदन पर, उन्होंने उसे टर्म ऑफ रेफ़रेंस जारी करते हुए, ईआईए और एन्वायरमेंट असेसमेंट प्लान और एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन उस स्वीकृति के आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि उस स्वीकृति के बाद तमिलनाडु राज्य, क्योंकि यह इंटर-स्टेट बेसिन पर बना हुआ है। तमिलनाडु के स्वामित्व का बांध है। ...(व्यवधान) इसलिए उसके लिए एन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए दोनों राज्यों की सहमति आवश्यक है। ...(व्यवधान)

(1130/RCP/KN)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, I am happy to hear from the hon. Minister that the Mullaiperiyar Dam is very safe. ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके सहयोगी दल के सदस्य हैं। आपने पहले बालू जी को बोलने नहीं दिया। अब इनको बोलने नहीं दे रहे। यह क्या है?

...(व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, my specific question is this. I do not know how the Government is functioning. The Minister of Jal Shakti is very categorical before the House that the dam is safe. ...(Interruptions) As per the report, as per the assessment that has been done by various Commissions, which the

Supreme Court was seized of, the Minister is categorical that the dam is in safe condition. Now, what is incumbent upon the Government? See, you are running Jal Shakti Ministry. There is another Minister for the Ministry of Environment and Forests. But we are under one umbrella in the Government. When the hon. Minister is saying that the dam is in safe hands, what prompted the Environment Ministry to have a pre-feasibility study and why did they approve the terms of reference to construct a new dam in the same place? I do not know why the two Ministries are going in opposite directions within the Government. Let me be apprised regarding this.

माननीय अध्यक्ष : माननीय अधीर रंजन जी, आप अपने माननीय सदस्यों को समझाएं कि जिन्होंने प्रश्न काल के दौरान दो प्रश्न पूछ लिए, वे भी खड़े होते हैं। उनको आप ट्रेनिंग दीजिए। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि यह इंटरस्टेट बेसिन नहीं है। इसका बहुत छोटा सा बेसिन तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है इसलिए इंटरस्टेट बेसिन की डेफिनेशन की यदि आप बात करें तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ...(व्यवधान)

I am replying to your question. I am coming to your question, Sir. Please allow me to speak. ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप उत्तर देने दें।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, जब सुप्रीम कोर्ट में यह वाद विचाराधीन था और उसके बाद में जब कमेटी बनी थी, उसने तीन मेजर्स जो अर्जेंट नेचर के मेजर्स, मीडियम टर्म और लॉग टर्म मेजर्स की बात की थी, उन मेजर्स के साथ-साथ में उनकी जो प्रस्तावना थी, उसमें उन्होंने इस बात के लिए भी कहा था कि ऐसा अल्टरनेटिव डैम बनाए जाने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। केरल सरकार ने सीधे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को इसके बारे में प्रतिवेदित किया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने उसमें इस बात का उल्लेख करते हुए कि दोनों राज्यों की सहमति होगी तभी EC जारी की जाएगी। लेकिन यदि इसके बारे में कोई सम्भावना तलाश करनी है तो तलाश की जा सकती है। क्योंकि जहां तक जल संसाधन का प्रश्न है, जल का विषय है, यह क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर राज्यों का विषय है, इसलिए कोई भी राज्य अपने जल संसाधनों के निर्माण और उसके लिए भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय से बात करने के लिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, while providing full water supply to Tamil Nadu, our concern is about addressing safety issues of Kerala. If anything happens to Mullaiperiyar Dam, 35 lakh Keralites will be killed and four districts namely Alappuzha, Kochi, Idukki and Kottayam will be washed out. Only for that reason, we have requested for construction of a new dam near the

present Mullaiperiyar Dam. So, I would like to know whether the Central Government will allow us to construct a new dam near the present dam.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी विस्तार से इस बात का उत्तर दिया है कि अभी तक केरल की सरकार ने जो प्रतिवेदन दिया था, उस पर एमओईएफ ने उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किया है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी करने के बाद में दोनों स्टेट अगर सहमति बनाकर नया डैम बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसमें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होगी।

(ends)

(Q. 63)

SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANNORKAR (CHANDRAPUR): Thank you, Speaker, Sir. As we are all very well aware that water problem in India is growing day by day. Earlier this year, another city ran out of water.

This time, it was Chennai, a metropolitan city in South India, that is home to over ten million people. The city has been dependent on monsoon showers to fill up its reservoirs, which is a primary bank to supply water to the ever-burgeoning population.

(1135/SMN/CS)

However, Chennai is not the only dry city in India. India's business capital – Mumbai and information technology capitals - Bengaluru and Hyderabad, which houses the new Amazon India headquarters, are suffering from water scarcity.

Unfortunately, the dire situation is not isolated to urban centres. India's rural communities are also suffering from an acute water shortage that has had a severe impact on the country's crops so much so that the leading cause for farmers suicides in India's agrarian states has been a lack of access to water for agriculture.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न काल में प्रश्न संक्षिप्त में पूछा जाता है। सभी माननीय सदस्य अधिकतम प्रश्न उठा सकें, इसलिए मैंने आप सभी से संक्षेप में प्रश्न पूछने का आग्रह किया था और अब फिर इसके लिए आग्रह कर रहा हूँ।

SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANORKAR (CHANDRAPUR): Therefore, my first question to the hon. Minister is this.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कुछ विषय दूसरे सप्लीमेन्टरी प्रश्न में पूछ लेना।

SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANORKAR (CHANDRAPUR): In Chandrapur and in Yavatmal districts, there are many river interlinking irrigation projects like lower Painganga project, Ghosikhurd irrigation projects, Wadner irrigation project etc. which are pending for a long time.

माननीय अध्यक्ष : आप जो लिखकर लाए हैं, वह पूरा विषय पूछेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि प्रश्न काल में केवल संक्षिप्त प्रश्न पूछें।

SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANORKAR (CHANDRAPUR): Why are these irrigation projects so delayed to get complete? How much time will it take to complete these projects?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मुझे लगता है कि मूल प्रश्न से उसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि आप संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिन लिंक्स की बात माननीय सदस्य ने की है, उसके अतिरिक्त भी महाराष्ट्र सरकार को सिंचाई के लिए 40 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता विभिन्न मदों में दी गई है।

SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANORKAR (CHANDRAPUR): My second supplementary question is whether the Government is working on desalination of sea water for the irrigation purpose and other necessities. If yes, please share the details. Why is the Government not planning to build barrages on rivers so that the stored water could be used for irrigation and for drinking purposes?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदय, मैं छोटा सा परिप्रेक्ष्य आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूँ। चार हजार बिलियन क्यूबिक मीटर पानी देश में हर साल बर्फ और बारिश के माध्यम के रूप में हमारे यहाँ पर आता है। इस चार हजार बिलियन क्यूबिक मीटर पानी में जो इंटरनेशनल रिवर्स हैं, जो इंटरनेशनल बेसिन से पानी आता है, वह भी सम्मिलित है। इसमें से लगभग दो हजार बिलियन क्यूबिक मीटर पानी संचय, संरक्षण और उपभोग के योग्य है। उस दो हजार बिलियन क्यूबिक मीटर पानी में से 40 प्रतिशत पानी नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन में है, जहाँ सिंचाई का स्कोप नहीं है। यह सही है कि अभी भी देश के लगभग-लगभग 17-18 प्रतिशत हिस्से में हर साल बाढ़ आती है और लगभग 12-13 प्रतिशत हिस्से में हर साल सूखा पड़ता है। देश की सरकार ने इसी के दृष्टिकोण से इंटरलिंगेज ऑफ रिवर्स का एक मॉडल तैयार किया है। मैं इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में आपके माध्यम से सदन और सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सब जिन-जिन राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ बैठकर एक मोटी-मोटी सहमति इस पर बनाएं। हमें खुले हृदय से बात करके एक मोटी सहमति बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। यदि हम सब लोग इस दिशा में काम करते हैं और ऐसी सहमति अपने-अपने राज्यों के बीच में बना पाएंगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में हम देश को जल के रूप से सुरक्षित कर सकते हैं।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि डीसैलिनेशन के माध्यम से आज दुनिया में समुद्र के पानी को पीने के पानी के उपयोग में लेने के बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे देश में भी इस दिशा में काम हो रहा है। स्टेट ऑफ गुजरात में, स्टेट ऑफ तमिलनाडु में और कुछ केन्द्र शासित प्रदेशों में इसमें उल्लेखनीय काम हुआ है। आने वाले समय में चेन्नई सिटी, जिसके बारे में पिछले प्रश्न के समय में चर्चा की गई थी, का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा, जो पीने के पानी का शेयर है, वह डीसैलिनेशन से होगा। दुनिया में केवल इजराइल और एकाध देश ऐसे हैं, जहाँ खेती, एग्रीकल्चर परपज के लिए डीसैलिनेशन के पानी उपयोग हो रहा है। जहाँ तक भारत का परिप्रेक्ष्य है, हमें प्रकृति ने इतने संसाधन

दिए हैं, यदि हम इस सप्लाई साइड मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम रोज बात करते हैं, उसके साथ-साथ डिमांड साइड मैनेजमेंट के ऊपर भी चर्चा करें, आज दुनिया का सबसे अनप्रोडक्टिव वाटर, सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव पानी कोई है, तो वह भारत का पानी है। यदि हम सब मिलकर के अपने क्षेत्र में सिंचाई के पानी का अधिकतम उपयोग और अधिकतम विवेकपूर्ण उपयोग किस तरह हो सकता है, यदि इस पर बात करेंगे और यदि हम 10 प्रतिशत पानी भी सिंचाई में कम कर पाते हैं, सिंचाई के उपयोग में कम कर पाते हैं, तो आने वाले 50 सालों तक देश को पीने के पानी के रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है।

(1140/RV/MMN)

माननीय अध्यक्ष: श्री के. नवसकनी - उपस्थित नहीं।

श्रीमती हेमा मालिनी।

SHRIMATI HEMA MALINI (MATHURA): Thank you very much, Speaker Sir.

According to a recent study by the NITI Aayog, nearly 600 million Indians face 'high to extreme' water stress, with about two lakh people dying each year because of inadequate access to safe water. This is high time that 'right to water' should be made as a fundamental right in the country. My question to the Minister is this. Is there any proposal for guaranteeing right to water to the people of the country either through the Constitution or through making legal provisions?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार या संसद में विचाराधीन नहीं है। लेकिन, इसके साथ ही साथ मैं सदन की जानकारी के लिए उल्लेख करना चाहता हूँ कि आज देश में लगभग 18 प्रतिशत ग्रामीण आवास, लगभग 18 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण आवास ऐसे आकलित किए गए हैं, जिनमें से केवल तीन करोड़ से कुछ अधिक आवास ऐसे हैं, जिनके घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचता है। 15 करोड़ आवासों तक नल के माध्यम से पीने का पानी पहुंचे, इसकी घोषणा हमारे प्रधान मंत्री जी ने की है और सवा तीन लाख करोड़ रुपये के बजटरी एलोकेशन के माध्यम से प्रत्येक आवास तक, प्रत्येक घर तक पीने का जल पहुंचे, इसके लिए देश और राज्यों की सरकारें और हम सब लोग संकल्पबद्ध और कटिबद्ध हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इस विषय पर बी.ए.सी. के अन्दर चर्चा हुई थी और मुझे लगता है कि इसके ऊपर सबकी आम सहमति बन रही है। इस विषय पर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, in the last Session you promised us that we would have an elaborate discussion. ...(*Interruptions*) I am requesting you to make sure that we take up this in this Session.

HON. SPEAKER: Okay.

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): I thank the Minister for giving a detailed answer.

In the reply, it has been given that Feasibility Report on the Pamba-Achankovil-Vaippar link has been completed. This Feasibility Report has been pending for many years. Will we move to the next stage from that? Or, is there any other thing that we will be doing? It is because the southern Tamil Nadu districts, namely, Virudhunagar and Ramnad districts, will be having water problem. Therefore, I would like to ask the Minister that what step the Government of India has taken in this regard. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: यह भारत की विशेषता है - एक दल, अलग-अलग राज्य और अपना-अपना मता
...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, हालांकि मैंने पहले प्रश्न के जवाब में कहा था कि मैंने सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया था कि विभिन्न राज्यों और विभिन्न दलों के सारे सदस्य साथ बैठ कर अपने-अपने राज्यों में इस तरह की सहमति बनाने की दिशा में काम करें।

माननीय सदस्य ने जिस वर्तमान लिंक की चर्चा की है तो यह लिंक महानदी से लेकर कावेरी तक जो पूरा एक लिंक सिस्टम है, उस सिस्टम का पार्ट है। जिस पार्टीक्युलर लिंक की इन्होंने चर्चा की है, इसके ऊपर की सारी लिंक्स के बनने पर ही इसकी हाइड्रोलॉजी एन्शोर हो पाएगी। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम शीघ्र ही इस दिशा में कुछ निर्णय ले पाएंगे, ताकि हम इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकें।

(इति)

(प्रश्न 64)

श्री अरुण साव (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए उन्होंने लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की एक बहुत बड़ी राशि उपलब्ध कराई है।

बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण लगभग चार वर्षों से चल रहा है। मुझे लगता है कि उसकी गति धीमी है। इसमें लम्बा समय हो गया है। लोग परेशान हो रहे हैं। इसी तरह से, बिलासपुर-रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कब तक पूर्ण हो जाएगा?

(1145/MY/VR)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी): आदरणीय स्पीकर महोदय, इन दोनों कामों में कुछ अड़चनें आई थी। इनमें कॉन्ट्रैक्टर्स के तरफ से भी प्रॉब्लम्स थे, लैंड एक्विजिशन का भी प्रॉब्लम था और प्रोजेक्ट भी डिले हुआ है। अभी मेरे साथ इन दोनों प्रोजेक्ट्स की रिव्यू मीटिंग हुई है। इसी बीच में आठ दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री भी मुझसे मिले थे और इस विषय पर चर्चा हुई है। कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेसमेंट करके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से काम कराने के प्रपोजल पर भी काम हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले एक साल के अंदर ये दोनों प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे।

श्री अरुण साव (बिलासपुर): राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130ए बिलासपुर से मुंगेली तक स्वीकृत है। केन्द्र सरकार के पास मुंगेली से पोड़ी तक स्वीकृति का प्रस्ताव लंबित है। यह कब तक अच्छी तरह से स्वीकृत हो जाएगी? बिलासपुर, कटघोरा और चापा राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत अत्यंत खराब है। 80 किलोमीटर सफर करने में लगभग चार घंटे का समय लग रहा है। इससे लोग परेशान हैं। इन मार्गों का निर्माण कब तक हो जाएगा?

श्री नितिन जयराम गडकरी: स्पीकर महोदय, छत्तीसगढ़ में करीब 800 किलोमीटर एन.एच. का जो काम है, उसका डी.पी.आर. बन रहा है। इसके साथ-साथ जिन दो मार्गों का उल्लेख अभी किया गया था, उनमें से इसका डी.पी.आर. भी रेडी हुआ है और एस्टिमेट भी प्रिपेयर्ड हुआ है। यह स्टेट पी.डब्ल्यू.डी. डी की तरफ से है। इनका जो अवार्ड सैंक्शन करना है, वह वर्ष 2019 के बीच में हो जाएगा।

श्री दीपक बैज (बस्तर): अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे संसदीय क्षेत्र बस्तर से राजधानी रायपुर तक 300 किलोमीटर का रास्ता है और यह एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहां एक ही सड़क मार्ग है, जो पिछले तीन वर्षों से बन रही है। कांकेर से लगभग 45 किलोमीटर तक का काम कछुआ की गति से चल रहा है और मार्ग की हालत बहुत ही जर्जर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि उक्त सड़क कब तक पूर्ण होगी और आप कब तक इसे बना कर देंगे? क्योंकि वहां कई जगहों पर दिक्कत हो रही है। मैं चाहूंगा कि

माननीय मंत्री जी इस पर जवाब दें। महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि उक्त सड़क को इस गर्मी तक दो से तीन महीने में कंप्लीट किया जाए।

श्री नितिन जयराम गडकरी: स्पीकर महोदय, यह सच्चाई है कि इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं सम्माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि बस्तर के बाद कई अनेक जगहों पर फॉरेस्ट की प्रॉब्लम आती है। जो फॉरेस्ट क्लीयरेंस है, वह नहीं मिल पाती है। पेड़ काटने की परमिशन के बारे में हम रुक जाते हैं। बहुत सी जगहों पर लैंड एक्विजिशन के कारण भी प्रॉब्लम आती है। जब तक काम ठप हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को बैंक फाइनेंस करना बंद कर देता है। स्टेट के सभी प्रोजेक्ट्स का रिव्यू मैंने खुद किया है। वहां मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। उसमें जो प्रॉब्लम्स थे, उनमें राज्य सरकार के सहयोग से हम लोगों ने मार्ग निकाला है। इसका काम जल्द ही शुरू होगा और तेज गति से इसका काम पूरा होगा, यह विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह पश्चिम बंगाल और केरल का विषय नहीं है। यह प्रश्न केवल छत्तीसगढ़ से संबंधित है, इसलिए मैंने माननीय सदस्य से आग्रह किया है।

(इति)

(प्रश्न 65)

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): अध्यक्ष महोदय, पटना में मेट्रो का निर्माण होना है। पटना मेट्रो के निर्माण के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच त्रिपक्षीय समझौता हो चुका है। उस समझौते के तहत सेन्ट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट के रूप में इसका कार्यान्वयन होना है और कार्यान्वयन करने की जिम्मेवारी पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दी गई है।

महोदय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकार इसमें ज्वाइंट प्रमोटर हैं। अब पांच वर्षों में इस योजना को पूर्ण होना है, लेकिन पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और उनके चार डायरेक्टर का नॉमिनेशन भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय में पेंडिंग है। अगर यह लंबे समय तक पेंडिंग रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रोजेक्ट डिले होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चेयरमैन और चार निदेशकों का जो नॉमिनेशन होना है, आप कब तक उसे पूर्ण करेंगे?

(1150/SAN/CP)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, a project to construct the Patna Metro Rail for 32 kilometres has been approved a few months ago. So, we have, as a part of that, made some money available for some preliminary work to be done, and the nominations of all the people concerned will be done very shortly, but this does not hold up the preliminary work like soil testing and other activities which are being carried out.

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): जब तक पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और डायरेक्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि नेचुरली स्वाभाविक तौर पर जो निर्णय लेना है, वह पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को लेना है। कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उनको दी गई है। यदि उसके चेयरमैन और डायरेक्टर्स के नामिनेशन नहीं होंगे, तो स्वाभाविक तौर पर उसमें विलम्ब होगा।

माननीय मंत्री जी, मेरा सेकेंड सप्लीमेंट्री भी सुन लीजिए, फिर एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत जाइका से 5,520 करोड़ रुपये सॉफ्ट लोन लेने की योजना है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उस लोन के संदर्भ में नीति आयोग से कमेंट्स मांगे हैं, जो महीनों से वहां पेंडिंग है। भारत सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय है, उसका नोडल डिपार्टमेंट है, भारत सरकार इसमें सहभागी है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहते हैं कि इन सभी बिंदुओं पर मानीटरिंग करके आप इसको शीघ्र स्वीकृत कराएं, ताकि योजना के कार्यान्वयन में और शीघ्रता आ सके।

श्री हरदीप सिंह पुरी: सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि जो पटना का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, इसको मैं खुद मानीटर करता हूँ। बाकी सारे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को भी मैं स्वयं मानीटर करता हूँ। यह प्रोजेक्ट इस साल फरवरी में अप्रूव हुआ है। ... (व्यवधान) 32 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मैं राज्य सभा का सदस्य हूँ और that was a slip of the tongue and I acknowledge that. I thank you for pointing out. ...*(Interruptions)*
Okay.

माननीय अध्यक्ष : आप तो जवाब दे दीजिए।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: The work on this Rs. 13,000 crore project has been initiated for which Delhi Metro Rail Corporation is the consultant. The preliminary work is already underway. The topographical survey agencies have been finalised. The work is in progress on both the corridors. Geotechnical investigation works of both the corridors have been awarded and the work is in progress. 50 करोड़ रुपये उनको ऑलरेडी दिए गए हैं और जो नॉमिनेशन्स की आप बात कर रहे हैं, वह एक महीने के अंदर-अंदर हो जाएगा। वे नाम इस समय भी प्रोसेस हो रहे हैं।

जहां तक जाइका का लोन है, वहां डिपार्टमेंट ऑफ इकोनामिक अफेयर्स को यह प्रपोजल ऑलरेडी भेज दिया गया है। They are in touch with the concerned agency which has to finance the project. So, I want to assure the hon. Member that all work is in hand and that even pending the nomination of the Chair and the four Directors, the work has not been held up. Work is underway, both on the North-South and the West-East corridors.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि बिहार में पहली मेट्रो का उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसे 5 साल में वे पूरा करेंगे। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 60 प्रतिशत राशि का जो लोन जाइका से लेना है, वह जापान की कंपनी है। हम नालंदा के सांसद हैं। नालंदा बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़ा हुआ है। काफी पर्यटक, बुद्धिस्ट लोग राजगीर तक आते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस मेट्रो प्रोजेक्ट को नालंदा तक ले जाने का सरकार कोई विचार रखती है?

श्री हरदीप सिंह पुरी: अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ 30 किलोमीटर का पटना में नार्थ-साउथ और वेस्ट-ईस्ट कॉरीडोर का प्रपोजल है। हमारे पास इस समय न कोई प्रपोजल इस मेट्रो को नालंदा ले जाने के लिए आया है और न ही कोई प्रपोजल इस समय कंसीडरेशन में है। (इति)

(1155/NK/RBN)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 66 - डॉ. उमेश जी. जाधव - उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 67 - श्री एम. वी. वी. सत्यनारायण - उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी।

(प्रश्न 68)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है। The deadline for this project has been extended to 2021 and an unprecedented amount of funds have been allocated to this project. बीस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के प्राजेक्ट को एलोकेट कर दिया गया है। वर्ष 2021 तक डेडलाइन थी जो काम 2019 में होना चाहिए था, नमामि गंगे 2019 तक साफ हो जानी चाहिए थी इसे 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या पालिसी और इम्प्लिमेंटेशन सेटबैक रहे हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डिक्लेयर किया है कि उत्तर और बंगाल के स्ट्रेच में गंगा का पानी नहाने तक के लिए उचित और साफ नहीं है। इस पर माननीय मंत्री जी की क्या सफाई है। पीने की बात छोड़िए नहाने तक के लिए यूपी से बंगाल तक गंगा का पानी साफ नहीं है। इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी? इसे आगे कैसे साफ किया जाएगा?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, जहां तक गंगा की शुद्धता का प्रश्न है, निर्मलता और अविरलता का प्रश्न है, उसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। कुल मिलाकर अब तक 305 प्रोजेक्ट गंगा की स्वच्छता को एन्शोर के लिए किए गए हैं। उन 305 प्रोजेक्ट्स में 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। शुरुआत के पहले दो साल इनिशियल डीपीआर बनाने, स्टेट के साथ कन्सलटेशन और जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं उसके बारे में समय लगे थे। पिछले तीन साल में इसके ऊपर तेजी से काम हो रहा है। बीस हजार करोड़ रुपये हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मिले थे उसके अगेंस्ट में हमने अट्टाइस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का काम एलोकेट हो गए हैं।

जहां तक गंगा की निर्मलता का प्रश्न है तो वह निश्चित रूप से अविरलता से जुड़ी हुई है। अविरलता को सुनिश्चित करने के लिए जितने सॉफ्ट मेजर्स हो सकते हैं, गंगा नदी में पानी का प्रवाह बना रहे, उसके लिए हमने ई-नोटिफिकेशन जारी किया है। जहां तक गंगा की स्वच्छता के लिए डेडलाइन की बात है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि गंगा की स्वच्छता एक यक्ष प्रश्न है, यह सदैव रहने वाला प्रश्न है। जब हम नहीं थे, तब भी गंगा थी, हम नहीं होंगे तब भी गंगा रहने वाली है। हमेशा यह प्रश्न बना रहेगा, दुनिया की सबसे लिविंग रिवर है। इसमें लाखों लोग रोज स्नान करते हैं, लाखों लोगों की दैनिक जीवनचर्या इससे जुड़ी हुई है। पिछले प्रश्न के जवाब में मैंने कहा था। गंगा नदी से जुड़े हुए क्षेत्र में जितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं, उसमें हम जल का संचय और उसमें कमी ला सकते हैं, इसको सुनिश्चित करेंगे तो प्रवाह को बढ़ा सकेंगे। अगर प्रवाह बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसकी निर्मलता सुनिश्चित होगी। जहां तक माननीय सदस्य ने नहाने योग्य पानी नहीं होने की चर्चा की है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गंगा के बारे में वर्ष 2014-2019 तक के जो आंकड़े दिए हैं, वह बीओडी, फीकल कोलीफार्म और डिजाल्वड ऑक्सीजन लेवल के आंकड़े हैं। तीनों ही में लगभग हरेक क्षेत्र में स्वच्छता के रूप में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जहां तक फीकल कोलीफार्म विषय को लेकर माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, मैं उसे समझ सकता हूं। जैसा मैंने कहा कि गंगा लिविंग रिवर है, केवल फीकल कोलीफार्म मानव द्वारा उत्सर्जित अशुद्धियों के कारण नहीं होती है। गंगा नदी में पशु स्नान करते हैं, गंगा नदी में

(P.23-30)

पशु रहते हैं, उस क्षेत्र में जो खेती होती है और जो खाद उपयोग होती है वह भी रन ऑफ होकर फीकल कोलीफार्म बढ़ाता है। केवल एक चीज जिसके माध्यम से नदी की शुद्धता को मापा जा सकता है, और जो सबसे साइंटिफिक मीज़र है, वह डिजाल्वड ऑक्सीजन है।

(1200/SK/SM)

डिजॉल्वड ऑक्सीजन के पैरामीटर पर, बाकी सारे पैरामीटर्स, चाहे बीओडी हो या फीकल कॉलीफार्म, दोनों उन के साथ जुड़ा हुआ है। डिजॉल्वड ऑक्सीजन के पैरामीटर पर गंगा उदगम से लेकर लगभग सब जगह मानक से ऊपर है। अभी एक गंगा आमंत्रण अभियान किया है।

मैं माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि गंगा के उद्गम स्थल देवप्रयाग से लेकर बक्खाली बीच तक, जहां गंगा समुद्र में विलीन होती है, हमने एक अभियान किया था। इसमें मंत्रालय के लोग, वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ, आईआईटी के साइंटिस्ट और अन्य विषयों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने नाव के माध्यम से 2600 किलोमीटर की यात्रा की। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, जो यात्रा चार साल पहले की थी, उसके परिप्रेक्ष्य में एक्वाटिक लाइफ में सुधार हुआ है और शुद्धता के मानकों में परिवर्तन हुआ है।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अध्यक्ष जी, 28,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन देश का पाल्युशन बोर्ड भी अभी तक गंगा जी को शुद्ध नहीं मान रहा है।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष: मुझे कुछ विषयों पर स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं दी है।

PAPERS LAID ON THE TABLE

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटि पर रखेजाएंगे।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R. K. SINGH): I beg to lay on the Table-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

1. Memorandum of Understanding between the NHPC Limited and the Ministry of Power for the year 2019-2020.
2. Memorandum of Understanding between the NHDC Limited and the NHPC Limited for the year 2019-2020.
3. Memorandum of Understanding between the Power Grid Corporation of India Limited and the Ministry of Power for the year 2019-2020.
4. Memorandum of Understanding between the THDC India Limited and the Ministry of Power for the year 2019-2020.

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the NTPC Limited, New Delhi, and its subsidiaries for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the NTPC Limited, New Delhi, and its subsidiaries for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (b) (i) Review by the Government of the working of the Power Grid Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

- (ii) Annual Report of the Power Grid Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to lay on the Table-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 14A of the Aircraft Act, 1934:-

1. The Aircraft (First Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.333(E) in Gazette of India dated 4th April, 2018, together with an explanatory note.
2. The Aircraft (Seventh Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1096(E) in Gazette of India dated 9th November, 2018, together with an explanatory note.
3. The Aircraft (Second Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.555(E) in Gazette of India dated 13th June, 2018, together with an explanatory note.

(2) A copy of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.692(E) in Gazette of India dated 26th September, 2019 under sub-section (3) of Section 18 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupant) Act, 1971.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963:-

1. G.S.R.761(E) published in Gazette of India dated 7th October, 2019 approving the Cochin Port Trust (Handling Freight Containers Carrying Dangerous or Hazardous Cargo) Regulations, 2019.

2. G.S.R.778(E) published in Gazette of India dated 14th October, 2019 approving the Cochin Port Trust (Licensing of stevedoring and shore handling) Regulations, 2019.
 - (2) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Cochin Port Trust, Cochin, for the year 2018-2019.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cochin Port Trust, Cochin, for the year 2018-2019.
 - (iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Cochin Port Trust, Cochin, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
 - (iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Cochin Port Trust, Cochin, for the year 2018-2019.
 - (3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2018-2019.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2018-2019.
 - (iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
 - (iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2018-2019.
- (4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Calcutta Dock Labour Board, Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Calcutta Dock Labour Board, Kolkata, for the year 2018-2019.
- (5) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the New Mangalore Port Trust, New Mangalore, for the year 2018-2019.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the New Mangalore Port Trust, New Mangalore, for the year 2018-2019.
- (iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the New Mangalore Port Trust, New Mangalore, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.
- (iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the New Mangalore Port Trust, New Mangalore, for the year 2018-2019.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES (SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI): I beg to lay on the Table copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 9 of the Micro Small Medium Enterprises Development Act, 2006:-

1. S.O.5621(E) published in Gazette of India dated 2nd November, 2018, regarding instructions in respect of buyers who get supplies of goods and services from Micro and Small Enterprises.
2. S.O.5622(E) published in Gazette of India dated 2nd November, 2018, regarding on-boarding of Large Enterprises on TReDS.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

1203 hours

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 19th November, 2019 agreed without any amendment to the Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 2nd August, 2019. ”

PAPERS LAID ON THE TABLE – CONTD.

1204 बजे

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विभाग निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2016-17 और 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2016-17 और 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) National Board for Micro, Small and Medium Enterprises

1204 hours

SHRI NITIN GADKARI: Sir, I beg to move the following:-

“That in pursuance of clause (d) of sub-section (3) and sub-section (4) of Section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder. ”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(ii) National Khadi and Village Industries Board

SHRI NITIN GADKARI: Sir, I beg to move the following:-

“That in pursuance of Section 10 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 read with rules 15 and 17 of Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Khadi and Village Industries Board subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder.”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 15 और 17 के साथ पठित खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्याधीन खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(1205/MK/AK)

विशेष उल्लेख**माननीय अध्यक्ष:** विशेष उल्लेख।

श्री मनीष तिवारी जी

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन का ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग के विरोध के बावजूद इस सरकार ने जो चुनावी बांड, जिसको अंग्रेजी में इलेक्टोरल बांड कहते हैं, वे जब जारी किए गए, उससे सरकारी भ्रष्टाचार के ऊपर एक अमलीजामा चढ़ गया है। ... (व्यवधान) मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, वर्ष 2017 से पहले इस देश में एक मूलभूत ढांचा था और उस मूलभूत ढांचे के तहत जो धन-पशु हैं, जो धनी लोग हैं, उनका भारत की सियासत में पैसे का हस्तक्षेप था उसके ऊपर नियंत्रण था। परन्तु, 1 फरवरी, 2017 को आम बजट में इस सरकार ने यह प्रावधान किया कि अज्ञात इलेक्टोरल बांड जारी किए जाएं, जिसके न डोनर का पता है, न जितना पैसा दिया गया उसकी कोई जानकारी है और जिसको दिया गया है उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। ... (व्यवधान) इससे सरकारी भ्रष्टाचार के ऊपर अमलीजामा चढ़ाया गया है। मैं आपको बहुत गंभीरता से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि जब पहले यह स्कीम लागू की गई थी तो यह स्कीम सिर्फ लोक सभा के आम चुनाव तक सीमित थी। पर, यह विडम्बना की बात है कि 11 अप्रैल, 2018 को कर्नाटक के चुनाव के ठीक पहले ... (Not recorded)... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इस तरह से नाम नहीं लें।

... (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष जी, मैं कागज पटल पर रख सकता हूँ। ... (व्यवधान)**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, बिना किसी दस्तावेज, बिना सबूत के नाम न लें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सदन के पटल पर रख दीजिएगा। मैं डिस्कस करके जवाब दूंगा।

... (व्यवधान)

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज जिसकी आबादी लगभग 26 लाख है। यहां से कोई भी ट्रेन दिल्ली या अन्य महानगरों के लिए नहीं है। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान गोपालगंज के थावे जंक्शन स्टेशन पर पिट लाइन के निर्माण हेतु आकर्षित करना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) विदित हो कि यहां पर इलेक्ट्रिकेशन का काम पूरा हो चुका है। पिट लाइन का निर्माण हो जाने से सरकार को थावे जंक्शन गोपालगंज से लंबी दूरी की ट्रेन चलाने में आसानी होगी। थावे में एक ऐतिहासिक दुर्गा मन्दिर है, जहां लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ट्रेन नहीं होने से गोपालगंज के करीब 150 बसें वहां से गुजरती हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और जान-माल की क्षति होती है। अतः गोपालगंज थावे जंक्शन से पिट लाइन का निर्माण कराने की कृपा करें। ... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, as the submission of our hon. Member is not being allowed to be completed, we are walking out of the House. ...(*Interruptions*)

1208 hours

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury and some other hon. Members left the House.)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Hon. Speaker, Sir, I am happy to mention that our Constitution of India came into being 70 years ago. ...(*Interruptions*) We are happy that we are going to celebrate this occasion in Parliament on 26 November, 2019. ...(*Interruptions*) Article 15 (5) of the Indian Constitution gives some special provisions for reservation in educational institutions. ...(*Interruptions*) Accordingly, 15 per cent has been identified for Scheduled Castes; 7.5 per cent has been identified for Scheduled Tribes; 27 per cent for the Other Backward Classes (OBC); and as per the 103rd Constitutional Amendment Act, the Government has included 10 per cent reservation for the Economically Weaker Sections. ...(*Interruptions*)

Here, what I want to insist upon this Government is that they have already advised the State Government institutions and private institutions -- offering medical sciences -- to extend 15 per cent of their total seats to the common pool. Every year, they receive seats in the common pool. In 2017-2018, they have received 9,966 seats. Out of these 9,966 seats, 27 per cent of the OBC quota should have been 2,689 seats.

(1210/SPR/VB)

Out of that, they have extended only 266 seats to OBC, and that too only in the Central institutions. They have not extended it to State Government institutions or the private institutions. In 2018-19, the total number of seats is 12,595; out of that, 27 per cent comes to 3,400. But only 299 seats have been given to OBC in Central institutions. They have not extended it to the State Government institutions or the private institutions. Sir, the Central Government is allotting seats as per 27 per cent reservation. Our State Government is having 50 per cent reservation for OBCs, according to the State law. So, my request is this.

Why not the Central Government extend 27 per cent reservation holistically and extend 50 per cent seats to Tamil Nadu alone, in filling up the medical seats? I am making this request, only as per our Constitution. I am not going away from our Constitution. My request to the Government is to act as per the Constitution. Otherwise, we would condemn the Government that it is going against the Constitution. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सुले को श्री टी.आर. बालू द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र की एक रेल समस्या के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूँ।

मेरे रामटेक संसदीय क्षेत्र में कामटी असेम्बली सेगमेंट है। कामटी एक बड़ी सिटी भी है, जिसकी आबादी दो लाख के करीब है। विशेष बात यह है कि वहाँ पर आर्मी का बेस है। नागपुर से जो ट्रेनें चलती हैं, तो कामटी जैसा बड़ा शहर होने के बावजूद वहाँ कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है।

मैं भारत सरकार और रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 12409-12410 गोंडवाना एक्सप्रेस है, जो निजामुद्दीन से बिलासपुर और बिलासपुर से निजामुद्दीन तक चलती है, का स्टॉपेज वहाँ पर दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य की इस लोक सभा में रोज लॉटरी खुल रही है।

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग के पास गेट था, उसे बंद करके वहाँ अंडरपास बनाया गया ताकि लोगों को और गाड़ियों को बिना रुकावट आने-जाने में सुविधा हो। लेकिन बारिश के मौसम में मेरे क्षेत्र के चाँदवाड़, नानगाँव, मनमाड़, येवला, निफड़ तालुके में बनाए गए अंडरपासेज में भारी मात्रा में पानी जमा होने के कारण ये बंद हो गये। इसके कारण आम जनता, विद्यार्थियों और पेशेंट्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से अनुरोध करती हूँ कि ऐसे अंडरपासेज से पानी को बाहर निकालने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाई जाए। मेरी विनती है कि आम लोगों की सुविधा के लिए एमरजेंसी सिचुएशन में रेलवे क्रॉसिंग गेट को खोलने का प्रावधान किया जाए।

***SHRI SANJAY (KAKA) RAMCHANDRA PATIL (SANGLI) :** Hon. Speaker Sir, thank you. I would like to draw your kind attention towards the unseasonal rain which had caused heavy damage to standing crops in Maharashtra in October, 2019. It had impacted Sangli district and whole of Maharashtra. The farmers of Maharashtra were badly affected. Due to huge loss, farmers are facing social and financial problems.

Now there is President's Rule in Maharashtra and the immediate relief announced by the Hon. Governor is meagre and insufficient. Bad weather and unseasoned rain had mostly affected horticulture and kharif crops.

Hence, I would like to request the Central Government to give enhanced sufficient financial relief to the farmers of Maharashtra immediately.

Thank you.

(1215/KDS/UB)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): धन्यवाद स्पीकर साहब। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपका और संसद का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कि सारा देश जानता है कि हमारे देश का सबसे अहम प्रोटेक्शन ग्रुप स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत के बाद देश को इसकी जरूरत पड़ी। एसपीजी उस समय बनाया गया, जब कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे। सर, उसके बाद राजीव गांधी जी की शहादत जब 1991 में हुई, तो उससे पहले यह ग्रुप विड्रॉ कर लिया गया था। उस समय मेरे ख्याल से चन्द्रशेखर जी की या वी.पी.सिंह जी की गवर्नमेंट थी। उसके बाद चन्द महीनों के अंदर राजीव गांधी जी की शहादत हुई और बड़ा असेसिनेशन हुआ। जिनसे आज वह सिक्योरिटी वापस ली गई है, उस समय वे बच्चे थे। श्री राहुल गांधी जी की आयु 21 साल थी और प्रियंका गांधी जी की आयु 19 साल थी।

माननीय अध्यक्ष: मान्यवर, यह विषय कई बार आ चुका है।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): सर, इससे बड़ा इश्यू कौन सा है? इस परिवार ने देश के लिए दो प्रधान मंत्री दिए हैं। सर, मैं दूसरे अपर हाउस, राज्य सभा के सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने कहा कि इनको आज कोई खतरा नहीं है। दो फांसियां दी गई हैं, जिनका मैं यहां जिक्र करूंगा। अफजल गुरु को किसने फांसी दी? यूपीए गवर्नमेंट ने।

डॉ. जयसिधेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर): धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे संसदीय क्षेत्र सोलापुर जिले के अंतर्गत 39 चीनी उत्पादन करने वाली मिलें हैं, जिसमें करीब 35 मिलें कार्यरत हैं। सोलापुर की चादर और टर्कीस टॉवेल जो सुप्रसिद्ध हैं। इनका निर्यात देश और विदेशों में किया जाता है। सोलापुर में एनटीपीसी और विश्व विद्यालय है तथा यह एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाता है। सोलापुर में एनटीपीसी होने के अलावा यह एक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित हो रहा है। सोलापुर शहर एक सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल है। इसके अलावा पंढरपुर, मंगलवेढा, घाणगापुर, तुलजापुर, हैदरा, अक्कलकोट तथा कूडल इन सभी तीर्थस्थलों पर महाराष्ट्र राज्य के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सोलापुर शहर में विमान सेवा उपलब्ध नहीं है, जिससे तीर्थ यात्री ही नहीं अपितु उद्योजक और विभिन्न क्षेत्र के लोगों को सोलापुर से आवागमन करने के लिए असुविधा हो रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय नागर विमानन मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र से देश के विभिन्न शहरों के लिए विमान योजनान्तर्गत हवाई सेवा जल्द से जल्द शुरू करें। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठें।

...(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): सर,...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पर कभी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आपको अपना विषय रखने का समय मैंने दिया है। यदि आप फिर मौका चाहेंगे, तो फिर आपको समय देंगे, लेकिन इस तरीके से कभी भी आसन पर बात नहीं करेंगे। माननीय सदस्य, नो, प्लीज, मैं लिस्ट के बाद आपको मौका दूंगा।

(1220/MM/KMR)

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र मिश्रिख में उत्तर रेलवे के अधीन मुरादाबाद डिवीजन के संडीला रेलवे स्टेशन के पास एक लेवल क्रॉसिंग नंबर 248 व 249 पर क्रमशः अंडरपास व आरओबी के निर्माण में हो रही देरी की ओर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

महोदय, स्थानीय जनता काफी समय से इन निर्माण कार्यों की मांग कर रही है। अंडरपास व आरओबी न होने से यहां यातायात की व्यवस्था चरमरा जाती है। इसका अनिवार्य सेवाओं में लगे वाहनों, एम्बुलेंस, फायर या पुलिस इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने में देरी होना इसके विलम्ब का कारण है। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकरण को राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के उपरांत उचित कार्रवाई हेतु अपने अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम): सर, मैं आयुष के संबंध में अपनी बात रखना चाहती हूँ। एमबीबीएस में वर्ष 2019 में कटऑफ मार्क 134 था, जिन लोगों के 133 आए हैं, उनका क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि बीडीएस में आयुष का नाम नहीं है, अगर कोई आयुष पढ़ना चाहता है और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है तो उनके लिए अगर नीट से अलग एग्जाम लेंगे तो वह उसी पर ध्यान देगा और तैयारी करेगा। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज के साथ और उसके अंडर ही आयुष चलाया जा रहा है। अगर अलग से कैम्पस नहीं बनाएंगे और एमबीबीएस के साथ में इसको जोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आयुष आगे जा पाएगा। आयुष में 70 परसेंट तक वैकेंसी है। मुझे लगता है कि अगर आयुष को आगे बढ़ाना है, जैसा कि सरकार भी चाहती है, तो इसके लिए इस सब पर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि आयुष के स्टूडेंट बढ़ेंगे और कॉलेज भी कंटीन्यू कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, 5 दिसम्बर, 2017 में भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज डिपार्टमेंट ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ओडिशा के नबरंगपुर के दस रोड रायगढ़ के कुंदेई से शुरू होकर उमरकोट, डाबुगांव और पापड़ाहांडी तक नेशनल हाईवे बनाने के लिए था।

अभी तक न तो ओडिशा का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसका काम कर रहा है और न ही नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट इसको पूरा कर रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत सरकार का रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के द्वारा जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जाए। धन्यवाद।
माननीय अध्यक्ष : श्री सप्तगिरी उलाका को श्री रमेश चन्द्र माझी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. MAHENDRABHAI KALUBHAI MUNJAPARA (SURENDRANAGAR): Respected Speaker, Sir, our hon. Prime Minister, Shri Narendrabhai Modi, launched cashless 'Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)'.

This is the world's largest Government-funded health scheme providing coverage to about 50 crore people for secondary and tertiary care hospitalisation up to Rs.5 lakh to each person of family on family floater basis.

Most of the States and Union Territories have implemented AB-PMJAY but some States like Delhi, West Bengal, Odisha, Telangana and Rajasthan are reluctant to implement this holistic health programme. People from non-implementing States of AB-PMJAY do travel to other States as tourists, pilgrims, workers, labourers, etc. When medical or surgical casualties like accidents, burns, heart attack, etc., happen to them, when they are outside their State, the poor people's condition becomes tragic. I know about this as I am also the owner of an ICU and a medical hospital.

So, I request all Chief Ministers of non-implementing States of AB-PMJAY to please adopt this holistic health programme for the benefit of the poor people of our nation, save them from huge medical expenses, and fulfil our Prime Minister's dream of a pan India AB-PMJAY. Thank you.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I would like to draw the attention of the House to an important issue. For persons with disability, assistive devices ensure personal mobility, communication, and often mean a difference between a life of seclusion and a life of activity.

(1225/SNT/GG)

Being able to lead a normal life, and even beyond that, winning medals for our country is their birth right. But imposition of GST ranging between 5 per cent and 18 per cent has become a hurdle. Instead of assisting them, Government is making their life harder, the extent of which is visible in every

State. This approach of the Government has compelled a huge number of people to stop using or switching over to basic prosthetic equipment.

There are pleas from several thousands of people including Paralympic athletes, be it Manisha Singh, or Neeraj George of Kerala, who seek removal of GST on prosthetic equipment. According to him, his five-year-old dream was achieved with a lot of pain only for a reason that he wanted to prove that differently abled persons without prosthetic limbs can achieve their dreams. And you are charging GST on prosthetic equipment. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी – उपस्थित नहीं।

श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित।

श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित (पालघर): अध्यक्ष महोदय, मैं आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का बिगुल बजाने वाले, आदिवासी स्वाभिमान के नायक एवं लोक देवता के रूप में स्थापित बिरसा मुंडा जी को भारत रत्न देने के लिए आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ।

महोदय, महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सैनिक एवं धार्मिक नेता और लोकनायक के रूप में, जो मंगू जनजाति के संबंधित हैं, वे ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल रेसिडेंसी ऑफ झारखण्ड में 15 नवंबर, 1875 को पैदा हुए थे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने आदिवासी धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसने उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महान व्यक्ति बना दिया। उन्होंने जमींदारों और जमीनदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजों के बिरसा मुंडा के नेतृत्व से डर होने लगा कि जब तक आदिवासी समाज को विश्वास में नहीं लेंगे, तब तक भारत में अपना व्यापार व राज्य स्थापित नहीं पाएंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा और वीर सावरकर जैसे भारत माता के महान एवं वीर सपूतों को भारत रत्न दे कर खुद भारत रत्न का गौरव बढ़ाएं।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री सप्तगिरी उलाका एवं डॉ. भारती प्रवीण पवार को श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल (खडूर साहिब): स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सेहत मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र खडूर साहिब, जो कि बॉर्डर का क्षेत्र भी है, वह कई तरह की सेहत मुश्किलों में ग्रस्त है, उसकी तरफ ले कर जाना चाहता हूँ। सर, जैसे हमारे प्रधान मंत्री जी की एक पॉलिसी है, जिसके तहत हरेक संसदीय क्षेत्र में एक मैडिकल कॉलेज खोला जाना है। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई भी मैडिकल कॉलेज या बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। ना प्राइवेट क्षेत्र का है और ना ही सरकारी क्षेत्र का है। सेहत मंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके, हम जमीन देने

को तैयार है, हमारे वहां मैडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जल्द से जल्द खुलवाया जाए, ताकि जो हमारे लोग कई तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं, पाकिस्तान की हर शरारत, जो वहां से शुरू होती है, उसका सामना करते हैं, कृपा कर मैडिकल कॉलेज और एक हॉस्पिटल वहां जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए। ... (व्यवधान)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, please let me complete my issue. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आपने इश्यु बोल दिया है कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए, सबने समझ लिया है।
... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, सबका विषय एक मिनट में आ जाता है।
प्रो. सौगत राय जी।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, क्या मैं आपसे एक विनती कर सकता हूँ? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ-हाँ करिए।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा, मुझे अपनी बात को कंप्लीट करने दिया जाए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको एक मिनट में कंप्लीट करना है।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): बोलते-बोलते आप बेल बजा देते हैं, सर, बड़ा अपमान होता है।
... (व्यवधान) मैं तो वरिष्ठ सदस्य हूँ। ... (व्यवधान) आप बीच में हैं। ... (व्यवधान) मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आपका विषय इतना लंबा है कि उसके लिए आपको अलग से समय देंगे।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, हमको लंबा नहीं बोलना है। ... (व्यवधान) आप ज़रा सुनिए और मुझे पूरा समय दीजिए। ... (व्यवधान) ज्यादा नहीं, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।
... (व्यवधान) सर, अभी शुरू करें? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रूलिंग एक मिनट की बन चुकी है।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैंने आपसे थोड़ी विनती की है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : फिर अन्य माननीय सदस्य कहेंगे कि रवनीत सिंह जी को डेढ़ मिनट दे दिया, इनको डेढ़ मिनट दे दिया, आपको डेढ़ मिनट अलाऊ करता हूँ।

... (व्यवधान)

(1230/RK/KN)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I would like to refer to the worsening economic situation in the country, which is the worst in many years. Nominal GDP growth at 5 per cent is at a 15-year low, unemployment at 8.5 per cent is at a 45 year-high, household consumption is at four-decade low, bad loans are at all-time high and the growth in electricity generation is at a 15-year low. Auto industry is on the brink of closing down and the real estate sector is in a crisis. This economic situation cannot be solved by giving tax concessions to corporates. Now, retail inflation numbers have shown an increase. Prices have increased.

Sir, all I want to say is that this situation can be solved only by boosting demand through fiscal policy and reviving private investment through social policy. Consumer confidence has dipped further. This is very disturbing. Unfortunately, the Prime Minister is showing a cavalier attitude towards this economic crisis. He is not dealing with economic problems. He is only raising either nationalistic, jingoistic or communal problems. I would urge upon him to give attention to the very serious situation in the economy.

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो में बड़ा स्टील प्लांट है और पास ही इलेक्ट्रो स्टील एक दूसरा प्लांट भी है। सैकड़ों छोटे-बड़े कल-कारखाने हैं। बगल में डीवीसी का चंद्रपुरा थर्मल पावर है, सीसीएल की कोलारीज़ हैं। बोकारो जिले में जहां आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ठेका-मजदूर के माध्यम से काफी काम होता है। वहां पर ईएसआई का हॉस्पिटल नहीं होने के कारण निजी क्षेत्र के ठेका-मजदूर, आउटसोर्सिंग कम्पनियों में काम करने वाले 60-70 हजार लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए सरकार से माँग करता हूँ कि बोकारो में ईएसआई का हॉस्पिटल खोला जाए। धन्यवाद।

श्री दीपक बैज (बस्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बस्तर संसदीय क्षेत्र अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जो दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जिसमें मुख्य रेलवे क्रॉसिंग है, जो सीधा बैलाडीला लोहा खादान को जोड़ता है। जिला मुख्यालय में रेलवे क्रॉसिंग में ओवर ब्रिज नहीं होने की वजह से सड़क के दोनों तरफ लम्बा जाम लग जाता है। उक्त रेलवे क्रॉसिंग किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है जबकि उक्त जिला एक नंबर माईनिंग जिला है। रेलवे व माइनिंग से केन्द्र सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि उक्त रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बने, यह सरकार से मेरी मांग है।

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ से सरकार का ध्यान इस ओर आकृषित करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में पंजाब एवं महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में वित्तीय त्रासदी के कारण कई डिपोजिटर्स को अपने पैसों की परेशानी सहन करनी पड़ रही है।

एक, मैं आपकी तरफ से सरकार से इसके रिवाइवल पैकेज की जल्दी घोषणा करने की माँग करता हूँ। दूसरा, वर्ष 1993 का कानून है, जिसके अंतर्गत डिपोजिटों के एक लाख रुपये तक के डिपोजिट सुरक्षित हैं। लेकिन उसके बाद वर्ष 1993 को आज 26 साल हो चुके हैं, सरकार इसको बढ़ाने की मंशा रखती है। मेरी आपकी तरफ से सरकार से माँग है कि यह एक लाख रुपये की डिपोजिट की सुरक्षा को 15 लाख कर दिया जाए। वित्तीय त्रासदी के कारण ऐसे बैंक जब परेशानी में हो तो डिपोजिटों का पैसा सुरक्षित रह पाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री गोपाल शेटी और डॉ. संजय जायसवाल को श्री मनोज कोटक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र भन्डारा-गोंदिया की ओर आकर्षित करना चाहूँगा।

(1235/CS/NKL)

सरकार के माध्यम से जहाँ बीपीसीएल की ओर से धान के अवशेषों, जिसको राइस स्ट्रॉ कहते हैं, उससे बायो-इथेनॉल प्लांट लगाने की बात कही गयी थी। जिसके लिए जुलाई महीने में ही 74 हेक्टेयर जमीन आबंटित की गई थी। वहाँ 1,500 करोड़ रुपये की लागत से इसे बनाया जाना था और इससे 15 हजार युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से दरखास्त करना चाहता हूँ कि वह इस प्लांट का शुभारम्भ जल्द से जल्द करे। इस प्लांट को एक साल के अंदर चालू करने की बात कही गई थी। इस प्लांट को चालू करने के बाद इस गाँव, शहर और दोनों जिलों, जहाँ भारी मात्रा में राइस पैदा होता है, उसके माध्यम से किसानों को मुआवजा मिलेगा, उनको लाभ होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा (रोहतक): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर माननीय रक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं और मेरी प्रार्थना भी उनसे है। दुनिया में भारतीय सैनिक और अर्धसैनिक बलों की बहादुरी की एक मिसाल है। मेरे हरियाणा को किसान, सैनिकों और खिलाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके साथ-साथ हरियाणा को शहीद और बहादुरों के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से दक्षिणी हरियाणा का अहीरवाल क्षेत्र है। आपने इसकी एक मिसाल सुनी होगी। वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध में, चीन ने बहुत धोखे से रात को रेजांगला की पहाड़ियों पर, रेजांगला की पोस्ट पर जब युद्ध किया तो 120 जवानों में 110 जवान हमारे अहीरवाल के शहीद हुए।

मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज उनमें से हमारे कैप्टन आशा राम जी, हवलदार अभय राम जी अभी जीवित हैं। उनकी एक इच्छा है कि उनके जीते जी अगर अहीरवाल रेजीमेंट की स्थापना हो जाए, तो स्वर्ग में जाकर वे हमारे शहीदों को बताएंगे कि उनके रहते-रहते अहीरवाल रेजीमेंट की स्थापना हुई। बार-बार यह माँग उठी है। हमारे

कई साथियों ने भी इस माँग को उठाया है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि वे दयालुतापूर्वक इस पर गौर करें। धन्यवाद।

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Respected Speaker Sir, I would like to draw the attention of the House towards the severe floods that are repeatedly affecting Kerala, and also some other States. The Central Government should think about it. It is happening every year because of the climate change.

If you take the example of Kerala, during 2018 Kerala floods, about one million people were evacuated, almost 480 people died, and about 140 people were missing. This time also, the situation is nearly the same. Almost the same number of people died this year also due to such calamities. Almost one sixth of the total population had been affected in the flood related incidents.

Last year, the Central Government helped a little bit. The State Government requested Rs. 4,700 crore as compensation from the Central Government but the Central Government gave Rs. 3,048 crore. This time, there is no help from the Central Government. Nobody knows what is the reason for that. The Central Government says that the State Government has not spent the entire money. We do not know about that. But the people are not getting anything. In certain districts like Wayanad and Malappuram, people are still in relief camps. So, this is a very serious situation. The Central Government has to come forward and help the State Government this time also. Otherwise, people will not get anything, and they will have to continue in the relief camps.

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Hon. Speaker Sir, today is the World Fisheries Day. The mind of fishermen is like the fish, not well on the land. The unsafe sea and land worries them a lot. Fish catch is decreasing day by day. The striking sea and unprecedented restrictions for fishing are destroying the dreams of fishermen.

(1240/SRG/RV)

He did not get his remuneration for his efforts. Hon. Speaker Sir, this is very emotional and sentimental to me to tell you that the traditional fishermen are in complete despair in our country. Fish wealth is declining. The entire organic system is changing in the sea. Climate change is doubling the suffering of these fishermen. Frequent coastal erosion and natural calamities are taking away their houses and boats. Poverty is a common thing; education is a far

dream. After the Adivasi community, it is the fishermen who are suffering the most. I request the Central Government to give a special package for welfare of fishermen in our country.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री टी. एन. प्रथापन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदय, जुलाई-अगस्त के माह में महाराष्ट्र में भारी वर्षा की वजह से वहां कृष्णा, पंचगंगा, वारना और कोयना नदियों में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। कोल्हापुर, सांगली, दोनों जिले कम से कम पन्द्रह दिनों तक बीस-बीस फीट पानी के अन्दर थे। उसमें 50 से भी ज्यादा लोगों की जानें गयीं थीं और करीब सात-आठ हजार जानवरों की भी जानें गईं थीं। केन्द्र सरकार की जो टीम वहां गई थी, उन्होंने वहां पर सात हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नुकसान का अंदाजा लगाया था। उस वक्त केन्द्र सरकार ने 900 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक वहां एक पैसे की भी मदद नहीं हो सकी। इसलिए लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जो स्ट्रिक्चर्स पास किए, उसमें बहुत नाराजगी व्यक्त की गई है।

महोदय, इसलिए इस ज़ीरो आवर के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से विनती करना चाहता हूं कि बाढ़ से प्रभावित कोल्हापुर, सांगली जिले के लोगों को आधार देने के लिए, वहां के लोगों को अर्थ सहायता देने का इंतजाम जल्द से जल्द करें। एक नैसर्गिक आपत्ति के लिए भी अगर न्यायालय आदेश देता है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है। यह पूरी होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री ओम पवन राजेनिंबालकर एवं श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक को श्री विनायक भाउराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे (बीड): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मौका दिया। उसके पूर्व मैं एक और चीज़ के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि हम सभी सांसदों के काम में क्या प्रोग्रेस है, इसका आप बहुत ध्यान रखते हैं और हम सबको प्रेरणा देते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा आगे आकर अपने चुनाव क्षेत्र के मुद्दे को आगे रख सकें। आप जैसा स्पीकर सर होने के नाते हमारे कार्यकाल में हमें इसका बहुत फायदा होने वाला है। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूं।

सर, मैं अपने मुद्दे पर आती हूं। जैसा कि आप इससे अवगत हैं कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में पिछले कुछ दिनों से जो भारी मात्रा में वर्षा हुई है, उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान वहां के किसानों को झेलना पड़ रहा है।

सर, इसका खरीफ की फसल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। उसी में कपास भी एक फसल है। पूरे महाराष्ट्र का अगर आप ब्यौरा देखें तो विदर्भ में कपास खरीददारी के जो केन्द्र हैं, वे सितम्बर से शुरू हो चुके हैं, पर मराठवाड़ा में और अन्य जगहों पर ये केन्द्र अब तक शुरू नहीं हुए हैं क्योंकि भारी मात्रा में जो वर्षा हुई है, उसके कारण फसल को तो हानि पहुंची ही है, इसका भाव भी कम होता

जा रहा है। इस स्थिति में अगर सरकार मराठवाड़ा में इस केन्द्र को जल्द से जल्द शुरू नहीं करेगी तो वहां के किसान अपने आप को और भी बेबस महसूस करेंगे।

इस आपदा की स्थिति में केन्द्र सरकार और राज्यपाल महोदय, दोनों ही अपनी तरफ से इसमें जरूर मदद करेंगे, पर मैं आपके माध्यम से यह दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि मराठवाड़ा क्षेत्र में सरकार के कपास खरीददारी केन्द्र जल्द से जल्द शुरू करा दिए जाएं।

SHRI MANNE SRINIVAS REDDY (MAHBUBNAGAR): I would like to bring to your kind notice, the need to set up a new Sainik School in Narayanpet district in my Mahbubnagar Parliamentary constituency in Telangana State.

Sir, I would like to state that many poor families, particularly from SC, ST and economically backward classes, are there who cannot afford high fees in private schools to provide quality education to the children. Their parents have requested me many times in this regard.

(1245/RP/MY)

Our Telangana State Government is ready to extend all the required cooperation in this regard. The people of my Constituency are eagerly waiting to start the classes. Thank you, Sir.

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): अध्यक्ष जी, मैं देश और अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहां उठाने जा रहा हूँ। आज देश के अंदर कई जगहों से इस प्रकार की खबरें आती हैं, पुलिस के अंदर इतना स्ट्रेस रहता है कि कई कॉन्स्टेबल तथा अधिकारी या तो खुद स्यूसाइड कर लेते हैं, या कई बार एक दूसरे के ऊपर भी गोली चला देते हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं सामने आई हैं।

मान्यवर, अभी मेरे संसदीय क्षेत्र का कॉन्स्टेबल प्रवीण कुमार बागपत जिले में तैनात था, वहां पर उसकी मौत हो गई। उसकी मौत उसी चौकी के दरोगा इंचार्ज के रिवाँल्वर से हुई। जब मैं उसके परिजनों से मिलने गया, तो उसके परिजनों का यह कहना है, आप यह देखिए कि कॉन्स्टेबल प्रवीण कुमार एक गरीब दलित परिवार का लड़का है। उसके पास एक छोटा-सा मकान है। उसके परिजनों का कहना है कि दरोगा ने उसकी मौत की है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर आग्रह करूंगा कि उसकी जांच पूरी तरीके से हो और हो सके, तो सीबीआई से उसकी जांच हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक एफआईआर भी लॉज नहीं की है। जब मैंने अधिकारियों से बात की, तो उनका कहना था, ... (व्यवधान) क्योंकि वह दलित है, इसलिए उसको एससी/एसटी एक्ट में तुरंत मुआवजा मिल जाएगा... (व्यवधान)

کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکر صاحب، میں ملک اور اپنے پارلیمانی حلقہ

سے جڑا ہوا ایک بہت ہی اہم مدعہ یہاں اٹھانے جا رہا ہوں۔ آج ملک کے اندر کئی

جگہوں سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں، پولس کے اندر اتنا اسٹریس رہتا ہے کہ کئی

کانسٹبل اور دوسرے افسران یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا کئی بار ایک دوسرے پر گولی چلا دیتے ہیں۔ اس طرح کی کئی واردات سامنے آ چکی ہیں۔

جناب، ابھی میرے پارلیمانی حلقہ کا ایک کانسٹبل پروین کمار باغیت ضلع میں تعینات تھا، وہاں پر اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت اسی چوکی کے دروغہ انچارج کے ریوولور سے ہوئی۔ جب میں اس کے رشتہ داروں سے ملنے گیا، تو اس کے رشتہ داروں کا یہ کہنا تھا کہ آپ دیکھئیے ک کانسٹبل پروین کمار ایک غریب، دلت فیملی کا ایک لڑکا ہے، اس کے پاس ایک چھوٹا سا مکان ہے۔ اس کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ دروغہ نے اس کی موت کی ہے۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اتنی ضرور گزارش کروں گا کہ اس کی جانچ پوری طریقے سے ہو اور ہو سکے تو سی۔بی۔آئی۔ سے اس کی جانچ ہو، کیونکہ اتر پردیش سرکار نے ابھی تک ایف۔آئی۔آر۔ بھی درج نہیں کی ہے۔ جب میں نے افسران سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ (مداخلت)۔ کیونکہ وہ دلت ہے اس لئے اس کو ایس۔سی/ایس۔ٹی۔ ایکٹ میں فوراً معاوضہ مل جائے گا (مداخلت)۔۔۔۔۔

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर को कुंवर दानिश अली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri S. Venkatesan – not present.

Shri M. Selvaraj.

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Sir, last year the Gaja Cyclone has devastated the Cauvery Delta Region of Nagapattinam, Thiruvarur and Thanjavur districts in my Constituency. More than 8 lakh coconut trees were uprooted. All the banana trees and paddy crops were completely damaged by this natural calamity. The farmers were driven to poverty.

The insurance companies, which are supposed to give crop insurance amount, have failed to disburse the insurance amount for more than half of the poor farmers. More than one year has elapsed. They did not disburse the crop insurance amount on flimsy grounds.

The Union Government should intervene and make sure that all the affected agriculturists get the crop insurance amount. It will help the poor farmers who are virtually starving.

Here, I would like to suggest that the Central Government may directly supervise the crop insurance scheme instead of giving it to the private companies. This may reduce the hardships being faced by the poor farmers. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री एम. सेल्वराज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मोहम्मद अकबर लोन साहब । हमारे अकबर लोन साहब नेशनल काँग्रेस के नेता है। नेशनल काँग्रेस के लोग कल भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर लोन (बारामूला): देखिए, कब तक आप उसको रखेंगे?... (व्यवधान) जनाब स्पीकर सर, जम्मू-कश्मीर को रेस्ट ऑफ दी कंट्री से मिलाने के लिए जो राष्ट्रीय रास्ता है, वह जम्मू-श्रीनगर रास्ता है। जम्मू-श्रीनगर रास्ता कभी भी एक दिन के अलावा खुला नहीं रहता है। उसका कारण यह है कि पेशिया गिराई जाती है। उसको ठीक करने वाला जो महकमा है, वह इसको अपने हिसाब से ठीक तरह से उसका ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वहां ठीक तरह से काम भी नहीं हो रहा है। मेरा आपसे गुजारिश है कि आप अपने उन लोगों से कहें, जो उसको महत्वपूर्ण कंडीशन में रखना चाहते हैं। उनको ठीक तरह से काम करने के लिए हिदायत बख्शी जाए।

جناب محمد اکبر لون (بارا مولہ): جناب چیرمین صاحب، کب تک آپ اس کو رکھیں

گے؟ (مداخلت)۔۔ جناب اسپیکر صاحب، جموں و کشمیر کو ریست آف دی کنٹری سے ملانے کے لئے جو قومی راستہ ہے، وہ جموں سری نگر کا راستہ ہے۔ جموں سری نگر کا راستہ کبھی کبھی کئی دن تک نہیں کھلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جب موسم خراب ہوتا ہے تو چٹانیں گرتی رہتی ہیں۔ اس کو ٹھیک کرنے والا جو محکمہ ہے، وہ اس کو اپنے حساب سے ٹھیک طرح سے اس کا دھیان نہیں دیتے ہیں، اس لئے وہاں ٹھیک طرح سے کام بھی نہیں ہو رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے اس کام کے لئے ایک مخصوص رقم رکھی جائے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اس تکلیف سے نجات مل سکے۔ اور آپ اپنے ان لوگوں سے کہیں جو اس کو اہم کنڈیشن میں رکھنا چاہتے ہیں۔

ان کو ٹھیک طرح سے کام کرنے کے لئے ہدایت بخشی جائے۔ شکریہ

*SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. The recent archeological excavation conducted in Keezhadi by the Tamil Nadu Government has proved that the age of artefacts found in Keezhadi belonged to 6th Century BCE. Hon. Union Minister has also endorsed this revelation in Rajya Sabha yesterday. In this context, I urge upon the Union Government that Sangam Age of Tamil Civilization mentioned as 3rd Century BCE in the 6th Standard and 12th Standard textbooks of NCERT should be changed as 6th Century BCE in the textbooks meant for forthcoming academic year. Secondly, it should also be mentioned in the NCERT textbooks that the urban settlements were also formed on the banks of River Vaigai at the places wherever it is mentioned that the big urban settlements were formed on the banks of River Ganges. Thirdly, I urge upon the Government through this August House that it should be prominently mentioned in the NCERT textbooks the fact that the Urban Settlements or Cities thus formed on the banks of river Vaigai in Tamil Nadu were fully literate. Thank you.

(1250/RCP/CP)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir. On 31st October, 2019, the Ministry of Home Affairs has released a new political map of India. But we are shocked to see that Amaravati, the capital of Andhra Pradesh is missing in this map. This is not only an insult to the people of Andhra Pradesh, but it is an insult to the hon. Prime Minister who has laid the foundation stone for Amaravati in 2015. The contention that there was no Gazette Notification issued is a frivolous and trivial argument. If this map goes into circulation, it is going to impact the flow of investments into our new State.

In view of the above, I request the Government of India to immediately rectify this situation and issue a revised map showing Amaravati as the capital of Andhra Pradesh. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री जयदेव गल्ला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI P. C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT): Sir, I hasten to raise an important issue, though belatedly, relating to severe loss of lives and crop damage in my district Bagalkot, Karnataka during the last monsoon, the heaviest in more than hundred years.

*Original in Tamil

Contrary to the perception that my constituency Bagalkot is considered a barren and drought prone area, this time it suffered the heaviest deluge of rains causing intensive crop damages as also loss of precious human lives and livestock. In quick response, the State Government had rushed rescue teams to the flood affected areas and announced compensation for two lakh families along with an ex-gratia payment of Rs. 5 lakh for the kin of each deceased victim. In addition to this, emergency supplies of essential commodities were also provided by the State Government to the marooned people.

It is because of torrential rains, the course of rivers changed causing erosion of river embankments and the surging waters washed away the top soil, thereby making the terrain unproductive until restoration measures were undertaken on a mass scale. The Centre has been apprised of the extent of damage caused by floods and funds needed to restore normalcy in terms of restoration of communication, roads and bridges as also replenishing top soil of a large area raising agricultural and horticultural crops to become productive again. With its meagre resources and fiscal constraints, the State Government expects the Centre to come forward by releasing calamity funds in order that rehabilitation of the flood affected people and restoration of the soil are taken up early in view of the forthcoming crop season.

I urge upon the Centre to respond to my plea with urgency and compassion. Thank you, Sir.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I rise to draw your attention and the attention of the House to an alarming financial situation in the country. Today's newspapers have three front-page items, namely, sale of five profit making public undertakings to cough up Rs. 85,000 crore for the Government; at the same time, the Government has given Rs. 42,336 crore moratorium to telecom companies on their payments to the Government; and more disturbing, the Reserve Bank of India takes over the ailing Housing Finance Corporation.
(1255/NK/SMN)

Adding to the already confused scenario, the market regulator Securities and Exchange Board of India's new rules for further disclosure of the listed companies on their loan payments and right issues to warn the investors is very worrisome.

Sir, I have been raising the issue of sale of BPCL, a navratna company, earning profits for years, which has a base in my constituency. Now, if we look into the list of PSUs which are for sale this year, they are all profit-making companies like Shipping Corporation, the Container Corporation of India – CONCOR, the Hydro Development Corporation of India and North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO).

The Government's notification informed that all these profit-making corporation will undertake a sale of 51 per cent stake and the control of the companies will be with the Government on a case to case basis depending on the stake of the other Government organisations.

Sir, I strongly suggest to the Government that there must be re-thinking and further expert consultations at the highest level before deciding on the sale of these PSUs.

श्रीमती रक्षा निखिल खडसे (रावेर): अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के मंधान मंत्री चाहते हैं कि देश के किसानों को बैंक के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। आज की ग्रामीण क्षेत्र की वास्तविक परिस्थिति यह है कि पहले नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या कम है और उसमें भी कर्मचारियों की संख्या कम है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्र और खासकर मेरे जलगांव जिले में ऑफिसर की नियुक्ति हो। वहां किसानों को व्यवस्था मिलनी चाहिए। कल ही मेरे मुक्ताई नगर तहसील में लोगों स्टेट बैंक को ताला लगा दिया क्योंकि वहां पर कर्मचारी नहीं थे। इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ न कुछ एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री उदय प्रताप सिंह और डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे को श्रीमती रक्षा निखिल खडसे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्वोत्तर राज्य और विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में केब बिल के बारे में निगेटिव अप्रेहन्शन है। आनरेबल एचएम, होम यहां बैठे हैं। इस बिल के अच्छाई के लिए दो बिन्दु रखना चाहता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में एनजीओ और स्टुडेंट ऑर्गेनाइजेशन की मांग है कि अरुणाचल ट्राइबल राइट्स, लैंड और प्रोपर्टी प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश जमाने से एक रेग्युलेशन है। Bengal Eastern Frontier Regulations 1973 and Chin Hill Act, 1896 Sections 20, 22, 23 and 40 सीएबी में डाला जाए तो इससे पूर्वोत्तर राज्यों में निगेटिव इम्पैक्ट या अप्रेहन्शन नहीं होगा। Article 71 (A-J) and all six Scheduled States and autonomous districts in the North Eastern Region. इस चीज को केब में इनकॉरपोरेट करेंगे तो शांति होगी, मैं यही मांग करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, I rise to draw the attention with regard to construction of AIIMS at Thoppur. It is situated at

Virudhunagar which is an aspirational district. AIIMS was announced in the 2015 Budget, that is, before the 2016 Assembly elections.

Hon. Prime Minister laid the foundation before the Lok Sabha elections in February, 2019. After 10 months, no construction work has started. Therefore, I would like to ask the Government about this project. JICA will fund this to the tune of Rs. 1250 crore. No progress has taken place for the past 10 months. Therefore, I would request the Government to speed it up and start the construction work before 2021 Assembly elections. Thank you Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री बी. मणिकम टैगोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र बदायूं की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं। हमारे क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन बहुत अधिक होता है।

(1300/SK/MMN)

यहां शुगर मिल के अभाव के कारण उत्पादन अच्छा होने के बावजूद किसान भाइयों को मेहनताना नहीं मिल पाता है। यहां क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान महापंचायत में किसानों ने एक स्वर में कहा कि इस बार वे निजी शुगर मिलों को अपना गन्ना नहीं बेचेंगे क्योंकि निजी शुगर मिल गन्ना तो ले लेती हैं, लेकिन भुगतान नहीं कर पाती हैं। उन्होंने कहा कि इस बार चाहे गन्ना खेत में ही सड़ जाए लेकिन निजी शुगर मिलों को नहीं देंगे।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों के पूर्व भुगतान का निस्तारण कराया जाए व पास के सरकारी शुगर मिल पर केंद्र बनाया जाए ताकि अन्नदाता खुशहाल हो सकें।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपस में बात न करें। सदस्यों की लंबी बातचीत के लिए सदन के बाहर सेंट्रल हॉल और गैलरी है। मैं पुनः आग्रह करता हूँ।

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Speaker, Sir, I am raising a very important issue related to the paddy farmers in Kerala, especially in my constituency in Kuttanad. In Kerala, the paddy farmers are facing a serious crisis in getting their PRS from the nationalised banks like the State Bank of India, Canara Bank, Scheduled Banks and Federal Bank. Actually, during the procurement period, the banks are giving the payment of paddy price to the paddy farmers. After that, the State Government and the Central Government give that money to the banks. Now, the payment of this amount is delayed by both the State and the Central Governments. An amount of around Rs.800 crore is pending with the State and the Central Governments. Now, this time the *puncha* procurement has already started in Kuttanad. The farmers are approaching the nationalised and scheduled banks. They are denying them to give the PRS.

Therefore, I would like to request, through you, Sir, the hon. Minister of Food and Civil Supplies to release the amount of Rs.450 crore from the Central Government. The Central Government's share of Rs.450 crore is pending with the Ministry of Food and Civil Supplies. I request the hon. Minister to release the amount immediately.

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं एक गंभीर विषय संसद में उठाना चाहता हूँ। एक दिन पहले घर से फोन आया और पता चला कि घर के सामने पुलिस है। मैंने पता किया, सुरक्षा के लिए पुलिस घर में आई थी। ओडिशा के सांसदों और विधायकों के घरों के सामने पुलिस थी। इसका कारण यह है कि ओडिशा में और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसानों का आंदोलन

चल रहा है। जिस समय प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, किसानों को मार्केट में जाकर धान बेचना चाहिए, वे रास्ते में बैठे हुए हैं। नेशनल हाई वे जाम है, विधायकों का घर जाम है। कलक्टर आफिस, सब-कलक्टर आफिस, तहसीलदार आफिस सब जाम है और कारण यह है कि अब वहां टोकन सिस्टम शुरू किया गया है। अगर किसान टोकन लेंगे तो ही धान बेच पाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर जैसे पहले होता था वैसे ही होना चाहिए। किसी भी प्रदेश में टोकन सिस्टम नहीं है। दुनिया में कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है लेकिन ओडिशा में शुरू किया गया है। इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो।

मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप केंद्र सरकार को निर्देश करें। केंद्र सरकार को ओडिशा सरकार से बात करनी चाहिए, टोकन सिस्टम समाप्त करना चाहिए। किसान कैसे धान बेच पाएं और सही मूल्य पा सकें, इसका निदान करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री सप्तगिरी उलाका को श्री सुरेश पुजारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय अध्यक्ष जी, मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र की एक युवती, जो अपने घर के पास ही एक स्कूल में पढ़ाती थी, नदीम नाम के पाकिस्तान युवक के संपर्क में थी। दिनांक 4 नवंबर, 2019 को युवती का पासपोर्ट बना था तथा 8 नवंबर, 2019 की सुबह वह युवती स्कूल गई परंतु लौटकर नहीं आई।

(1305/MK/VR)

लड़की के पिता ने उसी दिन स्थानीय थाने में युवती के गायब होने की सूचना दी, परन्तु थाने ने न तो एफआईआर लिखी न ही युवती की तलाश के लिए कोई कार्रवाई की। 10 नवम्बर को युवती के निराश पिता मुझसे मिले तथा मैंने मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की। मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उस युवती को नदीम द्वारा दुबई ले जाने की आशंका से भी परिचित कराया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर विभाग सक्रिय हुआ, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। अब युवती के बारे में यही आशंका है कि उसे अवैध तरीके से दुबई अथवा किसी अन्य देश में ले जाया जा चुका है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस मामले की विस्तृत जांच कराकर युवती को बरामद कराने की कृपा करे।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के 70 साल बाद भी सरकार द्वारा देश को कुपोषण मुक्त करने के लिए अनेकों कार्यक्रम और योजनाएं चलानी पड़ी हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र कर्जत में पिछले तीन महीने पहले 171 बच्चे कुपोषित पाए गए और इनमें से 74 बच्चे अति कुपोषित पाए गए। यह जानकारी सरकारी जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। मैंने 5 दिसम्बर, 2014 को तारांकित प्रश्न पूछकर सदन के माध्यम से कुपोषण के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था तब मुझे मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि सरकार जल्द से जल्द देश को कुपोषण मुक्त करेगी और देश को कुपोषण मुक्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम भी चलाएगी। लेकिन, वर्ष 2014 से आज तक देश भर में कुपोषित बच्चों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपके

माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार कुपोषण को गंभीरता से ले और देश को कुपोषण मुक्त करने के लिए कार्यक्रम चलाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से अपने लोक सभा क्षेत्र में स्वीकृत बाईपास की तरफ माननीय भूतल परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जनपद प्रतापगढ़ के एनएच-96 एवं एनएच-231 को मिलने वाले प्रतापगढ़ बाईपास का काम तथा राम वन गमन मार्ग जैसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर को आगे बढ़ाने का प्रोजेक्ट लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में मुआवजे का पैसा उपलब्ध करा दिया गया था। लम्बे समय बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन प्रतापगढ़ अभी तक किसानों को मुआवजे की मिली रकम को बांटा नहीं सका। हालात इतने बदतर हैं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र नगरीय क्षेत्र बेलहा प्रतापगढ़ भयंकर जाम की समस्या से बुरी तरह त्रस्त है। दूसरा कोई बाईपास न होने के कारण प्रयागराज-अयोध्या जाने वाला एनएच-96 मध्य शहर के पार्श्व इलाके घंटाघर से होकर निकलता है। इसलिए सुबह नौ बजे से ही शहर वाहनों के आवागमन से हांफने लगता है। लोगों को 2-3 किलोमीटर की यात्रा के लिए घंटों जाम झेलना पड़ता है। जाम के अलावा अत्यधिक वाहनों खासकर भारी माल वाहक ट्रकों के आवागमन के कारण धूल और गर्दा से गुब्बार नगरवासी त्राहि-त्राहि कर दमा जैसी घातक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHICODE): Sir, I would like to raise a very important issue regarding the fate of the National Institute for Research and Development in Defence Shipbuilding (NIRDESH) at Chaliyam under the Department of Defence Production.

Sir, NIRDESH began its operations in 2010 at Chaliyam, part of my constituency, Kozhikode. Conceived as a national centre of excellence to achieve self-reliance in strategic area of warship building, today it is in a very pathetic condition with just one officer to run the business.

The National Institute for Research and Development in Defence Shipbuilding (NIRDESH) requires Cabinet approval and also funds to start its operations in full steam besides the cooperation of defence shipyards to begin with.

Kind intervention of the Defence Minister and the hon. Prime Minister for Cabinet clearance and funding is required. Otherwise, the requirement of self-reliance in shipping sector will be a set back to the nation. Thank you, Sir.

(1310/RAJ/SAN)

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय बंदरों के आतंक से तीर्थस्थलों में रहने वाले लोगों के लिए समस्या से संबंधित है। बंदर का नाम लेते ही हम सभी को मजाक लगता है, लेकिन यह विषय बहुत ही गंभीर है, इसलिए मैं आज यह विषय आपके सामने उठा रही हूँ। मथुरा, गोवर्द्धन और वृंदावन के लोग बंदरों से परेशान हैं। वृंदावन में घना जंगल हुआ करता था, जहाँ बंदर खुशी से खाते-पीते और रहते थे, लेकिन वहाँ आज सिर्फ बिल्डिंग्स हैं और पेड़ इतने कम हैं कि कहने लायक नहीं है। जिसके कारण वहाँ के भूखे बंदर घर-घर जाकर आतंक मचाते हैं और वहाँ के नागरिक उन्हें मार-मार कर भगा देते हैं। तीर्थ यात्री उनको फूटी पिलाते हैं, समोसा, कचौड़ी और मथुरा का पेड़ा खिलाते हैं, जिसकी वजह से बंदर बहुत बीमार हो चुके हैं। यह बीमारी फैल रही है, यह बीमारी वहाँ के लोगों में भी फैल रही है। वहाँ के डॉक्टरों ने बंदरों की संख्या को कम करने के लिए स्टरलाइजेशन भी किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे बहुत वायलेंट हो गए हैं और वे लोगों पर जानलेवा हमला करते हैं। वृंदावन में ऐसा भी हुआ है कि कई लोग मर चुके हैं, यह सच है। हम लोगों को इस धरती पर रहने का जितना हक है, उतना ही जानवरों को भी इस धरती पर रहने का हक है। इसके लिए समाधान होना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से वन विभाग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 'मंकी सफारी' बना कर बंदरों को एक जगह रखेंगे, तो नागरिक और बंदरों की समस्या कम हो सकती है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती करती हूँ कि इस बात को बहुत गंभीरता से लें और इस समस्या का समाधान जरूर करें, इसे मजाक न समझें। It is a very important matter.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मनोज राजोरिया, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री गणेश सिंह, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री राहुल रमेश शेवले, श्री ओम पवन राजेनिंबालकर, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती हेमामालिनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री चिराग पासवान (जमुई): अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर समस्या है। जिस तरह से वन खत्म हो रहे हैं, बंदर तो एक इश्यू है ही, हम लोगों के एरिया में तथाकथित जो लुटियन जोन है, जहाँ पर घरों में परिवार और बच्चे रहते हैं। वहाँ गार्डन भी है, लेकिन बच्चे गार्डन में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ बंदरों का बहुत आतंक है। बंदर काटते हैं, परेशान करते हैं, हैरान करते हैं। लुटियन जोन में बोर्ड भी लगा दिए गए हैं कि बंदरों से सावधान रहें। यह गंभीर चिंता की बात है। मैं चाहूँगा कि मिनिस्ट्री इस पर ध्यान दे। डिफॉरैस्टेशन हो रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए वे हमारे घरों की ओर रुख कर रहे हैं। यह जरूरी है कि हम उनके घरों को सुरक्षित रखें ताकि वे अपने घर में सुरक्षा से रहें और हम अपने घर में सुरक्षा से रहें। दिल्ली में भी यह बड़ा विषय है। जिन्होंने इस विषय को उठाया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I have also been a victim of such a situation.

I am habitual of visiting Vrindavan. There is Ramakrishna Mission whose headquarters Belur Math is in Kolkata. When I visited, I was wearing my spectacles.

माननीय अध्यक्ष : मैडम, आप बैठ जाइए। आपके विषय का नोटिस लिया है।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): I went to Vrindavan to see the Banke Bihari Mandir.

I am very much connected with Ramakrishna Mission over there. The Guruji was also accompanying me. I was wearing my spectacles. When I simply stepped out of my car, I had a feeling of some touch and found that there were no spectacles on my eyes. It was so nicely lifted by a monkey that it was unbelievable. The moment eight or ten Fruity packets were thrown by the shopkeepers, बंदर ने वहां उसको देखा, वहां से उतरा और दो फ्रूटी लेकर ऊपर गया और चश्मा वापस दे दिया। At few places, I watched some persons waiting, from where the monkeys could get Fruity. फ्रूटी पीने के बाद उनके पेट में दर्द होता है, लेकिन वे खुद फ्रूटी मांगते हैं। So, the situation is very dangerous. आप मंदिर दर्शन करने से पहले अपना चश्मा, प्रसाद, सभी चीजें पॉकेट में रख दीजिए। जो चश्मा के बिना नहीं देख पाते हैं, वे भी बंदर के डर से मंदिर में ऐसे-ऐसे घूमते हैं। Sir, you take the issue seriously. Shrimati Hema Malini is the local MP of that area. I hear from the Ramakrishna Mission people that she also goes there and takes up their problems.

Sir, this is a serious issue and can be tackled by the Government.

(1315/VB/RBN)

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष जी, जिन क्षेत्रों में खनिज होते हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश के लोगों के लिए प्रधान मंत्री खनिज कल्याण कोष नाम की योजना दी। वे पैसे, जो भारत सरकार के खजाने में जमा होते हैं, वे उन्हीं जिलों में हेल्थ, एजुकेशन और सड़क-निर्माण में काम आएँ।

हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बना है। राजस्थान में सरकार बदलते ही उसमें से जनप्रतिनिधियों को हटा दिया गया और सारे पैसे को रोक लिया गया।

पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से सौ रुपये भेजे जाते हैं, तो गाँव में पहुँचते-पहुँचते 15 रुपये ही रह जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई निदान नहीं किया।

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने चाहे मनरेगा के मजदूरों के पैसे हों, पंचायत के विकास के पैसे हों, अब वे सीधे खाते में जाते हैं। राजस्थान में 14वें फाइनेंस कमीशन के पैसे, जो पंचायतों में जाने चाहिए थे, उनको रोक लिया गया। वे पैसे पंचायत समिति में पड़े हैं।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि चूँकि वे पैसे भारत सरकार के हैं, इसलिए वे सीधे पंचायत में जाएँ ताकि पंचायतों का विकास हो सके। मेरी सरकार से यही माँग है।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. मनोज राजोरिया और श्री सुमेधानन्द सरस्वती को श्री सी.पी. जोशी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्य के शपथ लेने के तीसरे दिन ही ये सदन में अपनी बात कह रहे हैं।

आपको बधाई हो।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पहले दो बार चुनकर आया हूँ। अभी मैं संसद सदस्य के रूप में तीसरी बार आया हूँ। इसके पहले मैं सिक्किम में राज्यपाल था।

मैंने आपसे विनती की थी और आपने उसे मानते हुए मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मेरे सतारा डिस्ट्रिक्ट में पश्चिम की ओर डैम होने की वजह से वहाँ के किसान हाई क्वालिटी के प्रोड्यूस- फल, फूल और सब्जियाँ उगाते हैं। ये चीजें मुम्बई और पुणे भेजने के लिए रेल की सुविधा हेतु वहाँ के किसान स्टेशन मास्टर से मिलते हैं।

वहाँ के लोगों ने मुझसे मिलकर कहा कि एक किम्बरजकर रेलवे जंक्शन है, जो सातारा से 150 किलोमीटर दूर दक्खिन में है, उधर जाकर प्रोड्यूस देना पड़ता है और दूसरे दिन उसे भेजा जाता है। ताजी फल और सब्जियाँ एक दिन पहले भेजने के लिए दिया जाए और वे सूख जाएँ, तो इससे काश्तकारों के जीवन में जो पैसे आने वाले हैं, वे नहीं आते हैं।

कई ट्रेन्स जो पुणे और मुम्बई या अहमदाबाद और दिल्ली जाती हैं, उनमें ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस चढ़ाने के लिए डीआरएम, पुणे, सेन्ट्रल रेलवे कंसीडर करे और जितने भी फल-फूल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं, उनको फ्रेश अवस्था में मुम्बई भेजा जाए, तो इससे अच्छे पैसे मिलेंगे और किसानों का नुकसान नहीं होगा।

(1320/SM/PC)

SHRI T.R.V.S. RAMESH (CUDDALORE): Thank you, Hon. Speaker, Sir, for giving me an opportunity to speak during Zero Hour regarding development of seaport in Cuddalore Parliamentary constituency. Sir, seaport and harbour should be developed in Cuddalore. ...(*Interruptions*). I am in front of the pillar, Sir.

A large volume of imports such as raw cashew nuts, coal of Neyveli Lignite Corporation and products from and into SIPCOT industrial park are now handled in Tuticorin and Chennai ports and this transportation and logistics improve efficiencies for these organisations with large-scale employment and benefit in the development of the port. Harbour should be developed in my Cuddalore constituency.

I, therefore, request you to consider my request to grant approval for opening of seaport in my constituency, Cuddalore so that people from all walks of life can be benefited.

माननीय अध्यक्ष : कैबिनेट मंत्री महेन्द्र पाण्डेय जी यहां बैठे हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सर, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, महेन्द्र जी कैबिनेट मंत्री हैं। दादा, आप जानकारी प्राप्त कर लिया करें।

...(व्यवधान)

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, I would like to draw the attention of the House towards the need for expeditious new railway line in my Theni constituency between Dindigul and Sabarimalai.

Previously, the Railway Board had sanctioned and done the survey for a new broad-gauge line from Dindigul to Sabarimalai. Since then, this proposal has been pending without any further move. A report was also submitted to the Railway Board in 2014. This line is imperative for the people of three districts as well as tourists and pilgrims of Sabarimalai.

Therefore, I once again urge the Government to take immediate steps for early completion of this new line without further delay.

श्री अर्जुन सिंह (बैरकपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी ने प्लास्टिक और प्रदूषण मुक्त भारत का जो आह्वान किया है, मैं आपके माध्यम से उसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा।

महोदय, हमारे पश्चिम बंगाल में जूट इंडस्ट्री थी। एक समय पश्चिम बंगाल को जूट उद्योग का मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि वर्ष 1992-93 में एक कानून लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि इंडस्ट्रियल जमीन ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन जब से ... (*Not recorded*) की सरकार आई है, पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रियल जमीन का कैरेक्टर चेंज हो जा रहा है, subject to approval.

महोदय, 66 परसेंट जमीन बेची जा रही है और कहा जा रहा है कि 33 परसेंट जमीन बंगाल में कहीं भी दे दो, उससे काम चल जाएगा। वह जमीन नहीं मिलती है। इसमें बड़ी व्यापक धांधली चल रही है। आज जूट मिलों की हालत यह है कि श्रीरामपुर के एमपी बहुत मुखर होते हैं। इनके क्षेत्र में बहुत दिनों से तीन कारखाने बंद हैं। सरकार उन कारखानों की जमीनें बेच रही है। पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की सात जूट मिलें थीं, जिनमें से तीन जूट मिलें मेरे क्षेत्र में हैं। मैं आपके माध्यम से इस गवर्नमेंट से यही कहना चाहूंगा कि उन जूट मिलों का ऑक्शन कर के यदि जूट मिलें चालू हो जाएं तो श्रमिकों का भला होगा। आज पूरी दुनिया में जूट के कपड़ों की जरूरत है। इससे पूरी दुनिया में भारत के प्रधान मंत्री का जो मैसेज जाएगा, उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद।

SHRIMATI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Respected Speaker, Sir, it is a great pleasure that all the State Governments have initiated special model residential school for the upliftment of SC/ST students.

I suggest that the Central Government should also intervene in their education. It will help them to achieve more in their life. I suggest the Government to start model residential school for SC/ST students with the standard of Kendriya Vidyalaya.

Sir, my Alathur constituency, with large number of SC/ST population, is the correct destination for such a pilot project, especially in Nelliampathy Grama Panchayat. It has a huge number of backward communities and good atmosphere. I will request the Government to take up this matter for immediate consideration.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री/श्रीमती राम्या हरिदास द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती भावना गवली (पाटील) (यवतमाल-वाशिम) : स्पीकर सर, धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं यहां बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाहूंगी। महाराष्ट्र में किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मदद देने की बहुत आवश्यकता है।

(1325/KDS/AK)

हम देख रहे हैं कि वहां पर सर्वे तो हो रहे हैं और उसके बाद घोषणाएं भी हुई हैं। घोषणाएं होने के बाद भी जो निर्णय आना चाहिए, जो मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, वह मुआवजा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। राज्यपाल महोदय का शासन है और इससे पहले जो सरकार थी, उसने भी घोषणा की थी कि सारे किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हमारे पक्ष प्रमुख ठाकरे साहब जी ने भी पचीस हजार रुपये का मुआवजा मिले, ऐसी मांग की थी। उनकी तो मंशा है कि किसानों का पूरा कर्ज माफ हो, लेकिन वह कर्जा माफ करना है तो सरकार बनानी पड़ेगी। हम तो कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री शरद पवार जी की तरफ से आशा रखते हैं कि सरकार बने किसानों की समस्याएं हल हों। ... (व्यवधान)। मैं यह भी बोलना चाहती हूँ कि यह समस्या हमें हल करने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। राज्यपाल महोदय जी ने जो निर्णय लिए हैं, उसे तुरन्त लागू किया जाए। स्पीकर सर, अभी दो मिनट नहीं हुए हैं। कृपया दो-चार सेकेंड मुझे और दे दीजिए। आज किसानों की यह स्थिति है कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, वे साहूकारों से कर्जा ले रहे हैं। अगर यह स्थिति बनी रही तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी खरीफ की फसल पूरी नष्ट हो गई है। रबी की फसल के लिए उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। अतः सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले, यह मेरी मांग है।

श्री प्रसून बनर्जी (हावड़ा) : थैंक्यू सर, क्या मुझे बोलना है?

माननीय अध्यक्ष : जी, मैं इसकी इजाजत देता हूँ।

SHRI PRASUN BANERJEE (HOWRAH): Sir, I thank you for giving me this chance to raise a very serious matter. ...(*Interruptions*). I am from the Howrah Constituency where there is Shalimar Station. उससे संतरागाछी स्टेशन तक चार लेवेल क्रॉसिंग हैं। 30 साल से 50 साल तक का कोई भी मेडिकल केसेज आते हैं, तो उधर डेथ हो जाती है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया था कि एक अंडरपास होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एम्बुलेंस जाने के लिए एक अंडरपास होना चाहिए। शालीमार से संतरागाछी तक चार लेवेल क्रॉसिंग हैं। इस कारण सभी को तकलीफ हो रही है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप माननीय मंत्री जी से बोलें। मैंने इधर चार बार बोला है। इससे सबकी तकलीफ दूर होगी। थैंक्यू सर।

श्री बी. बी. पाटील (जहीराबाद): सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा संसदीय क्षेत्र जहीराबाद है, जो कि तेलंगाना राज्य की सीमा पर स्थित है। एक तरफ से कर्नाटक स्टेट तथा दूसरी तरफ से महाराष्ट्र स्टेट आता है। कर्नाटक स्टेट का बीदर जिला और महाराष्ट्र स्टेट का नांदेड़ जिला से लगे होने के कारण हमारे किसान वहां पर खाद, बीज की खरीद करने या अपनी पैदावार को बेचने के लिए उधर ही जाते रहते हैं। इसके अलावा शिक्षा, अस्पताल, शॉपिंग के लिए भी वहां जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इन दो राज्यों से इंटरस्टेट कनेक्टिविटी हो जाने से हमारे लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। मैं आपसे इतनी विनती करता हूँ। थैंक्यू।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, BSNL is an erstwhile telecommunication company started in the early 2000s. Now, one lakh employees of BSNL have been denied their basic salary. About seven people have already committed suicide in the State of Kerala, and around 50,000 employees have been forced to take VRS in this company. Almost, the entire system of BSNL has been ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वीआरएस स्वेच्छा से ली जाती है।

श्री हिबी इडन (एरनाकुलम): सर, यह दो हजार करोड़ डिविडेंड देने वाली कंपनी है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को यह सरकार पूरी तरह से खराब करने की कोशिश कर रही है। कल मैंने अखबारों में पढ़ा था कि All the profit-making PSUs have been hampered for the interest of corporate companies. The Government has granted waiver to private companies for paying outright for the spectrum waves also.

(1330/SPR/MM)

This is a very serious business. BSNL employees have to be protected. उनकी बाकी सैलरी भी पे करनी है। The policy of the Government is for helping the corporate companies. ...(*Interruptions*) So, I would request the Government to take a creative stand on protecting the public sector undertakings of this country. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री हिबी इडन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं किसानों की आय दोगुना करने का हमारी सरकार का जो लक्ष्य है, उसी के संदर्भ में निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी-अभी हमने गांधी संकल्प यात्रा की तो मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों की स्थिति का आकलन करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा था। हमने 86 गांवों में किसानों की स्थिति का लक्ष्य का आकलन किया। वहां परम्परागत खेती पूर्णतया घाटे का सौदा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि केन्द्र सरकार के बागवानी मिशन योजनाओं को अधिक धन आबंटन हो और इनकी निगरानी बहुत अच्छे से की जाए। राज्य सरकारों के माध्यम से बागवानी मिशन में कार्यरत कर्मचारी किसानों को न तकनीकी ज्ञान देते हैं और न ही उनसे सहयोग करते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों को भी क्रियाशील करना अत्यंत आवश्यक है। यात्रा के दौरान किसानों ने मांग की कि उनके क्षेत्र में नीबू, आंवला, बैर, अमरूद आदि की बहुत अच्छे से पैदावार हो सकती है और इससे काफी अच्छी मात्रा में उनको धन भी प्राप्त हो सकता है। भूमि की उर्वरा शक्ति भी इन पौधों के लिए अनुकूल है। जल की कमी के बावजूद भी ये फसलें पैदा की जा सकती हैं। राज्य सरकार की उदासीनता के चलते किसानों की सरकारी योजनाओं को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि एक तरफ पौधा रोपण से पर्यावरण तो शुद्ध होगा ही, लेकिन किसानों की आमदनी भी चौगुनी हो सकती है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार द्वारा बागवानी मिशन पर पूरा ध्यान दिया जाए।

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए जिले वार फूड पार्क खुलवाई जाए। जिसमें किसान अपनी फसल को नजदीक और अच्छे दाम में बेच सके। अभी हरियाणा में दो फूड पार्क बनाने की योजना चल रही है। जिसके बनने में लगभग 5-7 साल लगेंगे। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि फूड पार्क को बढ़ावा देने और जल्दी खोलने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए और प्राइवेट कम्पनियों से फूड पार्क खुलवाया जाए।

वेयरहाउस के लिए सब्सिडी व फसल के रखरखाव के लिए एफसीआई और हेफेड के लिए जितने पैसे दिए जाते हैं, उतने पैसे किसान को डायरेक्ट अपनी फसल के रखरखाव के लिए दे दिए जाएं ताकि किसान अपनी फसल को अपने घर में स्टोर कर सके और जब भी सरकार को जरूरत हो किसान से फसल को ले ले। इसके लिए किसान को चार सौ रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए। किसान को आधा पैसा पहले और आधा बाद में दिया जाए। इसके दो फायदे हैं एक तो फसल सुरक्षित रहेगी और दूसरा किसान की आमदनी बढ़ेगी। किसान के दाने-दाने को एमएसपी पर खरीदा जाए। अभी तक सिर्फ 20-25 परसेंट फसल को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और किसान अपनी फसल को कम दाम में बिचोलियों को बेच देते हैं। जिसका नुकसान किसान को हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सभी राज्य सरकारों को इसके लिए गाइडलाइंस जारी की जाएं। पानी की बचत के लिए सिंप्रिक्लिंग सिंचाई की जगह ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए। सिंचाई के लिए जो सब्सिडी

दी जाती है उसे ज्यादातर एजेंसी वाले खा जाते हैं। मेरा सुझाव है कि ड्रिप सेट को किसान कहीं से भी खरीदे उसके लिए सब्सिडी किसान को मिले। धन्यवाद।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): अध्यक्ष महोदय, मैं आज पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र की बात सदन में रखना चाहता हूँ। पासपोर्ट आज एक व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है जो सिर्फ उसकी विदेश यात्रा तक ही सीमित नहीं है। बल्कि उसकी भारतीय नागरिकता का भी सबसे बड़ा पहचान पत्र है। वर्ष 2014 से पहले इस देश में कुल 77 पासपोर्ट केन्द्र थे। उसके बाद वर्ष 2017 में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ, जिसमें विदेश मंत्रालय डाक विभाग के सहयोग से देश के सभी प्रधान डाक घरों में 291 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। इसके तहत लगभग हर जिले में कम से कम एक पासपोर्ट केन्द्र होने की बात कही गयी। इसी सदन में केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए एक जवाब से यह पता चलता है कि इस साल के जुलाई महीने तक इस देश में 37 पासपोर्ट कार्यालय, 93 पासपोर्ट सेवा केन्द्र एवं 412 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र कार्यरत हैं। मेरे लोक सभा चुनाव क्षेत्र में डोम्बिवली एमआईडीसी में पासपोर्ट सेवा केन्द्र मंजूर किया गया था, लेकिन पिछले एक साल से वहां सेवा शुरू नहीं हुई है। कारण यह बताया जाता है कि पासपोर्ट सेवा केन्द्र शुरू करने के लिए तीन सौ स्कवेयर फीट जगह जरूरी है, लेकिन मेरे यहां सिर्फ दो सौ स्कवेयर फीट जगह है। इसके लिए मैंने बहुत बार मंत्रालय से पत्र व्यवहार भी किया। मैंने कहा कि एमआईडीसी के पास ऑफिस के आस-पास खाली जगह है, वहां से हमें पांच सौ स्कवेयर फीट की जगह मिल सकती है।

(1335/GG/UB)

एमपीलैंड्स से किया जा सकता है या खुद मंत्रालय इसके लिए जमीन बांध दे। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जल्द से जल्द इसकी परमिशन मिले और जल्द से जल्द पासपोर्ट सेवा केन्द्र शुरू हो।

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान 'आयुष्मान भारत योजना' की तरफ दिलाना चाहता है। यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें करीब 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद भी देता हूँ। दस करोड़ परिवारों को अब तक 'आयुष्मान योजना' के गोल्डन कार्ड्स जारी हुए हैं। इसके तहत पांच लाख रुपये तक का इलाज फ्री है। इस योजना में जो अस्पताल चिह्नित हैं, उनमें सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पताल भी हैं। निजी अस्पतालों में बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, जिनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है, हृदय रोग है, किडनी की बीमारी है, इनमें ज्यादा इलाज होता है। जैसे कैंसर में कीमो थेरेपी होती है, शायद वह आयुष्मान योजना में कवर्ड नहीं है। इसी तरह से उसमें ब्रेस्ट कैंसर भी नहीं है। ये सभी जानलेवा बीमारियां हैं। इस योजना में इन जानलेवा बीमारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

दीपावली के दिन हम लोगों ने लाभार्थियों के साथ चाय पी थी। ये सारी चीजें तब सामने आई थीं। माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर इस तरह के जो सभी तरह के लाभार्थी हैं, उनके साथ बैठ कर उनकी समस्याओं को जानने का निर्देश हुआ था। तब ये मामले सामने आए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें और इन जानलेवा बीमारियों को इस योजना में जोड़ने का काम करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा एवं डॉ. मनोज राजोरिया को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR): I thank you, Hon. Speaker Sir, for giving me the opportunity to raise an important matter of urgent public importance.

Sir, I want to draw the attention of the Central Government towards the screw industry existing in Amritsar since pre-independence times. Till 2010, this industry had 500 to 600 units in Amritsar. However, China is dumping their screws in our market. Due to Chinese imports, Amritsar now has only 100 screw units. In China, raw material is cheap, labour is cheap and the Chinese Government encourages its screw industry. However, our raw material is expensive. So, we have not been able to successfully compete with China in this sector. We had to import raw material. But big industrial houses got these imports cancelled.

Sir, in 2014, the 'Make in India' slogan gave some hope to this industry. But GST was increased from 6.8% to 18%. Whatever was being manufactured, shut its shop. So, I urge upon the Central Government that import duty on screws imported from China should be either increased or imports of Chinese screws should be banned. Or else, the GST on Ch-83 items should be reduced to 5% so that this industry can be revived and saved. This screw industry of Amritsar had been set-up in pre-independence times and it supplies screws to entire India. So, the need of the hour is to save this industry from closure and extinction. Thank you.

डॉ. राजदीप राय (सिल्वर): स्पीकर महोदय, मैं एक बहुत ही संगीन विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारा पड़ोसी राज्य बंगलादेश है। हालांकि बंगलादेश के साथ हमारे राजनयिक संबंध काफी अच्छे हैं। लेकिन बंगलादेश में आज के दिन भी अल्पसंख्यकों – हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्धों पर अत्याचार हो रहे हैं ये और आए दिन अखबारों की हैड लाइंस बनाते

रहते हैं। कुछ दिन पहले भी एक उभरते हुए वकील, जो कि एक्टिविस्ट थे, उनको अंडर डिटेंशन, अंडर घुस कर मारा गया। यह सब सोशल मीडिया में भी आया था। कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा और नवरात्रि के पर्व पर भी माइनोरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हुआ है। बहुत जगहों से हमको खबर मिली है कि पूजा आदि बंद हो रखी थी। मेरी आपसे और सरकार से गुजारिश है कि ये सब इनता सीरियस मैटर है to take it up on a serious note. हालांकि हमारे प्रधान मंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि 'इंडियन-डायस्पोरा, इंडियन-डयस्पोरा'। उसमें कोई कार्यवाही शुरू की जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा।

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): Sir, my issue pertains to the recruitment in the Central Bank.

(1340/KMR/KN)

The Central Bank of India had issued advertisements on 9-11-2012 and 11-11-2012. Subsequently, candidates were called for interview on various dates in January and February 2013. After the interviews, successful candidates were issued appointment letters and were asked to report to duty. This process was conducted for different regions throughout the country. For Mumbai Zone, the process was held for three zones – South Mumbai, North Mumbai and Thane. The candidates in the Thane region were allowed to join the Bank but candidates from South Mumbai and North Mumbai were not allowed to join even after getting appointment letters. In the same case, candidates from Chhattisgarh region were recruited. While in majority regions candidates had already joined the Bank, still the Bank had issued a public notice dated 5-7-2014, 6-7-2014 and 8-7-2014 cancelling the recruitment process undertaken by the authorities for reasons unknown.

When the candidates from other Zones have already joined the Bank, why are the candidates from South Mumbai and North Mumbai being discriminated against? I understand from reliable sources that if the Finance Ministry gives directions to the Central Bank of India, they may reconsider the recruitment process in respect of candidates from South Mumbai and North Mumbai.

I would earnestly request the Minister of Finance, through this House, to reconsider the matter afresh and permit candidates from South Mumbai and North Mumbai to join the Bank. Thank you.

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे पिताजी स्व. नारायण कृष्ण शेजवलकर जी

छठी, सातवीं लोक सभा के सदस्य थे। मेरा सौभाग्य है कि आज इसी सदन में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है।

महोदय, ग्वालियर देश का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर होने के साथ-साथ व्यापारिक, औद्योगिक एवं शिक्षा का प्रमुख केन्द्र भी है। गत दिनों ग्वालियर से हैदराबाद, जम्मू, बंगलुरु व कोलकाता हेतु स्पाइस जेट की उड़ानें प्रारम्भ की गई थीं। उसी समय स्पाइस जेट के चेयरमैन श्री अजय सिंह जी ने ग्वालियर से पुणे हेतु फ्लाइट शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु आश्वासन किया था, लेकिन अभी तक यह सुविधा ग्वालियरवासियों को प्राप्त नहीं हो सकी है।

इस फ्लाइट के प्रारम्भ होने से ग्वालियर के उद्योगपति, व्यवसायी एवं आईटी सेक्टर से जुड़े अनेक युवक-युवतियां लाभावित होंगे। ग्वालियर से पुणे नियमित फ्लाइट की व्यवस्था जल्द से जल्द करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्वालियर से पुणे की रेल यात्रा असुविधाजनक होने से काफी लम्बे समय से पुणे फ्लाइट की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उपरोक्त सेवा ग्वालियरवासियों को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ऐसा आग्रह मैं सदन और आपके माध्यम से सरकार को करना चाहूंगा।

श्री चन्द्र सेन जादौन (फिरोजाबाद): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अति आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। मेरे लोक सभा क्षेत्र फिरोजाबाद की टुंडला विधान सभा क्षेत्र में मण्डल नारखी व मण्डल टुंडला पानी की समस्या से अत्यधिक परेशान है। यहाँ का पानी खारा है तथा यहां के बाशिंदे खारा पानी पीने के लिए बाध्य हैं। इन मण्डलों के 50-60 गाँव तो ऐसे हैं, जिनमें खारा पानी इतना कड़वा है कि कुल्ला करना भी असम्भव है। इस फ्लोराइड युक्त पानी को पीने से अधिकांश नर-नारियों की हड्डियाँ टेढ़ी हो गई हैं, जिससे वे चलने-फिरने में असमर्थ हैं। वे अपने दैनिक जीवन के कामकाज को भी सम्पन्न करने में असमर्थ हैं। यहां के बाशिंदे मीठे पानी की एक-एक बूंद पाने को तरस रहे हैं। मीठा पानी मीलों दूर से लाना पड़ता है। उनका अधिकांश समय पानी की व्यवस्था में ही लग जाता है और वह कृषि कार्य करने के बेशकीमती समय को यूँ ही बर्बाद करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। इस कारण उनके विकास की गति भी अति धीमी हो गई है। इसके साथ ही यहां पानी का जलस्तर अत्यधिक गिर गया है, जिससे हैंड पम्प ने पानी देना बंद कर दिया है। पानी की किल्लत के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है। विधान सभा क्षेत्र टुण्डला से सिरसा नदी व सेंगर नदी गुजरती है। ये दोनों नदियां वर्षों से सूखी पड़ी हैं। इन दोनों नदियों में पानी छोड़ने के कई बार प्रयास किए गए, लेकिन अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण हाथरस माइनर से पानी नहीं छोड़ा जा सका। अगर इन नदियों में हाथरस माइनर से पानी छोड़ दिया जाए तो कुछ हद तक पानी की समस्या हल हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से गुजारिश करता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र फिरोजाबाद की पानी की समस्या का शीघ्र निराकरण करें, जिससे यहां के बाशिंदे अपने नारकीय जीवन से बाहर आएँ, अमन-चैन का जीवन व्यतीत करें तथा खुशहाली का इजहार करें। धन्यवाद

(1345/SNT/CS)

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश में पेयजल की विकट समस्या है। गत वर्ष में प्रदेश के कई जिलों में सूखा पड़ा है तो कहीं अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि के समय वर्षा के पानी का समुचित भंडारण न होने के कारण सम्पूर्ण पानी व्यर्थ बह जाता है। अबकी बार बीसलपुर बांध के गेट 64 दिन तक खुले थे। वह पानी चम्बल नदी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चला गया।

महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि गत 20 वर्षों में 7 वर्ष, 2001, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016 और वर्ष 2019 में वर्षा हुई है और इसकी भंडारण क्षमता 38.70 टीएमसी है, जबकि उसमें पानी इतना आ जाता है और उससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है।

मेरा निवेदन है कि या तो बीसलपुर डेम की एक मीटर ऊँचाई बढ़ाई जाए, या वहाँ ईसरदा बांध है, वह बांध बनाया जाए ताकि पीने के पानी की समस्या हल हो सके। धन्यवाद।

श्री मितेश रमेशभाई पटेल (बकाभाई) (आनंद): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

जैसा कि आप अवगत होंगे कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधान मंत्री शिंजो आबे ने सितम्बर, 2017 में 508 किलोमीटर लंबे 12 स्टेशन वाले अहमदाबाद से मुम्बई के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की थी। इनमें से एक स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आनंद भी है। क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का इस सौगात के लिए आभार और धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट हेतु अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे की प्रक्रिया न्यायसंगत नहीं है। प्रोजेक्ट की वजह से जो उद्योग स्थान्तरित या नष्ट हुए हैं, उनकी पूरी जमीन अधिग्रहीत नहीं की जा रही है, जबकि भू-स्वामी पूरी जमीन देने को तैयार हैं। प्रशासन को जितनी जमीन चाहिए, वह उतनी ही जमीन ले रहा है, जबकि अधिग्रहण के चलते उद्योगों की पूरी जमीन खराब या नष्ट हो रही है। मेरा एक आग्रह है कि उद्योगों की पूरी जमीन ली जानी चाहिए।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि संबंधित प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि भूमि अधिग्रहण की वजह से खत्म हुए उद्योगों की पूरी जमीन अधिग्रहीत की जाए, जिससे भू-स्वामियों को उचित मुआवजा मिल सके। धन्यवाद।

SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Hon. Speaker, Sir, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, former Chief Minister of Tamil Nadu has created a unique scheme called Samathuvapuram, which means equality village. Under this scheme, model habitations were established with Government fund in rural areas where all the communities live with unity and brotherhood and share all basic infrastructure and amenities without any discrimination.

Each village has 100 houses and is subdivided into 40 houses for Scheduled Castes, 25 houses for Backward Castes, 25 houses for most Backward Castes, and 10 for other communities. To avoid caste discrimination, this village has one community hall for all communities, as well as a common burial ground. Now, there are 145 such equality villages in Tamil Nadu. It is an important model to end caste discrimination and to establish social justice. I request the Government, through you, Sir, to take steps to replicate this model in other parts of our country.

Thank you.

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Sir, Tandur, which comes under my constituency, which is 100 km away from Hyderabad, is considered as very backward. Tandur Tur Dal is world famous. Tandur is also famous for blue, green, yellow limestone, cement industries, and educational institutions, फिर भी यह बैकवर्ड कहा जाता है, क्योंकि लॉजिस्टिकली नॉट कनेक्टेड है। बशीराबाद जो ताण्डूर में है, साढ़े 6 बजे के बाद वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती है।

So, through you, Sir, I request the Railway Minister that Bangalore-Nanded Express, Hubballi-Secunderabad Express, Bidar-Yesvantpur Express, ट्रेन्स वहाँ रुके तो बहुत सारे यात्रियों और छात्रों को लाभ होगा और वे बहुत खुश होंगे।

We requested for a ROB at Tandur at Railway KM 70/7-9 on Secunderabad-Wadi section. इसका काम भी पाँच सालों से अब तक नहीं हुआ है।

(1350/RV/RK)

We had requested for the stoppage of Padmavathi Express, Garib Rath Express, Hussain Sagar Express and Palnadu Express at Tandur. यह अब तक नहीं हुआ है।

हमने इधर एक ई.एस.आई. हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की मांग की है। विकाराबाद जिले में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है।

आपके माध्यम से, I would request the Ministers concerned to please look into all these and see that Tandur is given a helping hand.

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

सर, 'पी.एम.-किसान' सम्मान योजना के माध्यम से किसानों को जो पेंशन दी जा रही है, उसमें मुझे लगता है कि हर एक सांसद का यह विषय हो सकता है। अगर 400 किसान इसके पात्र हैं तो उनमें से सिर्फ 150 किसानों को ही पेंशन का लाभ मिल रहा है। बाकी के किसानों के बारे में मैंने

डी.एम. से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने डेटा अपलोड किया है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से वह आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सम्माननीय कृषि मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि ऑनलाइन सिस्टम में जो कुछ कमियां हैं, वे दूर की जाएं और हर पात्र किसान को पीएम-किसान सम्मान योजना के माध्यम से जो पेंशन मिल रही है, वह पेंशन उनके खाते में जमा होती जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर को श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अनिल फिरोजिया - उपस्थित नहीं।

श्री राज बहादुर सिंह।

श्री राजबहादुर सिंह (सागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी खम्भे का शिकार हूँ। यहां से साफ दिखता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: मैं भी पाँच साल पोल के पीछे था।

श्री राजबहादुर सिंह (सागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में इन्दौर से हावड़ा तक एक क्षिप्रा एक्सप्रेस चलती है। मैं आपका ध्यान उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। वर्तमान में इसका परिचालन तीन दिनों - मंगलवार, गुरुवार और शनिवार - को होता है। यह मालवा और बुंदेलखण्ड को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण ट्रेन है। इस ट्रेन को सप्ताह में पूरे सात दिन चलाने की मांग हमारे क्षेत्र की जनता काफी लम्बे समय से कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान माननीय रेल मंत्री जी की घोषणा की ओर दिलाना चाहता हूँ। 16 अप्रैल, 2018 को भोपाल में आयोजित 63वें राष्ट्रीय रेल सप्ताह पुरस्कार कार्यक्रम में इस ट्रेन को पूरे सात दिन चलाने की घोषणा उनके द्वारा की गई थी। मगर, आज तक इस घोषणा पर अमल नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ट्रेन को सप्ताह के सातों दिन चलाया जाए।

श्री भोलानाथ 'बी. पी. सरोज' (मछलीशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर आपका ध्यान मछलीशहर, जौनपुर जिले के आरक्षित लोक सभा क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, मेरा लोक सभा क्षेत्र लगभग 22 लाख आबादी वाला क्षेत्र है, जो कि वाराणसी जिले के एक विधान सभा पिण्ड्रा मिला कर बना हुआ है, जो हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के लोक सभा संसदीय क्षेत्र के बगल का क्षेत्र है। हमारा लोक सभा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, जो कि अति पिछड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने मछलीशहर लोक सभा क्षेत्र के विकास के कार्य को न करके इसे अनदेखा किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां काफी हद तक विकास के काम हुए हैं।

महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने माध्यम से मछलीशहर सुरक्षित लोक सभा क्षेत्र का सर्वे कराएं, जिससे आप वहां की अनुसूचित जाति और गरीब मजदूर किसानों की समस्या से अवगत हो सकें।

(1355/PS/MY)

महोदय, मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप मछलीशहर (सुरक्षित) लोक सभा क्षेत्र को विशेष पैकेज दिलाने की कृपा करें, जिससे वहां के गरीब लोगों का पूर्ण रूप से विकास हो सके। धन्यवाद

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Hon. Speaker, Sir, certain incidents happened recently in Kerala, arose suspicion among general public regarding the credibility of governance of universities in Kerala.

Though universities are autonomous in nature, the Kerala Government is trying to politicise them. Mark moderation in the Mahatma Gandhi University is the latest incident of this kind. The State Higher Education Minister has influenced the University syndicate to grant extra marks after the results were announced. Granting extra marks after the results were published, is a violation of the rules. The syndicate is also granting marks directly without getting any instruction from the Academic Council. It is also a violation of rule. The Private Secretary to the Minister, who has no authority to take part in the proceedings of the University, was present in the meeting which took a decision to award extra marks.

In a similar case, an inquiry is going on in the Kerala University. In another case, the Minister directly issued an order to modify the preparation of question paper and conduct of examination. The Governor of Kerala summoned Vice Chancellor to the Raj Bhavan and asked them to report in this matter.

So, I urge upon the Government to make a CBI inquiry in this matter.

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के शिक्षकों के बारे में जो गंभीर विषय है, उसको मैं यहां उठाना चाहती हूं। 11 नवंबर से लेकर आज 21 नवंबर है, उधर 1,000 पैरा टीचर्स भूख हड़ताल का आंदोलन कर रहे हैं। अभी पांच लोगों की सिचुएशन गंभीर है और वे हॉस्पिटलाइज हैं। दो सालों में 100 पैरा टीचर्स की डैथ हुई, यह बिना ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है। वैस्ट बंगाल में लगभग 50,000 पैरा टीचर्स हैं। उनका जो अधिकार तथा इश्यू है, वह सरकार से मांग हैं। केन्द्र सरकार से जो पैसा उधर जाता है, उसको राज्य सरकार नहीं दे पाती है। वह पूरा का पूरा पैसा उनके ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) की जो कंपनी है, उधर चला जाता है।...(व्यवधान) इस विषय में बोलना चाहती हूं कि उधर शिक्षा देने के लिए जो गुरु हैं, अगर उनका भविष्य ठीक नहीं होगा, तो वे बच्चों को कैसा सपना दिखाएंगे? ...(व्यवधान)

*If you play with the future of the teachers, what will happen to the students? Teacher is the guru. His future should be secure. So I request you to look into the matter. ...(*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): I would like to know whether the State subject is allowed to be discussed now. ...(*Interruptions*)

Everyday she creates a problem. ...(*Interruptions*)

SHRI PRASUN BANERJEE (HOWRAH): It is unethical. It should be stopped. ...(*Interruptions*)

श्री सौमित्र खान (बिशनपुर): सर, मैं जो विषय उठा रहा हूँ, उसे तृणमूल सांसदों को भी सुनना चाहिए...(*व्यवधान*) आप उसे सुनिए। हम लोगों ने अभी चिट फंड बिल पास किया है...(*व्यवधान*) सर, मेरा विषय चिट फंड का है। अगर वे इसे सुनेंगे, तो भी चलेगा...(*व्यवधान*) हम लोगों ने चिट फंड बिल पास किया, लेकिन ...(*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।*) ने लॉटरी कंपनी खोल ली।...(*व्यवधान*) हर महीने में 300 करोड़ रुपये की लॉटरी कंपनी खुली।...(*व्यवधान*) इसको कौन परमिशन देता है? ...(*व्यवधान*) जो गांव से 300 करोड़ रुपये लूट रहे हैं।...(*व्यवधान*) हर महीने में 300 करोड़ रुपये लॉटरी में लूट रहे हैं। अभी चिट फंड बंद हो गया।...(*व्यवधान*) लेकिन लॉटरी का पैसा लूट रहे हैं। ...(*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।*) का राज चल रहा है।...(*व्यवधान*) देखिए, यह जो लॉटरी कंपनी खुली है, मैं लॉटरी कंपनी के अगेन्स्ट हूँ।...(*व्यवधान*) चिट फंड बंद हुआ, लेकिन वहां लॉटरी कंपनी खुली है।...(*व्यवधान*) एक ...(*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।*) के नाते लॉटरी कंपनी बंद होनी चाहिए।...(*व्यवधान*) बहुत सारी लॉटरी कंपनीज़ खुली हैं। सर, आपने मुझे बोलने नहीं दिया।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही पंद्रह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1400 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पंद्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1500/CP/SNB)

1503 बजे

लोक सभा पन्द्रह बजकर तीन मिनट पर पुनः समवेत् हुई।
(श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1503 बजे

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

Re: Need to organize a 'Krishi Mela' in Salempur parliamentary constituency, Uttar Pradesh

***श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर):** मेरा संसदीय क्षेत्र सलेमपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। गन्ना यहां की प्रमुख फसल है। सलेमपुर और इसके आस-पास बड़ी संख्या में चीनी मिल स्थित हैं। पूर्वांचल की भूमि उपजाऊ है। यहां अन्य फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन इस क्षेत्र की उर्वरा भूमि की इष्टतम क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है। किसानों को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में आधुनिक कृषि तकनीक के इस्तेमाल का महत्वपूर्ण योगदान है। समय समय पर कृषि विशेषज्ञों से किसानों को प्राप्त उचित मार्गदर्शन से भी कृषि पैदावार में वृद्धि होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सलेमपुर में प्रति वर्ष एक किसान मेला का आयोजन करने की कृपा करें। इससे इस क्षेत्र के किसानों को अनेक लाभ होंगे और कृषि पैदावार में कई गुना वृद्धि होगी। कृषि मेला में किसानों को अद्यतन कृषि तकनीक, उच्च कोटि के बीज, उपयुक्त उर्वरक के बारे में विशेषज्ञों की राय मिलेगी जो उनके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी किसान मेला बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। अतः इस संबंध में मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर में कृषि मेला का आयोजन करने की कृपा करें।
 (इति)

Re: Connecting Shillong to Dawki in Meghalaya

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): The Government of Meghalaya has a plan to connect the capital city, Shillong, to Dawki, a city lying on the border of India and Bangladesh, by upgrading and constructing a National Highway. The project is supposed to be funded by the Japan International Corporation Agency (JICA). The land acquisition for the same is in doldrums due to the defence land, which comprises only 1 percent of the total land requirement. I thus urge the Government of India to take prompt action in handing over the required defence land to the National Highways Authority of India without any delay. I am afraid that if we delay the land acquisition any further then the entire JICA fund may be cancelled. This would cause trouble to the people of Meghalaya who face heavy traffic jams on the city roads and national highways.

(ends)

Re: Need to increase the percentage of reservation for SCs

SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): The Scheduled Caste population is constantly increasing. State Governments like Uttar Pradesh have included many numerically significant OBC Castes into the Scheduled Castes list recently.

So it is necessary to increase the percentage of reservation for SCs. By giving 10% reservation to EWS, the Centre has already flouted the 50% upper limit fixed by the Supreme Court. So, I request the Government to increase the percentage of reservation for SCs.

(ends)

Re: Including state highway Narsipatnam -Tuni road under Bharatmala Project

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): The road Narsipatnam — Tuni is an important State Highway and inter district connectivity road (Visakhapatnam to East Godavari District) connecting the Anakapalli Parliamentary constituency and the Araku Parliamentary constituency. People from the nearby 10 Mandals travel through this road to reach the railway station at Tuni. People use this road to transport the agricultural produce and the products obtained from agency areas to nearby market.

In view of the importance of the road, it is requested to include the above State highway — Narsipatnam — Tuni road for a length of 42 Km under the Bharatmala Project. (ends)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि आइटम नंबर 12, जो मनीष तिवारी जी द्वारा वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में है, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन कुछ चर्चा शेष है। पहले यह आइटम लेकर इसे कनक्लूड कर लिया जाए, उसके बाद दूसरा आइटम लिया जाए। मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): ठीक है। अब हाऊस नियम 193 के अंतर्गत वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के विषय पर चर्चा जारी रखेगा।

डॉ. संजय जायसवाल जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

(1505/NK/RU)

वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के विषय में चर्चा – जारी

1505 बजे

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदया, मैंने वायु प्रदूषण की चर्चा में जो मामला उठाया था, इसमें इंडिया बनाम गांव या गांव बनाम शहर की चर्चा नहीं होनी चाहिए। कल ही आप दिल्ली की स्थिति देखिए, कल दिल्ली सबसे प्रदूषित दिनों में से एक थी। उसका कारण यह था कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। यह कहना कि पंजाब के किसान पराली जलाते हैं, हरियाणा के किसान पराली जलाते हैं इसलिए प्रदूषण होता है। कल जब हवा बिल्कुल रुकी हुई थी तो दिल्ली का प्रदूषण स्तर बहुत ज्यादा था, यह अपने आप में बताता है कि दोष हम सभी में है लेकिन हम दूसरों में गलतियां ढूंढ रहे हैं।

कल मैंने जिन समस्याओं की चर्चा की और भारत सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, उन सभी की चर्चा मैंने परसों की थी। आज मैं केवल इसकी चर्चा करूंगा कि क्या-क्या कदम उठाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा जिससे हमें इस वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज से मुक्ति मिल सके। अभी तुरंत क्या करना चाहिए। इसके लिए मेरा अनुरोध रहेगा। ... (व्यवधान) माननीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी को ऑथराइज किया गया है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: राज्य सभा में भी इसी सब्जेक्ट की चर्चा चल रही है।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदया, वहां भी एयर पोल्यूशन ही चल रहा है। एयर पोल्यूशन कितना प्रमुख है। ... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): एयर पोल्यूशन नहीं चल रहा है उसके खिलाफ चर्चा चल रही है।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदया, जी नहीं, उसी की चर्चा चल रही है। आज आप सौ प्रतिशत उपस्थित हैं, परसो एक भी उपस्थिति नहीं थी। आज आपकी पार्टी की सौ प्रतिशत उपस्थिति है इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि 70-80 करोड़ रुपये अपने प्रचार में खर्च करती है, अगर उसके बदले सारे हॉट स्पॉट पर वायु टॉवर बना दे तो उससे बहुत ज्यादा हवा साफ होगी, यह मेरा आपसे अनुरोध रहेगा।

श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदया, हवा केजरीवाल जी नहीं बनाते हैं।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदया, मैं प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने वॉटर स्प्रीकल्स गाड़ियों की व्यवस्था की है इससे वायु प्रदूषण कम होता है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि पिछले पन्द्रह वर्षों से क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी बहुत साधारण चीज हो गई है। हम लोगों ने बीडिंग ओलम्पिक्स में देखा कि बारिश नहीं हुई तो उसके पहले ही बारिश करा दी गई। भारत सरकार बड़े शहरों में जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक दिल्ली के लिए क्लाउड सिडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए। जो उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं उनमें सबसे जरूरी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। ईंट के भट्टे पर टेक्नोलॉजी के लिए

सब्सिडी दें या कृषि अपशिष्ट से कागज बनाने का जो प्रोजेक्ट है, इन सभी चीजों पर ज्यादा सब्सिडी दें, उससे इस तरह की परियोजनाएं आंगी और प्रदूषण कम होगा। इसके लिए मैं एक साधारण उदाहरण देना चाहूंगा। सीएसआईआर ने वॉटरलेस क्रोम टेक्नोलॉजी पर बहुत बढ़िया रिसर्च किया है। अगर नदियों में सबसे ज्यादा प्रदूषण कोई करता है तो वह चमड़ा उद्योग करता है। सीएसआईआर की खोज है कि पानी का उपयोग किए बिना चर्म उद्योग को फायदा हो सकता है। इस पर केन्द्र सरकार को राज्य सरकार को सब्सिडी देने के लिए विचार करना चाहिए। हम सिविज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते चलें, यह निदान नहीं है। जो इंडस्ट्री प्रदूषण करते हैं उनको हम कैसे कम कर सकें, यही उसका निदान है।

मीथेन का उत्सर्जन विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। भारत में सबसे ज्यादा पशु है इसलिए सबसे ज्यादा मीथेन उत्सर्जन हमारे यहां से होता है। वायोगैसी फायर प्रोजेक्ट्स गरीब किसानों को अच्छे से लागू करा दें तो हमारी विदेशी मुद्रा का एलपीजी सिलेंडर का खर्च बचेगा और किसानों का एलपीजी खर्च भी बचेगा।

इतने दिनों से जैविक खाद की इतने दिनों से चर्चा चल रही थी। वर्मिग कम्पोस्टिंग को खाद बनाने में नार्मली तीन महीने लगता है लेकिन अगर बायोगैसीफायर लगते हैं तो उसके सलरी से केवल 15 दिनों में ही वर्मिग कम्पोस्ट तैयार हो जाता है।

(1510/SK/NKL)

इस चीज के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने गोवर्धन पर कितनी बार कहा है। माननीय धर्मेन्द्र प्रधान जी ने भी लोकसभा में जवाब देते हुए गोवर्धन की चर्चा की थी। एमएनआरई मंत्री श्री आर.के. सिंह जी भी मानते हैं कि यह बहुत ही अच्छी चीज है और इसे बढ़ावा देना चाहिए। मत्स्य, पशु पालन और डेयरी मंत्री गिरीराज सिंह जी तो इसे पर मास लैवल का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। मेरा माननीय जावड़ेकर जी से अनुरोध है, हमने पायलट प्रोजेक्ट दिया था कि एक साथ क्लस्टर में 25,000-30,000 बायो गैसीफायर्स लगें। नीति आयोग इसके लिए तैयार है। यह प्रपोजल नीति आयोग से पेट्रोलियम मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय से एमएसएमई यानी विभिन्न मंत्रालयों में घूम रहा है। मेरा अनुरोध है कि सभी मंत्रालयों से बात करके, एमएनआरई, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और खादी ग्रामोद्योग विभाग की सब्सिडी योजनाओं में सबको मिलाकर एक योजना बनाकर लागू कराएं जिससे हम मीथेन उत्सर्जन पर कमिटमेंट के अनुसार उत्सर्जन कम कर सकें।

हम 50,000 गैसीफायर्स की बात करते हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बांट देते हैं। इससे हर जिले में पांच से सात बायो गैसीफायर्स पड़ते हैं। सात बायो गैसीफायर्स अगर किसान बना भी लेता है, अगर एक रबर भी खराब होती है तो यह बंद हो जाता है। इससे किसान के पैसे भी डूबते हैं और सब्सिडी भी डूबती है। इसके लिए सैट्रिक एप्रोच करना पड़ेगा, जहां बड़े डेयरी के कोऑपरेटिव्स हैं, वहां ध्यान देना चाहिए, जब एक जगह ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, तभी बायो गैसीफायर्स का असर शुरू होगा।

राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बहुत अच्छी चीजें हुई हैं, जैसे नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान और नीति आयोग द्वारा ब्रीथ इंडिया फ्रेंड वर्क। इंड एयर का डैश बोर्ड बहुत बढ़िया है, मुझे इसे दो दिनों में

देखने का सौभाग्य मिला। यहां जितने रिसर्च हो रहे हैं, जितने भी इनपुट्स हैं, सबको इंड एयर में इकट्ठा कर दिया गया है, कोई भी इससे लाभ उठा सकता है, उपयोग कर सकता है।

गुजरात सरकार ने पार्टिकुलेट के लिए सूरत एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत की है, जो कम पॉल्यूशन फैलाते हैं, उनको बेचने की परमिशन होगी और जो ज्यादा प्रदूषित उद्योग हैं, खरीद सकते हैं। इससे जो उद्योग कम प्रदूषण कर रहे हैं, उनको अतिरिक्त आमदनी होगी। इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूँ।

झारखंड सरकार ने इस बार रेटिंग सब उद्योगों पर लागू की है, इसमें हर वर्ष एक नई गैस जोड़ी जाएगी। इससे पब्लिक में भी अवेयरनेस आती है कि अगल-बगल के उद्योग कैसे कम से प्रदूषण कर रहे हैं। इससे कम प्रदूषण करने वाले उद्योगों को विशेष रेटिंग मिल रही है, इससे भी फायदा होगा। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। हमारे पूर्वजों ने जितनी खूबसूरत धरती हमें दी है, हर मनुष्य को सोचना होगा कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को दें।

सिक्किम उदाहरण है, यहां दम्पति बच्चों की तरह पेड़ों को गोद लेते हैं, पेड़ों की रक्षा करते हैं, पेड़ों का बच्चे की तरह पालन करते हैं। पिछले वर्ष मुझे नर्मदा जी के ग्वारी घाट में जाने का मौका मिला था। आरती के बाद सभी से शपथ दिलाई जा रही थी कि हम नदी में कोई प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, इसे प्रदूषित नहीं करेंगे। इस तरह के जन आंदोलन की जरूरत है, तभी हम लोगों को सफलता मिल सकती है।

मैं बिहार सरकार को भी बधाई दूंगा कि जल, जीवन, हरियाली मिशन चलाया है और इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यह वायु प्रदूषण दूर करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह संभव भी है। वर्ष 1952 में लंदन स्मॉग दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण का उदाहरण था। आज लंदन में कुछ भी वैसा नहीं है। यहां हर व्यक्ति को सुधरना होगा, पूरी संसद को इसका प्रयास करना होगा।

मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराधा

इस लड़ाई में जो लोग भाग नहीं ले रहे हैं, जो लोग वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज पर काम नहीं कर रहे हैं, पूरी जनरेशन भविष्य में उन पर हंसेगी, नफरत करेगी कि यही 21वीं शताब्दी के लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी को गर्त में धकेल दिया। इस कलंक से बचने के लिए पूरी संसद को एक स्वर में, एक साथ उठकर काम करना होगा।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1515/MK/SRG)

1515 बजे

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय सभापति जी, प्लीज आप हेड फोन लगा लीजिए, ताकि आपको ट्रांसलेशन समझ में आ जाए क्योंकि मैं पंजाबी में बोलूंगा। मैंने पहले नोटिस दे दिया है।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): मुझे पंजाबी आती है।

***[श्री भगवंत मान (संगरूर):** Hon. Madam Chairperson, I rise to speak on a grave matter of much significance. Today, we are discussing "Air-pollution and Climate change" under Rule 193.

Ma'am, today, the current topic of utmost importance is the 'burning of stubble'. It is alleged that the burning of the stubble by farmers of Punjab, Haryana etc. has added to smoke and pollution woes in North India. माननीय सभापति जी मेरा एक सवाल है। Who encourages these farmers to sow such crops where stubble has to be burnt in the end? Our farmers can sow maize, pearl millet, sunflower, oilseeds and pulses. However, there is no marketing facility for these crops. Where will the farmers sell these crops? Who will purchase these crops? बाजरे की एमएसपी नहीं है। एमएसपी आपने उस फसल की दे रखी है, जिससे पराली पैदा होती है। These non-stubble crops do not have favourable 'Minimum Support Price'(MSP). Remunerative MSP has been given for rice and wheat. क्या इतने हेक्टेयर पर धान उगाया जाएगा और चावल की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो जाएगी? Farmers are encouraged to sow paddy and wheat where stubble has to be burnt. When there is a bumper production of paddy, the Government is very happy at this record production. However, this is bound to lead to record burning of stubble.

Madam, the farmers of Punjab should be given another option.]

पंजाब का किसान पराली जलाना नहीं चाहता। जब वह धुंआ उठता है तो सबसे पहले उसी के बच्चों के फेंफड़ों से धुंआ निकलता है। लेकिन, आप उसको कोई ऑप्शन तो दीजिए। MSP can be sowed. But, there is a huge difference of income when one sows paddy in one acre and when one sows maize in one acre. The farmers can be induced to sow maize. Then, there will be no stubble and no stubble-burning. हम कोई इल्लिगल फसल तो नहीं बीज रहे हैं। ये फसल बैन है, आपने क्यों बीज ली? आप क्या कर रहे हैं? चावल हम से ले रहे हैं और उसके बाद हम पर पर्चा काट रहे हैं। The food-grain provider is accused of being a criminal. So, do provide us better MSP for non-stubble crops.

* Original in Punjabi

वी.के.सिंह जी बैठे हैं। जनरल साहब नव गोविन्द सागर झील कितना पानी पंजाब एक धान के सीजन में धरती से निकाल लेता है। हमारा पानी 500-600 फीट नीचे चला गया और आने वाले दिनों में आशंका व्यक्त की जा रही है कि पंजाब मरुस्थल बन सकता है। हम तो दोनों तरफ से मारे गए। धरती के नीचे से भी मारे गए और धरती के ऊपर यदि हम चावल उगाते हैं तो हम पर पर्चे काटे जा रहे हैं। आप मुझे यह बताइए कि किसान का कसूर क्या है? आप हमें फसलों का बदल दे दीजिए। पंजाब की धरती इतनी जरखेज है, इतनी उपजाऊ है कि आप कुछ भी बो देंगे तो उग जाएगा। लेकिन, कोई अल्टरनेटिव तो दीजिए। सिर्फ ए.सी कमरों में बैठकर हरे रंग के पैन से आर्डर देने से नहीं चलेगा। मैं खुद भी जमींदार का बेटा हूँ। मैं खुद खेती करता हूँ। आप जो हैपी सीडर मशीनों की बात कर रहे हैं। वह इतनी महंगी है कि आम जमींदार के बस की बात नहीं है। उसके लिए बड़ा ट्रैक्टर चाहिए और बड़ा ट्रैक्टर भी जमींदार के बस की बात नहीं है। हम क्या करें? जमींदार खुद भी यह नहीं चाहता। सुखबीर सिंह बादल जो हमारे डिप्टी सीएम थे। वे एक डेलीगेशन लेकर यह पता करने चीन गए थे कि चीन पराली से बिजली कैसे बनाता है। कुछ भी नतीजा नहीं निकला। सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा, चीन घूमकर कर आ गए। चीन में पराली से बिजली भी बनती है। ... (व्यवधान) इसको इंधन के रूप में अपना लीजिए। लेकिन, हमें बता तो दीजिए, हम पर इतना जुल्म मत कीजिए। दशहरा, दीवाली और पराली ये सभी बीस-बीस दिन के अंतर पर आते हैं।

(1520/RAJ/RP)

दशहरा के 20 दिनों के बाद दिवाली और 20 दिनों के बाद पराली, सभी धुएं वाले हैं। अब दिवाली और दशहरा को कुछ नहीं कह रहे हैं, आप पराली को कह रहे हैं। अरविंद केजरिवाल ने इस बार दिवाली सी.पी. में लेजर से मनवा दी, लेजर वाले पटाखे चल गए। दुबई में जब फायरवर्क्स होता है तो लेजर वाले पटाखे चलते हैं, आप उसको नहीं रोक रहे हैं। अब धुआं भी जात-पात में आ गया। कृपया ऐसा मत कीजिए। पराली की बात हो गई, सरकार इस पर जो भी फैसला करेगी।

दूसरा, यहां बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं। अगर आपको अमेरिका, कनाडा में एक पेड़ काटना है तो आपको सिटी से इजाजत लेनी है। वहां सिटी बोलते हैं, यहां पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन बोलते हैं। वहां एक पेड़ काटने के लिए सिटी से इजाजत लेनी पड़ती है। आपको पहले उसी प्रजाति के 50 पेड़ लगाने पड़ेंगे, तब आपको एक पेड़ काटने की इजाजत मिलेगी, लेकिन यहां सरकार खुद उसे काटती है कि इस रोड को 18 फुट से 22 फुट करना है तो सभी पेड़ काट दो, पर सरकार का उन्हें लगाने का क्या प्रोग्राम है?... (व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): दिल्ली में पेड़ काटने की इजाजत दिल्ली सरकार देती है, एमसीडी नहीं देती है।... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): एमसीडी किसकी है?... (व्यवधान) यह दिल्ली को ही देश मान बैठे हैं, जो आता है, वह दिल्ली-दिल्ली करता है।... (व्यवधान) मैडम, जी इनको बैठाइए।... (व्यवधान) बीजेपी जी, आप आराम से बैठ जाइए।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर) : मैडम, मैं पानी का एक उदाहरण देता हूँ।

माननीय सभापति : जब आप अपना घर नहीं संभालिएगा तो दुनिया को कैसे संभाल लीजिएगा? आप बैठ जाइए। दिल्ली में जब कटता है, ऑर्डर दिया जाता है।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर) : मैडम, भाखड़ा नांगल से भाखड़ा नहर निकलती है और सतलुज नदी भी वही से निकलती है।...(व्यवधान) मैडम, हमारा सूबा पानी के नाम पर है। कृपया घंटी से थोड़ा परहेज करीए। भाखड़ा नहर का पानी नीले रंग का रहता है और सतलुज का पानी लुधियाना आते-आते काले रंग का क्यों हो जाता है, क्योंकि भाखड़ा नहर में पंजाब से कहीं पानी नहीं डाला जाता है, वह भाखड़ा नांगल से निकलती है। सतलुज नदी में बुड्ढा नाला एवं अन्य के द्वारा डम्पिंग की जा रही है। लंदन में टेम्स नदी है। वह बहुत प्रदूषित थी, क्योंकि उसमें सीवेज का पानी जाता था। उन्होंने वहां ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए और टेम्स नदी में सीवेज का पानी जाना बंद हो गया। आज टेम्स नदी लंदन की कमाऊ नदी है। वहां क्रूज चलती हैं। ऐसी सेम रीवर्स फ्रांस में है। उन्होंने भी अपने प्रदूषित नदी को भी कमाऊ नदी में बदल दिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बाबा सीचेवाल, बाबा सेवा सिंह, ऐसे वातावरण प्रेमी हैं, जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जाता है।

हम गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं। उन्होंने तो बहुत-सी वाणी रची है। अगर हम एक लाइन पर भी अमल कर लें तो पूरी दुनिया का क्लाइमेट बच सकता है। 'पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महता' पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माता का दर्जा, अगर तीनों दर्जे कायम रखे जाएं, तो पूरी दुनिया का क्लाइमेट बच सकता है।

(इति)

1524 बजे

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि नियम 193 के तहत आपने जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। जब आप ने दो दिन पहले नियम 193 के तहत अनुमति दी थी तो ज्यादातर लोगों ने सिर्फ दिल्ली की बात कही, जबकि इस समस्या से केवल दिल्ली ही परेशान नहीं है, बल्कि प्रदूषण की समस्या से देश के कई शहरों के लोग परेशान हैं।

(1525/VB/RCP)

हम जब एम.पी. बनकर आये थे, तो सोचा था कि बच्चों के एडमिशन यहीं कराएँगे। लेकिन यहाँ का प्रदूषण देखकर हमारे बच्चों ने कहा कि हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम जयपुर में ही पढ़ेंगे। हमारा एडमिशन दिल्ली में मत कराइए। एमपीज खुद डरने लगे कि दिल्ली में कैसे रहें। दिल्ली के साथ-साथ विश्व के दस सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली भी है। दिल्ली के साथ-साथ, कोलकाता, कानपुर तथा भारत के कई अन्य शहर हैं, जिनको सरकार चाहे तो प्रदूषणमुक्त कर सकती है। मेरे से पूर्व बोलने वाले साथी सांसदों ने भी एक बात कही थी कि निश्चित रूप से हमें पर्यावरण को लेकर एक बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। पर्यावरण को नियंत्रित करने वाले कारकों में से एक जलवायु है। जलवायु से प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जीव-जन्तु आदि प्रभावित होते हैं।

मैंने कल एक साम्भर लेक से संबंधित एक मामला उठाया था। यह एक बड़ी लेक है, जिसमें नमक का उत्पादन होता है। यह नागौर और जयपुर के बॉर्डर पर है। वहाँ 15 हजार पक्षी मर गये, जिनमें साइबेरियन सारस भी थे। उसका मुख्य कारण प्रदूषण ही था।

जलवायु मानव की मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। मानव पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में जलवायु सर्वाधिक प्रभावशाली है, क्योंकि यह पर्यावरण के अन्य कारकों को भी नियंत्रित करती है।

मैं एक रिपोर्ट के हवाले से बताना चाहता हूँ कि वैश्विक तापमान का सबसे स्पष्ट और सर्वव्यापी एवं भयंकर दुष्परिणाम वायुमंडल का निरन्तर गर्म होते जाना है। वर्षों के गहन अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी का ताप निश्चय ही बढ़ रहा है। 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक पृथ्वी के ताप में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई है। यदि यही हालात रहे, तो हर दशक में पृथ्वी के ताप में 0.2 से 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।

हम सबको मिलकर इस देश की चिन्ता करनी होगी, मानव जाति की चिन्ता करनी होगी। यह देश की राजधानी है। पिछले तीन-चार सालों से लगातार दिल्ली जिस तरह से प्रदूषण की ओर बढ़ रही है, यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। जहाँ से देश की सरकार चलती है, अगर वही शहर प्रदूषणमुक्त नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरे शहर प्रदूषणमुक्त हो जाते होंगे।

इसके बारे में हम लोग यह कहें कि केवल पराली जलाने की वजह से ही प्रदूषण हो रहा है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जलवायु परिवर्तन पर कई साधियों ने अपनी-अपनी बातें रखीं। आज बढ़ते वाहनों की संख्या सहित कई अन्य कारण हैं, जिनसे प्रदूषण बढ़ता है। दुर्भाग्यवश केवल किसानों को ही पराली जलाने के लिए जिम्मेदार बताकर प्रदूषण का कारण बता दिया। पराली से मात्र तीन-चार पर्सेंट प्रदूषण होता है।

अभी मेरे से पूर्व पंजाब के सांसद ने कहा था कि हमारा डेलीगेशन चाइना गया, तो पता चला कि वहाँ पराली से बिजली का उत्पादन होता है। हरियाणा और पंजाब में जब धान की पराली जलायी जाती है, उससे पहले ही दिल्ली सरकार अगर हरियाणा और पंजाब की सरकार को निर्देशित करे और पराली को किसानों से खरीदकर उसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन में करे। इससे निश्चित रूप से बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा। ... (व्यवधान)

दिल्ली-एनसीआर में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको यहाँ से बाहर स्थानांतरित किया जाए। गाजीपुर-दिल्ली बाइपास पर एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है, जिसकी वजह से भी दिल्ली प्रदूषित हो रहा है। मेरा यह मानना है कि इसके लिए हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मानव जाति को बचाने के लिए काम करना होगा। निश्चित रूप से, इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी और वन एवं पर्यावरण मंत्री जी चिन्तित हैं।

दिल्ली के प्रदूषण के संबंध में 'आप' पार्टी के नेताओं के बयान अखबारों में रोज आते हैं। कहीं-कहीं वे इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी पूसा एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डी-कम्पोजर गोलियाँ बनाई है। इससे पराली को जलाये बिना खाद बनाया जा सकता है। सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाले, जिससे किसान को पराली जलाने की नौबत ही न आए ताकि किसान को किसी भी दृष्टि से प्रदूषण के लिए जिम्मेदार न बताया जाए।

अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, तो पाली-बाड़मेर के बालोतरा और जयपुर के आसपास के कई जिलों में उद्योगों से बहुत मात्रा में प्रदूषण होता है, इससे खेती पर भी असर पड़ा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि केवल किसान को ही जिम्मेवार ठहराना गलत है।

विश्व की जनसंख्या में तेजी से होती बढ़ोतरी ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक-से-अधिक शोषण किया है। वनस्पति और हरियाली से रहित बड़े-बड़े शहर बढ़ते औद्योगिकरण के कारण बंजर हो रहे हैं। यह भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। हमें मिलकर जलवायु प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं, उन्हें कम करना होगा।

(1530/PC/SMN)

सभापति महोदया, मेरा एक निवेदन राजस्थान का है। लुधियाना से फैक्ट्रियों का जो पानी निकलता है, वह पूरे राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से पंजाब, गंगानगर, हनुमानगढ़ के लिए जाने जाने वाले पीने के पानी में मिल जाता है। वहाँ सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं। वहाँ की एक ट्रेन को कैंसर ट्रेन का नाम दे दिया गया है।

मैं हमारे राजस्थान से बने जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन करूँगा और प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूँगा, क्योंकि राजस्थान की आधी आबादी और पंजाब की पूरी आबादी उससे प्रभावित है। उन फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है, जो रसायन है, उसको इंदिरा गांधी कैनाल में पड़ने से रोका जाए और नए संयंत्र बनाकर, कचरे का संसाधन कर के बिजली भी बनाई जाए और उसका उपयोग किया जाए। इस मानव जाति को बचाने के लिए सब लोग मिलकर, पार्टियों से ऊपर उठकर ऐसा काम करें।

इस मामले पर अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूँगा, 193 पर जो पक्ष-विपक्ष की मांग थी, उस पर अध्यक्ष जी ने चर्चा भी कराई और दो दिनों तक सारी पार्टियों को खुलकर बोलने का मौका भी दिया। आपने हमें भी मौका दिया है। हम आपके साथ हैं और आगे भी इसी तरह साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।

(इति)

1531 बजे

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत आभारा सारी दुनिया के अंदर या पूरी मानवता के सामने आज दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक समस्या पर्यावरण की है और दूसरी आतंकवाद की है। दोनों समस्याओं पर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री ने जिस प्रकार इनिशिएटिव लेकर दुनिया में नेतृत्व करने का काम किया है, उसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ।

सभापति महोदया, आजकल के जमाने में, विज्ञान और विकास की दौड़ में मनुष्य क्या करता चला गया कि वह यह भूल गया कि वह पीछे क्या छोड़ता जा रहा है। जब देश का संविधान लिखा गया, देश के संविधान में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या जमीन का प्रदूषण क्या होता है, इसके बारे में कोई अनुच्छेद नहीं है। जिस प्रकार इन्डस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, विकास के नाम पर जिस प्रकार सुख-सुविधाओं के लिए अधिक से अधिक गाड़ियां, एसी, जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, उसके लिए रसायनिक उर्वरक, पेस्टिसाइड और इन्सेक्टिसाइड का प्रयोग होने लगा। दुनिया ने 1960 के दशक में यह महसूस किया कि हम सब लोगों को सचेत और जागरूक होने की जरूरत है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले वर्ष 1962 में अमेरिका में एक किताब लिखी गई, जिसका नाम था – 'साइलेंट स्प्रिंग'। राशेल कार्सन ने यह किताब लिखी थी। जिस प्रकार अमेरिका में रसायनिक उर्वरक और इन्सेक्टिसाइड से जो दुष्परिणाम आ रहे थे, जिस प्रकार से वायु प्रदूषित हो रही थी, उस पर किस प्रकार पाबंदी लगाएं, इस पर उन्होंने पहली बार आवाज उठाई।

वर्ष 1972 में दुनिया के स्तर पर स्टॉकहोम कांफ्रेंस आयोजित की गई है। उसमें गंभीर चर्चा हुई और दुनिया की सरकारों ने निर्णय लिए और जगह-जगह कानून बनाने शुरू किए गए। वर्ष 1970 में सबसे पहले भारत के संविधान में परिवर्तन लाया गया और पहली बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम पर आर्टिकल-48 भारतीय संविधान में इन्क्लूड किया गया। Article 48A of the Indian Constitution states that:

“The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.”

यह वर्ष 1970 में आया सबसे पहला संशोधन था। एक संशोधन यह आया कि आदमी की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो अनिवार्य ड्यूटीज़ हैं, देश के नागरिक के अनिवार्य कर्तव्य हैं, उनके लिए आर्टिकल-51 के माध्यम से कहा गया। Article 51A(g) of the Indian Constitution states that:

“It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures.”

महोदया, इसके बाद वर्ष 1974 में दुनिया में एक वर्ल्ड फूड कांफ्रेंस हुई।

(1535/KDS/MMN)

एक तरफ बढ़ती जनसंख्या थी, जिसका पेट कैसे भरा जाए और दूसरी तरफ जो रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड की दुनिया चल रही थी, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। फिर उस पर वर्ष 1976 में एक किताब लिखी गई-“How the other half dies.” मेरे माननीय सदस्यों ने शायद इसे नहीं पढ़ा होगा। उसमें लिखा था कि अमेरिका के बाहर किस प्रकार की कृषि हो रही है और भारत में किस प्रकार की कृषि की शिक्षा आई, किस प्रकार की रिसर्च आई और जो ऑर्गेनिक कृषि, जिसको हम जैविक खेती कहते हैं, उसे किस प्रकार से खत्म किया और किस प्रकार से हमारे किसानों को नुकसान हुआ। यह पढ़ने लायक किताब है। उसके बाद हमारे देश के अंदर एयर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट पर काम करना शुरू किया गया। जब से देश में माननीय मोदी जी की सरकार आई, तो देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रदूषण कम करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए।

सभापति महोदया, मैं कुछ समय चाहता हूँ। मैं किसी भी बात की पुनरावृत्ति न करते हुए इस बात को बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड, क्लोरो फ्लूरो कार्बन पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं और ओजोन पर्त, जिसको हम अंग्रेजी में ओजोन लेयर बोलते हैं, वह कैसे पतली होती है, 20 से 30 किलोमीटर की रेंज का हमारा जो वायु मण्डल है, वह कैसे गड़बड़ होता है और सूर्य की जो अल्ट्रा वॉयलेट किरणें आती हैं, उसको वह कैसे रोकने का काम करता है, इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा भारत सिग्नेटरी रहा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वर्ष 1987 में हुआ, अर्थ समिट वर्ष 1992 में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में और पेरिस एग्रीमेंट वर्ष 2016 में हुआ, जिसमें भारत ने अपने दस्तखत किए। तब भारत ने यह निश्चय किया कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, उसे वर्ष 2030 तक हम लोग 35 प्रतिशत कम करेंगे। हम लोगों ने यह भी तय किया कि वर्ष 2030 तक कम से कम 40 प्रतिशत बिजली हम रिन्यूअल सोर्सेस से बनाएंगे।

मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का इस बात के लिए भी अभिनन्दन करूंगा कि उनके मार्गदर्शन में वायु प्रदूषण कम करने के लिए पॉवर मिनिस्ट्री ने पहले श्री पीयूष गोयल जी और बाद में श्री आर. के. सिंह जी के नेतृत्व में अद्भुत काम किया। उनके साथ-साथ पेट्रोलियम गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ने जो काम किया, वह भी काबिले तारीफ है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा घरों में गैस कनेक्शन दिए गए। हम लोग पराली की बातें करते हैं कि हम लोग पराली जला रहे हैं। अगर हम यह सोचें कि इन 8 करोड़ घरों में सुबह-शाम अगर चूल्हा जलता तो इन 8 करोड़ घरों से कितना वायु प्रदूषण बढ़ता। हमने इस बात का अनुभव नहीं किया है। हम केवल सैकड़ों-हजारों किसानों को दोष देने का काम करते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि इससे कितना फायदा हुआ। 8 करोड़ घरों को जब गैस कनेक्शन दिया गया तो उसके माध्यम से क्लीन एयर दी गई। यह कितना बड़ा काम हुआ।

महोदया, अगर ये गैस कनेक्शन न दिए गए होते तो जंगलों को कितना नुकसान होता और हम लोग जो कैरोसिन जलाते हैं, उसके न जलाने से हमारी कितनी विदेशी मुद्रा बची होगी, इसका

अंदाजा हम लगा सकते हैं। उजाला योजना जनवरी, 2015 से शुरू हुई। इस स्कीम के अंतर्गत 36 करोड़ एलईडी बल्ब लगाए गए। 8 लाख पंखे और 23 लाख ट्यूब्स दी गईं। 21 लाख सड़कों पर एलईडी बल्ब लगाए गए। मैं श्री आर.के. सिंह जी का बहुत अभिनन्दन करूंगा कि उनके अंदाज से 32 अरब किलोवाट ऑवर बिजली एक साल के अंदर बचाई गई। अगर इसका अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 1.9 करोड़ टन कोयला खर्च होता, अगर यह बिजली हम बनाते। उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब जो भारत सरकार ने लगवाए हैं, उसके कारण ढाई करोड़ टन कार्बन डाई ऑक्साइड कम हुई है। इसका कितना बड़ा फायदा हुआ है। अगर 60 करोड़ पेड़ हम 10 साल तक लगाते तब हमें इतना फायदा होता। 12 हजार 4 सौ करोड़ लोगों की बिजली का बिल बचाने काम उजाला योजना ने किया है।

महोदया, इसी तरह वर्ष 2019 में जब यूएन क्लाइमेट समिट हुई और भारत ने घोषणा की कि हम रिन्यूअल ऊर्जा बनाएंगे। हमारा जो टारगेट वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट था, वह टारगेट हम लोगों ने 450 गीगावाट किया है। वर्ष 2016 के मुकाबले 16 गुना सोलर पॉवर हम लोग बनाएंगे। इतना बड़ा टारगेट हमारी मोदी सरकार ने इसके लिए लिया है।

(1540/MM/VR)

पहली बार मोदी जी ने 21 देशों का इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। वर्ष 2014 के मुकाबले में आज हम 8-9 गुना सोलर एनर्जी तैयार करते हैं। हमारा 20 गीगा वॉट का जो टारगेट था, उसको हम लोग पार कर चुके हैं। वर्ष 2022 तक 16 गीगा बाइट सौर ऊर्जा इस देश में हम तैयार करेंगे, जिससे एयर पल्यूशन इस देश में नहीं होगा। हम लोगों ने 42 सोलर पार्क बनाए हैं। सितम्बर, 2019 तक भारत में 82580 मेगावाट के रिन्युएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से पावर मिनिस्ट्री का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ।

सौभाग्य योजना के अंदर 2.6 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाई गई है। अगर इन घरों में बिजली नहीं पहुंचती तो कितना प्रदूषण होता? प्रदूषण में 25 से 30 परसेंट तक वाहनों का हिस्सा है। पहले देश भर में बीएस-3 ग्रेड इंधन मिलता था। वर्ष 2016 से हमने पूरे देश में बीएस-4 इंधन देना शुरू किया। हम लोग दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में हम लोगों ने बीएस-6 इंधन देना शुरू किया है। मेट्रो लाए और 60 हजार हेवी ड्यूटी ट्रक्स जो दिल्ली में आते थे, उनको हमने इस्टर्न-वेस्टर्न पैरीफिरी बनाकर के बाहर से ही रास्ता दिया। लाखों ई-रिक्शा इस देश में हम लोगों ने चलाए हैं। सीएनजी के लगभग पांच सौ स्टेशन हमने बनाए हैं। भट्टों में नई तकनीक हम लोग लेकर आए हैं। इलेक्ट्रिक व्हिकल लाने की योजना हम लेकर आए हैं। बायोफ्यूल पॉलिसी भारत सरकार लेकर आयी है और अब ईथनॉल बेस्ड क्लीन ईंधन मिलेगा। वेस्ट टू एनर्जी के तहत बिजली बनाने पर हम लोगों ने काम किया है।

मैडम, मैं इसके साथ-साथ यह भी बताना चाहता हूँ कि पिछले पांच वर्षों में हमने कितनी तरक्की की है। एक तरफ हमारी आधुनिक सोच है। यह ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अभी इसके बारे में सोचना शुरू किया है। जैसा मैंने कहा कि भारतीय संविधान में इसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया, लेकिन अगर आप कौटिल्य पढ़ेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, कौटिल्य ने लिखा है कि तीन

तरह का प्रदूषण होता है। एक वायु का प्रदूषण होता है, दूसरा जल का प्रदूषण होता है और तीसरा जमीन का प्रदूषण होता है। वायु का प्रदूषण बहुत जल्दी हो सकता है और जल्दी खत्म भी किया जा सकता है। जल के प्रदूषण को देर से साफ किया जाता है और जमीन में अगर प्रदूषण हो जाए तो उसे खत्म करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है।

वायु, प्राण वायु है और वायु के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। हम लोग भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। इस हाल में भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए प्राण वायु कैसे अच्छी बने, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत विचार किया गया है। इसलिए प्राण वायु को उन्होंने देवत्व रूप में देखा है।

“वायुर्यथैको भुवनंभू प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभुवः॥

एकस्तथा सर्वभूतन्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्चः॥”

हमने वायु में देवत्व देखा था और इसलिए वायु को शुद्ध करने के लिए हम लोगों ने अनिवार्य किया था। प्रत्येक व्यक्ति हम में से कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी बलवान हो, हम में से हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ, हर एक व्यक्ति वायु को प्रदूषित करता है। चाहे वह अपने श्वास से करता हो या अपने शौच के माध्यम से करता हो, लेकिन हर एक व्यक्ति वायु को प्रदूषित करता है। जब वायु को हम प्रदूषित करते हैं तो उसको शुद्ध करने की भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक गृहस्थी को कम से कम रोजाना अग्निहोत्र और यज्ञ करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में अग्निहोत्र के बारे में संदेह हो सकता है लेकिन यह बात सांइटिफिक है। इस पर कई एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। इस पर बड़े प्रयोग किए गए हैं। मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से हम लोग पेड़ लगाते हैं, उसी प्रकार से यज्ञ पर भी हम लोग प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें और यह पता लगाएं कि क्या इससे हमारा वायु प्रदूषण भी कम हो सकता है? बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1544 बजे

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): धन्यवाद सभापति महोदया, आपने प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर आयोजित इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का महत्वपूर्ण अवसर मुझे प्रदान किया।

प्रदूषण आज वैश्विक स्तर पर और विशेष तौर से हमारे अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है। इसलिए इस विषय पर इस सदन में बहस हो यह बहुत जरूरी था।

महोदया, लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल की वर्ष 2017 की इंडिया डिजीज बर्डन इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। जिसमें यह बताया गया है कि भारत के अंदर बीमारियों का दूसरा अगर कोई प्रमुख कारण है तो वह आज की तारीख में प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है।

(1545/GG/SAN)

भारत का जो डिजीज बर्डन है, उसमें दस प्रतिशत योगदान प्रदूषण का है। इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से भी बताना चाहूंगी कि दस माइक्रोमीटर से छोटे आकार का जो पार्टिक्युलेट मैटर होता है, जो आउटडोर पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा कारण होता है, अगर वह मानव के शरीर में प्रवेश कर लेता है तो सीधे फेफड़ों पर गहराई से जा कर उसका प्रभाव पड़ता है और तमाम रैस्पिरेटरी डिजीजस के लिए वह कारण बनता है। इस संबंध में हमारे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने राज्यों के तमाम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिल कर पूरे देश के अंदर 339 ऐसे शहर चिह्नित किए हैं, जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है और वहां पर एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन 339 शहरों में से अधिकांश ऐसे हैं, जहां पर पार्टिक्युलेट मैटर दस का जो स्तर है, वह मानव से कहीं अधिक है। डब्ल्यूएचओ ने भी अपनी रिपोर्ट में सन् 2018 में कहा है कि पार्टिक्युलेट मैटर 2.5 के स्तर की स्थिति से दुनिया के जो 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं, उनमें से 14 अकेले भारत के अंदर हैं। इसलिए पार्टिक्युलेट मैटर 2.5 और पार्टिक्युलेट मैटर 10 दोनों के स्तर में कमी लाने के लिए हमें उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में प्रदूषण की समस्या बहुत गहरी हो चुकी है। सर्दियों के मौसम में जब पार्टिक्युलेट मैटर का स्तर बढ़ता है तो हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि सांस लेना भी दूभर होता है। इस बार इतने खतरनाक हालात उत्पन्न हुए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एयर एमरजेंसी और हेल्थ इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। इसके लिए तमाम चर्चाएं मीडिया से ले कर अखबारों से ले कर आम जनमानस की बीच में जब उठीं तो एक प्रमुख और बहुत मुख्य कारण के रूप में किसानों द्वारा पराली जलाने को दर्शाया गया। मैं अभी दो दिन पहले देर रात एक वैवाहिक आयोजन में सम्मिलित होने के लिए अपने क्षेत्र मिर्जापुर के विकासखण्ड जमालपुर के डोहरी गांव में गई थी। महोदया, मैंने देखा कि इस चर्चा का कितना खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मेरे क्षेत्र के डोहरी गांव के तमाम किसान वहां उपस्थित थे और उन्होंने मुझे बताया कि प्रशासन ने हार्वेस्टर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह सोच कर कि किसान उसके बाद पराली जलाएंगे। किसानों की फसल तैयार खड़ी है और वे उसे काट नहीं पा रहे हैं तो उनकी चिंता यह है कि रबी की फसल की बुवाई कैसे होगी। तो यह पराली जलाने से प्रदूषण कैसे बढ़ता है, इस चर्चा ने किसानों पर बहुत अत्याचार करवाना शुरू कर दिया है, बहुत अन्याय करवाना शुरू कर दिया है। लेकिन हम सब यहां पर बुद्धिजीवी साथी बैठ

कर चर्चा कर रहे हैं। सभी इस बात को समझते हैं कि अकेले किसानों द्वारा पराली को जलाए जाना ही प्रदूषण का एकमात्र कारण नहीं है। निश्चित रूप से उसका कुछ योगदान हो सकता है, लेकिन इससे बड़े-बड़े योगदान जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल के कण होते हैं, उससे प्रदूषण बढ़ता है, लकड़ी या कोयला जलाने से होता है। मोटर वाहनों से निकलने वाले धुंए से होता है। यहां तक कि जो जगह-जगह फैला हुआ कचरा है, जिसका हम प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, वह भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। इन सारे कारणों को जब तक हम समग्र रूप से एड्रेस करने का प्रयास नहीं कर करेंगे, तब तक यह वायु प्रदूषण का जो संकट गहराया है, इससे निजात पाना मुश्किल होगा।

महोदया, इस संबंध में ससंदीय स्थायी समिति ने सन् 2018 में दिल्ली एनसीआर पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी है, उसने कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए थे, सुझाव दिए थे। जिसमें पहला सुझाव देश के किसानों के पराली जलाने की समस्या से जुड़ा हुआ था। किसानों को कुछ प्रैक्टिकल और साइंटिफिक सॉल्यूशंस दिए जाएं। किसानों को वित्तीय सहायता दी जाए। उन्हें वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का या दलहन या इसके बारे में बताया जाए या कैसे पराली का वैकल्पिक साधनों में उपयोग हो सकता है, बायो गैस में या पेपर या कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। इन सारी जागरूकताओं को किसानों के बीच पहुंचाने का एक सुझाव पार्लियामेंटी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में आया था। इसके साथ ही जो सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइंस निर्धारित की हैं, उनका कड़ाई से पालन हो। रोडस्ट को प्रबंधन करने के लिए राज्य की सरकारें उसमें व्यवस्थाएं बनाएं और साथ ही दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने की जो दिल्ली की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वह जितनी होनी चाहिए, वह उस निर्धारित क्षमता से कम है। उस क्षमता को भी बढ़ाया जाए, उसमें भी वृद्धि की जाए।

(1550/KN/RBN)

ये तमाम सुझाव स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा आए थे। मैं माननीय मंत्री जी से जरूर जानना चाहूंगी कि इन तमाम सुझावों पर सरकार ने क्या कदम उठाए? मिनिस्ट्री ऑफ इनवॉयर्समेंट फोरेस्ट्स एंड कलाइमेट चेंज ने वर्ष 2018 से 2020 के अंदर एक महत्वपूर्ण स्कीम लाने का काम किया था, जिसके तहत in-situ crop residue management के लिए 1152 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। इसके अलावा हमारा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वर्ष 2019 में लांच हुआ है। उसमें वर्ष 2024 तक एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हम पार्टिक्युलर मैटर 2.5 का जो स्तर है, उसको वर्ष 2024 तक 20 प्रतिशत तक कम करेंगे। पार्टिक्युलर मैटर 10 का स्तर 30 प्रतिशत तक कम करेंगे। इसी के तहत 28 ऐसे शहर हैं, जहां पर पार्टिक्युलर मैटर 10 का स्तर बहुत ज्यादा है, उनमें से प्रत्येक शहर के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन भी किया था। मैं माननीय मंत्री जी से विस्तार में जानना चाहूंगी कि इस धनराशि के उपयोग का और जो हमने वर्ष 2024 तक यह 20 परसेंट और 30 परसेंट का रिडक्शन का टारगेट रखा है, इसका स्पेसिफिक एक्शन प्लान क्या है? किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे? इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ महत्वपूर्ण नेशनल एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग और एयर कंट्रोल प्रोग्राम से ज्यादा आगे बढ़कर कुछ और कदम भी उठाएं जिसमें सीएनजी, एलपीजी और इथनोल ब्लैंडेड फ्यूल को बढ़ावा देना, बीएस-4 से बीएस-6 फ्यूल

स्टैंडर्ड पर शिफ्ट होना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, ऑलरेडी माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक' की शुरुआत की वह भी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के एमिशन स्टैंडर्ड्स को समय-समय पर रिवाइज करना, ये तमाम प्रयास भी किए। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे इतने प्रयासों के बाद भी अगर प्रदूषण के स्तर में गिरावट नहीं आ रही है तो हमें निश्चित रूप से अपने एक्शन प्लान की समीक्षा करने की, जो तमाम हमने कदम उठाए हैं, उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। हमारी दिशा ठीक है, लेकिन अड़चनें कहां हैं कि हम अपने लक्ष्य के निकट नहीं पहुंच पा रहे हैं। उससे भी ज्यादा मैं कहूंगी कि जहां तक प्रदूषण की समस्या का सवाल है, यह समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका केवल सरकारी उपायों के माध्यम से हम समाधान कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने स्वच्छता के प्रति देश को जागरूक किया, उसी प्रकार से प्रदूषण एक ऐसी समस्या है, जिसके लिए समाज में जागरूकता, चेतना और संवेदनशीलता लाए बगैर एक सरकारी टारगेट बना कर इस समस्या से निजात हम नहीं पा सकते हैं। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से समाज से जरूर अपील करना चाहूंगी कि सरकार के सहयोगी बने और जब तक हम इसे जनभागीदारी का आंदोलन नहीं बनाएंगे, तब तक यह समस्या आगे इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इतनी भयावह स्थितियां उत्पन्न कर देंगे कि शायद आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए हम सब को, सरकार के साथ-साथ समाज के हर एक व्यक्ति को देश में बढ़ते हुए प्रदूषण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कारगर उपाय करने चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1553 बजे

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, मुझे नियम 193 के तहत आपने वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चर्चा में मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज दूसरे दिन इस पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूँ कि जलवायु परिवर्तन जो मौसम का मिजाज गड़बड़ा गया है, इसको कैसे ठीक किया जाए, आज पूरे देश के लोगों को इसकी चिंता है। हम लोग जन प्रतिनिधि हैं। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सांसद बन कर आए हैं। निश्चित रूप से जो देश की चिंता है, यहां रखने की जरूरत है। आज पूरे देश में बारिश के मौसम में जितनी बरसात होनी चाहिए, उतनी होती नहीं है। गर्मी जितनी पड़नी चाहिए, उतनी नहीं पड़ती है, जाड़े उतना नहीं पड़ता है। इस पर तमाम लोगों को चर्चा करके, इस बात पर देश के माननीय प्रधान मंत्री खुद चिंतित हैं। अभी सत्यपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आज पूरा देश जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है। मैंने इस साल देखा, हम लोग बिहार से हैं। बिहार में सूखाड़ घोषित हो गया है। सरकार ने घोषणा की है और बेसमय इतना बारिश हुई कि पूरे बिहार में बाढ़ भी आई। पटना डूब रहा था, पूरे देश में चर्चा हो गई कि पटना डूब गया। ऐतिहासिक पानी, लोग बताते हैं कि 30-35 साल पहले उतना पानी आया था। जलवायु परिवर्तन पर हम लोग ज्यादा चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि हम लोग गाँव के रहने वाले हैं। जो किसान हैं वह लगातार इस चपेट में आ रहे हैं।

(1555/CS/SM)

लगातार नदी की उड़ाही नहीं हो रही है, उसकी सफाई नहीं हो रही है। जो हमारे पुराने कुएं, तालाब थे, वे भरते जा रहे हैं। हर व्यक्ति सरकारी जगह, सार्वजनिक जगह पर कब्जा कर रहा है। बड़ी-बड़ी इमारतें बन रही हैं। इस पर भी नियंत्रण करने की जरूरत है। हम यह बात इसलिए बोल रहे हैं कि लगातार हर प्रदेश में यही स्थिति है, कहीं सूखाड़ ज्यादा है, कहीं बाढ़ का प्रकोप है। महाराष्ट्र के लोग चिंता जता रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग चिंता जता रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार का निर्णय ऐसा होना चाहिए, जैसा हमारी बिहार की सरकार ने जल, जीवन और हरियाली का निर्णय लिया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। हम तो कहते हैं कि पूरे देश में बिहार पहला ऐसा राज्य है, जहाँ इसकी उन्होंने चिंता की है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जल, जीवन और हरियाली योजना चलाकर इसके समाधान का एक प्रयास किया है। जितनी भी पंचायतें हैं, हर पंचायत में एक योजना ली है। चाहे वह योजना तीन करोड़ की हो या चार करोड़ रुपये की हो। एक दिन में साढ़े आठ हजार योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया और वह काम लग गया है। यह एक बड़ी पहल है। उसमें और काम करने की जरूरत है। हम लोगों को भी उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि जो पैस है, आहार है, जो हमारी प्रकृति की धरोहर थी, उसको हम ठीक करें। आज पेड़ों की कटाई हो रही है। आज लगातार जंगलों की कटाई हो रही है। अगर कहीं जंगल है और वहाँ इमारत बनानी है, तो वहाँ हम लोग जंगल को काट रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। आज सरकार की तरफ से लगातार प्रयास हो रहा है। हमारी बिहार की सरकार लगातार इस प्रयास में है कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए और उसको सुरक्षित रखे। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रयास है। बिहार सरकार की तीन साल के अंदर 22 करोड़ पेड़ लगाने की योजना है। आज यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, अन्य प्रदेश के लोगों को भी उससे शिक्षा लेने की जरूरत है। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वह नहीं सुधर पायेगी। इसलिए हमें उसकी चिंता करनी चाहिए।

महोदया, आज हर कोई चाहता है कि वह बड़े-बड़े शहर में रहे, जहाँ देश, प्रदेश की राजधानी हो। आज सभी लोग ऐसी जगहों पर रहना चाहते हैं। वे यहाँ इसलिए रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हवाई सेवा मिल रही है, यहाँ मेट्रो की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, नल का पानी पीने के लिए मिल रहा है।

इन सुविधाओं के चलते दिल्ली और पटना जैसे शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। आज दिल्ली में उद्योग लग रहे हैं। जहाँ आबादी ज्यादा है, वहीं उद्योग लग रहे हैं। इससे प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। अभी तो हवा में प्रदूषण हुआ है। भूमि में भी प्रदूषण की बात सामने आ रही है। जब पुआल जलाए जाते हैं, तो वह प्रदूषण है। वहाँ की भूमि पूरी तरह से जल जाती है। वहाँ पौधे अच्छे नहीं होते हैं। इसकी भी चिंता होनी चाहिए। पराली जलाने से सिर्फ हवा का प्रदूषण होता है, ऐसा नहीं है। इससे जमीन का भी प्रदूषण होता है। वहाँ फसल की पैदावार के लिए ज्यादा खाद देना पड़ता है। वहाँ डीएपी का ज्यादा उपयोग करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

आज पूरे देश में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हो रही है कि कैसे उसकी नीति बने और मैं देश के माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस पर आकृष्ट करना चाहता हूँ। आपकी पहल से कई काम हुए हैं। हमारे से पूर्व बोलने वाले कई साथी इस बारे में बता रहे थे। मैं समझता हूँ कि चाहे नदियों का सवाल हो, प्रधान मंत्री जी की सोच है कि नदी से नदी को जोड़ा जाए। जब एनडीए की सरकार माननीय अटल जी के समय में थी, उस समय भी इस योजना को चलाया गया था। नदी से नदी जोड़कर, जो पानी बरसात में बर्बाद हो जाता है, समुद्र में चला जाता है, उसको रोककर, जहाँ पानी नहीं जाना चाहिए, उसकी भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसके चलते भी किसानों की हालत बदहाल हो रही है। पानी का लेवल लगातार नीचे जा रहा है। उसके लिए भी हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को इस पर भी पहल करने की जरूरत है। प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, कई शहरों में प्रदूषण की समस्या है। हम सिर्फ दिल्ली की सरकार पर नहीं बोल सकते हैं। जहाँ भी आबादी बढ़ रही है, आबादी जिस रूप में बढ़ रही है, आने वाले समय में ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत होगी। हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पेड़ों को काट रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में बड़े-बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं। गुडगाँव से लेकर दिल्ली तक चले जाइए, कहीं भी पेड़-पौधा, जंगल कुछ नहीं है। आज उसकी जरूरत है। यह हर व्यक्ति महसूस कर रहा है।

(1600/RV/AK)

प्रधान मंत्री जी की एक सोच है कि हम अटल ज्योति योजना चलाकर, कई तरह की योजनाएं चलाकर, बैट्री की गाड़ियां चलाकर इस पर नियंत्रण पाएं। हर सरकार ऐसा चाहती है, लेकिन इसमें और पहल करने की जरूरत है, तभी देश प्रदूषण मुक्त बनेगा।

कई ऐसे भी प्रदेश हैं, जहां जलवायु परिवर्तन कम हो रहा है। उनसे भी हमें सीख लेनी चाहिए। आप हमीरपुर चले जाइए। वहां का वातावरण बहुत अच्छा है। वहां के लोग कहते हैं कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम यहीं पढ़ेंगे। इसलिए मैं विनती और निवेदन करूंगा कि आज जो जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण पर चर्चा चल रही है और जिसमें आपने हमें बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(इति)

(Page No. 345-346)

1601 बजे

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदया, जब भी हम सदन में खड़े होते हैं तो हमें इस बात की थोड़ी चिंता रहती है। इस सदन में हम लोग जीत कर आए हैं और भारत सरकार के माननीय मंत्रिगण यहां बैठे हैं। पर, बीच-बीच में उच्चतम न्यायालय का निर्देश मिलता है और उसके बाद हम लोग यहां बैठ कर चर्चा करते हैं और कई बार उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर तो हम लोग कानून भी बनाते हैं। उस समय हमें लगता है कि जिस काम को हम सब लोगों को कर देना चाहिए, उसमें हम कहीं न कहीं चूक गए हैं।

दिल्ली के प्रदूषण से यह विषय शुरू हुआ। इसके आंकड़ों को मैं जब देख रहा था तो उच्चतम न्यायालय ने लगभग आठ-दस पेटीशंस में दिल्ली के प्रदूषण के बारे में चर्चा की है। हाल फिलहाल दिनांक 06.11.2019 और 13.11.2019 को उन्होंने कहा कि आप सब लोग निर्णय लीजिए और उन्होंने यह काफी कड़ाई के साथ कहा। उस समय मुझे बहुत चिंता लगती है कि बार-बार उच्चतम न्यायालय हमें निर्देशित करता है या मार्गदर्शन देता है या सलाह देता है और हम उस पर आगे कार्रवाई करते हैं। हम लोगों को कम से कम इससे एक कदम आगे चलना होगा क्योंकि तीनों अंगों में हम सबसे आगे हैं। इस बात की हमें बड़ी चिंता सताती है।

हम अभी जो विमर्श कर रहे हैं, इस पूरे प्रसंग के दो बिन्दु हैं। एक तो वायु प्रदूषण है और दूसरा जलवायु परिवर्तन है।

महोदया, जलवायु परिवर्तन तो अपने आप में एक ऐसा विषय है, जिस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आज की इस वार्ता में मैं अपने आपको प्रदूषण पर ही सीमित रखने का प्रयास करूंगा।

महोदया, दिल्ली तो एक उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष जी का जो कोटा शहर है, चाहे वह हो चाहे पटना हो, पटना तो कोई बहुत औद्योगिक शहर नहीं है, लेकिन पटना का भी प्रदूषण बीच में दिल्ली के स्तर के आस-पास पहुंच गया था। गाज़ियाबाद, कानपुर, राँची इसमें हैं। यह हो सकता है कि दिल्ली में सभी माननीय न्यायाधीश रहते हैं तो उन्हें यहां यह कठिनाई ज्यादा दिखी, लेकिन यह समस्या सिर्फ एक राज्य की नहीं है और राजधानी दिल्ली की नहीं है, बल्कि यह समस्या पूरे भारतवर्ष की है और बहुत बड़े-बड़े शहरों की यह समस्या है। इसलिए केन्द्रित रूप से हमें बड़े निर्णय करने होंगे और मैं उस विषय पर आगे आऊंगा।

आखिर इसका मानक क्या है? हाल-फिलहाल दिवाली के समय किसी ने मुझे एक मशीन गिफ्ट की। पहले तो मुझे उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे मैंने अपने कमरे में लगाया। उसमें रंग-बिरंगी रोशनी निकलती है। पहले बैंगनी रंग की रोशनी निकलती है, फिर उसके बाद हल्की नीली रोशनी निकलती है और इसी तरह की तरह-तरह की रोशनियां निकलती हैं। फिर उसके ऊपर मैं आंकड़े देखने लगा। वह एयर प्यूरीफायर था। रात को सोते-सोते कभी-कभी उसमें लाल रंग दिखता है तो पता चलता है कि पॉल्यूशन 300 के ऊपर चला गया। जब तक वह मशीन और यंत्र नहीं लगा हुआ था, तब तक तो मुझे इसके बारे में अनुमान ही नहीं था।

महोदया, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि सदन में भी उस यंत्र को लगाकर रखा जाए, ताकि सभी माननीय सदस्यों को समय-समय पर इसके बारे में पता चलता रहे और हम सब इसके प्रति जागरूक रहें।

1604 बजे

(श्री कोडिकुन्निल सुरेश पीठासीन हुए)

महोदय, ईश्वर ने प्रकृति बनाई है, पेड़ बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं और सब कुछ मुफ्त दिया है। उसमें सबसे बड़ी चीज़, जो ईश्वर ने मुफ्त दी है, जिस पर सबका बराबर अधिकार है, वह है - ऑक्सीजन। हमारे शरीर का एक अंग है, जो बड़े ही सेल्फलेस्ली तरीके से काम करता है। आप सोए हों, तब काम करता है, आप पढ़ रहे हों, तब काम करता है, जब भाषण दे रहे हैं, तब काम करता है। गिरिराज जी के बारे में चर्चा कीजिए, तब काम करता है। अध्यक्ष जी के बारे में चर्चा कीजिए, तब काम करता है।... (व्यवधान) वह हम लोगों के भीतर का एक अंग है, जो कभी किसी से कुछ माँगता नहीं है। बीमार अवस्था में भी अपना काम करता है। आप दुःखी हों, बीमार हों, पर वह काम करता रहता है, जब तक आप अपनी अंतिम साँसें नहीं लेते हैं।

(1605/MY/SPR)

वह हमारा हार्ट है। वह कभी किसी से पूछता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। वह निरंतर सोई अवस्था, दुखी अवस्था और जीवित अवस्था में चलता रहता है। उसे एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है, उसे अच्छी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। वह बिना किसी पूछताप के आपकी सेवा में लगा रहता है। अगर हम उसे अच्छी ऑक्सीजन देने की स्थिति में न रहें, तो शायद उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके लिए मानक बनाए गए हैं कि 50 से कम है, तो अच्छा है।

अभी हमारे एक मित्र हेनरी जॉर्ज हैं। वह अमेरिका में रहते हैं। जब मैंने हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ली, तो मैं वहां उनके इंस्टीट्यूट में था। वह भारत आते रहते हैं। उन्होंने लिखा कि मैं दिसंबर माह में आना चाहता हूँ और जनवरी में दो विंडो हैं। मैंने उन दोनों में लिख कर भेजा कि आपका दोनों में स्वागत है। वह मयामी में रहते हैं, जहां हमने ट्रेनिंग ली थी। मैंने मयामी के बारे में कहा, तो उन्होंने पीछे लिखा कि - I have read it in the newspaper that pollution level there is very high. I prefer to come in January. वह मयामी में रहते हैं। वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 20-30 है, दावोस की तरह है। अब स्वाभाविक तौर से एक इंसान भारत आना चाहता है, लेकिन पॉल्यूशन के कारण वह वहीं रुक गया। उन्होंने कहा कि - I will try to come in January. अब थोड़ा सा देखिए कि यह अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। जब हवा खराब हो जाए, तो उसे अर्थव्यवस्था से क्या लेना-देना है?

महोदय, दिल्ली में एक महीने तक यहां के जितने ईटिंग आउटलेट्स थे, जहां रोज शाम को लोग खाना खाने या पिक्चर देखने जाते हैं, इस प्रकार के जो इंडस्ट्री दिल्ली में थी, उनका 20 परसेंट रेवेन्यू डिप कर गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि खाना खाने के लिए होटल में नहीं जाएंगे, बाजार तथा इंडस्ट्री में भी नहीं जाएंगे और कहीं भी घूमने नहीं जाएंगे। अगर पॉल्यूशन 50 तक हो, तो अच्छा माना जाता है। 50 से 100 है, तो अच्छा है। इस प्रकार से पूरा मानक बना हुआ है। 200 से 300 खतरनाक, 300 से 400 और भी खतरनाक, 400-500 बहुत ज्यादा खतरनाक, लेकिन

दिवाली के अगले दिन दिल्ली का जो पॉल्यूशन था, वह 900 था। उस दिन जितने लोग दिल्ली में रह गए, उन्होंने अपनी आयु को कुछ न कुछ दिन कम तो कर ही लिया होगा।

अगर हम इन परिस्थितियों के बारे में विश्लेषण करें, तो थोड़ा डरावना लगता है। हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोगों को पता चलता था कि अगर बहुत बारिश हो जाए, तो छुट्टियां हो जाती थीं। हवा का पॉल्यूशन हो जाए और उसके लिए स्कूली बच्चों की छुट्टी हो जाए, तो यह अपने आप इस बात को इंगित करता है कि कहीं न कहीं स्थिति बहुत भयावह तथा खतरनाक है। स्वाभाविक तौर पर उच्चतम न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करेगा। अगर हम राजनेता और कार्यपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो कौन इसमें भाग लेगा।

महोदय, इसका कारण क्या है? अब हम एक तरीके से कह देते हैं कि दिल्ली में फलां-फलां हो गया। गर्मी के मौसम में जब गर्मी आती है और वायु तेज गति से चलती है, तो राजस्थान के रेगिस्तान से धूल उड़ती है। वह कई कारणों से बड़े शहरों एवं देश के दूसरे भागों में प्रवेश करती है। यहां तक सउदी अरब के डेज़र्ट में जो बालू के कण उड़ते हैं, वे भी उठकर भारत तक आते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन सिर्फ दो राज्यों के बीच हो रहा है और पंजाब तथा हरियाणा से हो रहा है। पॉल्यूशन तो एक ऐसी चीज है, जिस पर दुनिया का मैनेजमेंट शुरू हो गया है। हम पॉल्यूशन का कैसे ट्रांस बॉर्डर मैनेजमेंट कर सकते हैं? हमें अपने दायरे को छोटा नहीं करना चाहिए। हम उस विषय पर भी आएं कि किस तरह से भारत के प्रधान मंत्री इस विषय को उठाकर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ले गए। हमारी समझ है कि इस दीवाल से उस दीवाल के पीछे जो पॉल्यूशन है, वह सीमित है।

महोदय, जाड़े में क्या होता है? जाड़े में मौसम का टेम्परेचर नीचे आता है और वायु मंडल का मॉड्यूलर कम हो जाता है। जब वायु की गति कम हो जाती है, तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है। यह भी उसका एक कारण है। अगर किसी कारण वायु कहीं न कहीं रुक जाती है, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। जैसे आज दिल्ली का जो वातावरण है, यहां टेम्परेचर गिर रहा है और मॉड्यूलर कम हो रहा है। प्राकृतिक रूप से इसका भी उपचार है, लेकिन इन उपचारों पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। हम लोगों ने वर्षों से इसे गिराया है। इसके पीछे क्या कारण है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले भी टेम्परेचर ड्रॉप करता था। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। हम केवल एक फैक्टर के बारे में नहीं कह सकते हैं।

महोदय, दिल्ली के इर्द-गिर्द और अरावली से लेकर यहां तक कई स्थानों पर लोगों ने हजारों एकड़ जमीन खरीद करके छोड़ दी है। न उस पर पौधे लगे हुए हैं, न ही उस पर किसी प्रकार का निर्माण हुआ है। रियल इस्टेट के बड़े-बड़े तथा हजारों हेक्टेयर लैंड दिल्ली के आसपास खाली पड़े हैं, वे बंजर पड़े हैं। उनका ऐसा मानना है कि इस पर डेवलपमेंट नहीं करेंगे। जब सरकार या लोगों से अच्छा पैसा मिलेगा, तब उसको डेवलप करेंगे। इसके आगे हमारे दुश्मन कौन है? अब हम अपने आप को कहें, क्योंकि आप दिल्ली के घरों में चले जाइए, ऑड-ईवन का विषय तो अब एक पोलिटिकल विषय बन गया है, लेकिन स्वाभाविक तौर से हर घर में चार गाड़ियां खड़ी हैं। बेटे के पास एक है, बेटे के पास एक है, बहू के पास एक है, पिताजी के पास एक है और आजकल तो स्टाफ भी गाड़ी लेकर आते हैं, क्योंकि उनको घर का काम देखना होता है। यह कारण भी बहुत जोर से है।

(1610/CP/UB)

महोदय, दिल्ली के आसपास बहुत सम्पदा थी, जंगल थे, पहाड़ थे, नेचुरल झीलें थीं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, पर्यावरण के छोटे मंत्री यहां बैठे हैं, उनको नहीं, हमारे लिए तो सौभाग्य है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी यहां आ गए हैं, क्योंकि अकेले हम केन्द्रित इस बात को करते हैं कि सिर्फ पर्यावरण मंत्री ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। महोदय, पर्यावरण मंत्री ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बहुत सारे इनफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वह सड़क के मंत्री हों, चाहे ग्रामीण सड़क के मंत्री हों, चाहे शहरी क्षेत्र के मंत्री हों, इन सभी विभागों का हस्तक्षेप जब तक इसमें नहीं होगा, तब तक कुछ लाभ नहीं होगा। सड़कों का निर्माण होता है, धूल उड़ती रहती है, पानी की छिंटाई नहीं होती है, गांव-देहात के लोग सड़क पर आ जाते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इतनी ज्यादा डस्ट है, रोड किनारे रहने वाले लोग हैं, बड़े-बड़े एनएच का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण के बगल वाले लोग परेशान होते हैं। यह बड़ी सोचने वाली बात है।

त्रिवेन्द्रम से, चेन्नई से लोग चाहते हैं कि चलो बड़े शहर में चले जाएं। कुछ लोग पटना से दिल्ली चले आते हैं, कुछ लोग त्रिवेन्द्रम से दिल्ली चले आते हैं, यहां घर बना लेते हैं। पूरे देश को लगता है कि अच्छी राजधानी में पहुंच जाइए, तो वहां बिजली 24 घंटे है, पानी है। ... (व्यवधान) बड़े शहरों में लोग आते हैं। हमारे पिता जी मेरे गांव अमनौर से निकलकर पटना आए, तो हमें पटना के अच्छे स्कूल का, अच्छे शहर का लाभ हुआ। उसी प्रकार से जो और बड़े थे, वे पटना से निकल कर दिल्ली आए, सूरत से निकल कर दिल्ली आए, देश की राजधानी में रहने के लिए आए।

आज पूरे भारतवर्ष में 13 सौ मिलियन लोगों में से पिछले 10 वर्षों में 80 मिलियन लोग गांवों को छोड़ कर शहरों में चले आए हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तो स्वाभाविक तौर से लोग शहरों की तरफ आएंगे। आज परिस्थिति बदल रही है। लोगों को यह बताने की जरूरत है। मैं आजकल अगर पटना, बिहार जाता हूं, तो पटना नहीं रुकता है, क्योंकि पटना का भी पोल्यूशन लेवल 300 के आसपास पहुंच जाता है। देश की सरकार ने और हम सब लोगों ने देश के निर्माण में भागीदारी शुरू की है। मैं जिस गांव में रहता हूं, जो 50-60 किलोमीटर दूर है, वहां 24 घंटे बिजली है, सड़क है, एम्बुलेंस है, इंटरनेट है और हमारे यहां स्वच्छ हवा है। देश के इन बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि अब देहातों में भी ये सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। देश के प्रधान मंत्री और भारत की सरकार ने यह कमाल कर दिखाया है। अब समय आ गया है कि शहर छोड़ कर हम देहात की तरफ जाने की भी कल्पना कर सकते हैं। अब वह समय आ रहा है।

मैं प्रामाणिकता से इसलिए कह सकता हूं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन का, अब तो मैं बार-बार चला जाता हूं, लेकिन मेरी जो जवानी थी, मैं विधायक बना, सांसद बना, मैं शहरों में रहा... (व्यवधान) मैं शहरों में ही रहना पसंद करता, लेकिन अब मैंने जिस उम्र में प्रवेश किया है, मुझे लगता है कि देश के गांवों में रहने में कम से कम लंग्स और हार्ट को परेशानी तो नहीं होगी। मैं इसको संक्षिप्त कर देता हूं।

एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि बेचारे किसानों का क्या कसूर है? आप पोल्यूशन करेंगे गाड़ी से, आप पोल्यूशन करेंगे मकान बना करके, आप पोल्यूशन करेंगे एनक्रोचमेंट से, आप

पोल्यूशन करेंगे बीस इंडस्ट्रीज लगा करके, आप पोल्यूशन करेंगे गाड़ी चला करके, पेट्रोल खर्च करके, लेकिन इस सब चीज को छोड़-छाड़ कर हम लोग किसानों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? बिहार में लीची खाकर कुछ बच्चे मर गए, तो कहा कि लीची में प्राब्लम है और लीची की फसल को मार दिया। अनुप्रिया जी कह रही हैं, अब हार्वेस्ट रोक दिया है। किसानों के पीछे हम पढ़े-लिखे लोग और खास कर सदन के लोग यह कहते हैं कि स्टबल बर्निंग हो रही है। This is one of the hundred factors. बेचारे किसान को आप बता दीजिएगा, अल्टरनेटिव क्रॉप दे दीजिएगा, वह तरीके से कर लेगा। हर बार घूम-फिर कर हम किसानों के पीछे पड़ जाते हैं। यह सदन को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि इस पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मात्र किसान दोषी है। यह कतई इस सदन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे लोग दोषी हैं। शहरों की कैरिंग कैपिसिटी की एक लिमिट होती है। वह भी अब समाप्त हो रही है। मैंने आपको उदाहरण बता दिया। मैं अभी सिर्फ पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। महोदय, लगता है कि क्लाइमेट चेंज पर बात करने का आप मौका देने के मूड में नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा विषय रख दूँ।

मैं ट्रांस बार्डर पोल्यूशन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जब सीरिया में बांबिंग होती है, उसके ऑयल फील्ड्स को आग लगाई जाती है, तो इराक की क्या हालत हो जाती है?

(1615/KMR/NK)

वहां कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। एक समय भारत में वल्चर चालीस लाख के आसपास थे। अब भारत में मुश्किल से पन्द्रह या बीस हजार वल्चर रह गए हैं। जब पशु मरते हैं तो उस शरीर को खाने के लिए गिद्ध नहीं आते हैं। हमने पर्यावरण को इस तरह से प्रदूषित किया है कि The vultures are no more there. As a result, what happens when these animal carcasses start decaying? जब जानवर मरते हैं तो इनके शरीर से एंथ्रेक्स निकलता है और वह हवा में बहकर आता है, वह इतना घातक है कि इंसान की जान ले सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।

बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं। हम लोग आईएसआई विंटर कहते हैं, वहां इतनी बम्बिंग हुई है, इतना नुकसान हुआ, मिडल ईस्ट का पूरा वातावरण खराब हो गया है। हम अकेले एक फैक्टर को लेकर चल सकते हैं। अमेरिका का देखिए। माननीय मंत्रिगण बैठे हुए हैं, माननीय राजनाथ जी भी बैठे हुए हैं। वर्ष 1970 को इन विभिषकाओं को देखते हुए अमेरिका ने यहां क्लीन एयर एक्ट बनाया। अमेरिका में 45 सालों से क्लीन एयर एक्ट लागू करने की कामयाबी दिख रही है। That Clean Air Act has been responsible for increasing the lifespan of Americans by more than 15 years. But that investment has gone to build up the productivity of the nation. By spending around 0.5 trillion dollars, they have had a GDP addition of 22.2 trillion dollars. We should take that as an example. उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक देश ने कर दिखाया है कि किस प्रकार से एन्वायरमेंट का काम जाता है। मैं क्लाइमेट चेंज पर नहीं जाना चाहूंगा, आप लोगों ने इतना जल्दी-जल्दी कर दिया कि कुछ बोल ही नहीं पाए, लेकिन फिर भी इतना समय पर्याप्त है।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी का संदर्भ लाना चाहूंगा। यह मेरा अधिकार है कि प्रधान मंत्री जी के पॉजिटिव कदम के बारे में बोलूँ। हाउडी इंडिया के बारे में पूरी दुनिया ने देख लिया। प्रधान मंत्री जी इस बार एक बहुत बड़ा काम करके आए हैं जो दुनिया में शायद किसी प्रधान मंत्री ने नहीं किया है। इसे संज्ञान में लेने की आवश्यकता है कि क्लाइमेट एक्शन ग्रुप के बारे में यूएन जनरल असेम्बली में बोला That was on 23rd September in New York.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Rudy Ji, please conclude.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): You are not listening to me, Sir? If you listen to me, you will not ask me to conclude. But I will conclude in exactly in two minutes, Sir.

The Prime Minister talked about the Clean India Mission. Clean India Mission is not an ordinary programme. It could be words of a language when we say Clean India Mission. But the Clean India Mission is a philosophy which the Prime Minister of this country proposed. When he says, 'Swachh Bharat', it has a motivational aspect to each one of us. Swachh Bharat is not a scheme of the Government. कई बार हम लोग कहते हैं, ये गंदगी पड़ी हुई है, ये क्या है? Swachh Bharat is a philosophy of which the Prime Minister is a proponent and that is what we call the Clean India Mission. He talked about stopping usage of single-use plastic. He talked about many more things. He talked about increasing renewable energy target to 50 GW. Then he talked about something very interesting. इस विषय को सभी को अंतिम रूप से संज्ञान में लेना चाहिए। He talked about a coalition for disaster resilient infrastructure. This House needs to debate on this aspect, on what the Prime Minister had told the UN. It has a huge connotation when he talked about a coalition for disaster resilient infrastructure. This includes almost everything of what we are talking about today. The Prime Minister has put in the key word here. This key word is what we are going to talk about for the posterity. आज यहां सदन में बोल रहे हैं, यह हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। यह अगले हजार वर्ष के लिए बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोट सेट कर दिया है। इसमें थोड़ा वक्त लगता है। हम लोग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज कहते रहते हैं। पहले गांव देहात में कहते थे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो किसी को समझ में नहीं आता था। लेकिन आज किसान कहता है कि जिस समय बारिश होना चाहिए थी बारिश नहीं हो रही है। दीवाली के बाद पतंगे आते थे, जब दीया जलाते थे तो बहुत पतंगे आते थे, बल्ब पर भी आते थे। देहात का किसान बताता है। जब हम लोग कहते हैं कि यही क्लाइमेट चेंज है तो कहता है कि एकदम ठीक कह रहे हैं। मौसम

बदल रहा है। पहले हम लोग दस वर्षों से क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं लेकिन किसी को समझ में नहीं आया।

(1620/SNT/SK)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Rudy Ji, please conclude. Your two minutes are also over.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I will conclude. My only point is we all have to become conscious to it.

HON. CHAIRPERSON: That is why you have got more time.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I try to fish out new things.

HON. CHAIRPERSON: You are a long speaker in this subject.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): मैं एक चीज का कम्पलीमेंट देना चाहूंगा, जो पिछले इन पांच वर्षों में और इन आठ महीनों की अवधि में देखा है। अब सदन में आने की एक सीनियोरिटी बन गई है, मैं लगभग वर्ष 1996 से यहां बैठा हूं, बीच में जाता भी रहा हूं, कभी उस सदन में भी गया हूं। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, इस सदन में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं, यह मेरा पर्सनल आब्जर्वेशन है, देश के सामने ऑब्जर्वेशन है, किसी को खराब न लगे, इस सदन में पिछले कई सत्रों से इस सत्र का डिबेट का लैवल सबसे ऊंचा है, सबसे बढ़िया है। जब प्रत्यक्ष रूप से सांसद श्री कौशलेन्द्र जी बोलते हैं, अनुप्रिया जी बोलती हैं, पाठक जी बोलते हैं, it deserves a compliment and this credit goes to the Prime Minister of this country to have set the agenda to bring this level to the Parliament.

Thank you.

(ends)

1621 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. While participating in this discussion, I feel that this is the noblest work an MP can do at this particular situation of climate change. This affects the very existence of the Universe and it affects the breathing of the nation. But what exactly is happening, Sir, is, we are spoiling ourselves and we are spoiling the future of the nation and the country in general.

Among the risk factors of diseases in India, air pollution ranks the second highest, only after malnutrition, accounting for 10 per cent of the disease burden. Air pollution causes premature death and disabilities.

According to the findings of the India State-Level Disease Burden Initiative, published in 2017, 12.4 lakh deaths, that is, 12.5 per cent of the deaths in India, were attributable to air pollution.

As per the pollution database released by WHO in 2018, 14 Indian cities are among the 20 most polluted cities in the world. Recently, Supreme Court of India asked, how to breathe? That was the question of the Supreme Court of India.

Over the last few days, in Delhi, we had bitter experience. There is some relief for 2-3 days but forecast says that the situation will deteriorate again. We all know that it is vital, significant, and a burning issue. How do we solve it? Many proposals have come.

The first point is with regard to carbon emissions. We are all talking about electric vehicles. I humbly submit that an expeditious action should be taken to manufacture electrical vehicles in a rapid manner. We must set a goal to make 25 per cent of private vehicles to be electrically powered by 2023, or so. We also have to tell the farmers to use the new vehicles so that climate change can be effected.

Our rivers are out of water. Poets have written poems and many novels have been written about that. We are all proud of our water bodies. But, unfortunately, what is happening, Sir? It is estimated that around 70 per cent of surface water in India is unfit for consumption. Every day, almost 40 million litres of waste water enters rivers and other water bodies. Who is here to question? There is a Pollution Control Board. But, unfortunately, Pollution Control Board is not working effectively in this country. We have to revamp that.

Now, I will come to the next issue. We have numerous rivers like, Ganga, Yamuna, Kaveri, etc. In my constituency, Bharathappuzha river is there, and Chaliyar river is flowing through my village. But we have not been able to maintain their purity, cleanliness and the physical well-being.

(1625/RK/MK)

It is an unfortunate situation.

Due to water pollution, there is an increase in the water-borne diseases. I would like to make some humble suggestions.

The manufacturers and importers must share some responsibility. They are responsible for polluting the air and water. The responsibility has to be fixed. Those who are polluting water and air should be punished. We should have stringent laws to punish these people. We have a number of laws but they are not working properly.

India is a member of the Paris Agreement. Paris Agreement is known as a Magna Carta on this. We have to set our goals. What should be our goals? In accordance with the Paris Agreement, we have a commitment. That is the main thing which I would like to point out.

Though we have a number of laws on pollution, in reality, our air, water, space and even our sea is polluted. All these legislations and guidelines are there but unfortunately their implementation is very poor.

The Government has taken a number of steps, like the ban on plastic. This should be strictly adhered to. The Government should be determined to act on it sincerely.

Building rules must have strict provisions to prevent pollution. We have to amend our building rules accordingly.

At the school level itself we should create awareness among the children of the consequences of pollution.

We have to make an effort on war footing to convert from coal-based energy system to renewable energy system. This has to be given maximum importance. As I have told in the beginning, this affects the mankind as a whole or I would say, not only mankind the entire population of different species living on the earth. I hope, the Government will take maximum possible steps in this regard.

I once again congratulate the man who has moved this discussion. This is a great move, as far as this House is concerned. With these words, I conclude. Thank you very much.

(ends)

1629 hours

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much Mr. Chairman. I am grateful for this opportunity to speak on this extremely important subject because I had actually been leading an effort to have dealt with it for the last three years. I have taken the initiative to bring together a group of civil society stakeholders, health care experts, practitioners, Director-Generals of AIIMS, technical experts and a few fellow MPs who are willing to accept my invitation to an annual closed-door discussion on the magnitude of the current crisis of toxic air quality across our country.

The discussions in 2017, 2018 and also this year dealt not only with the current state of air quality but also extended to deliberations on what we could possibly do as concerned citizens and as elected representatives to create and implement a National Action Plan on cleaning up our air.

Since the inaugural meeting in 2017, this platform has brought together some of the most accomplished and experienced stakeholders on this issue of vital national importance, including for the first time this year, the hon. Minister of Environment, my good friend Shri Prakash Javadekar, who addressed the serious gathering in a comprehensive ideation of this Government's strategies to address air pollution.

(1630/PS/RAJ)

So, I think, we are on the right track and I am glad to see that the hon. Speaker has taken this conversation forward, at a time, when it simply cannot be ignored any more. The issue of air pollution has simply, until this debate, so far not been given the due recognition it deserves or even serious discussion within the walls of this august chamber. In a few times, it has become a political hot potato. It is always in the few weeks before and after Diwali and in fact, just after Diwali, is when the debate also peaks as does the AQI, the focus on urban centres is very often reduced to Delhi-Punjab debate and honestly, that misses the larger point. That is the situation we have. This is a national crisis. It is a perennial issue, not just in November. It is a pan-India problem that we must solve together.

In 2017, there was a report of the State of Global Air. There is one more last year. I have not seen it. It was published by the Health Effects Institute. It revealed that since 1990, the number of ozone-related deaths in India has risen

by 150 per cent. It is a staggering figure. The economic implications of deteriorating air quality are ominous as well, with the 2013 World Bank study estimating that the welfare costs and lost labour income due to air pollution, cost the exchequer nearly 8.5 per cent of India's GDP. So, our GDP would have that much higher if we had dealt with our air successfully. Labour losses due to air pollution, in terms of the number of man-days lost, for instance, resulted in an estimated and calculated loss of 55.39 billion dollars in a single year and further premature deaths will cost our country an estimated 505 billion or roughly 7.6 per cent in this coming Fiscal Year. The effect on our quality of life is also incalculable. We cannot do it in numbers. But I remember that when I was a student at Delhi University in the early 70s, September to February used to be the best months of the year. Today, let us face it that these are the worst months of the year.

I can talk about a diplomatic friend of mine, who after three years' service in Delhi, was taking his exit medical examination. His doctor asked him, 'How many packs of cigarettes do you smoke every day.' The poor diplomat protested saying that he is a non-smoker and he never smoke in his life. But the doctor said that his lungs show otherwise. The poor chap has never lit up. He had merely been breathing Delhi's smoggy air three winters in a row. It really is that bad.

The New York Times former India correspondent, Gardiner Harris wrote a famous or perhaps, to many of us a notorious article in the year 2015 in which he explained why he was leaving his post prematurely. He says merely living in Delhi is damaging my children's health. Describing the asthma and the travails of his eight years old son, Harris wrote and I quote, 'That Delhi was suffering from a dire paediatric respiratory crisis, with a recent study showing that nearly half the city's 4.4 million school children have irreversible lung damage from the poisonous air.' He said that his other expatriates, posted in Delhi, were pursuing their careers at their children's expense. He concluded by saying that it was unethical for him and those who have a choice to willingly raise children here. So, he picked up his kids and left India and wrote about it. This is a kind of a thing that makes, as Shri Rajiv Pratap Rudy was mentioning, many foreigners hesitate to even come to our country. रूड़ी साहब कह रहे थे कि जब लोग तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आते हैं, उनकी हालत क्या है, यह मैं बता सकता हूँ। मैं हर हफ्ते तिरुवनंतपुरम से दिल्ली

आता हूँ। मैं कहूँगा कि जब हवाई जहाज से उतरता हूँ, तो खांसी आती है, जब सांस लेता हूँ, तो खांसी आती है। That is the experience of all of us in Delhi and this is a situation that we are finding ourselves in the Nation's capital. The New York Times' correspondent has a choice. Unfortunately, MPs and most Indians do not have that choice. So, a study was conducted by the Kolkata-based Chittaranjan National Cancer Institute. They found that the key indicators of respiratory health and lung function are markedly worse among the school children in Delhi, between four and seventeen years of age than their counterparts elsewhere. In fact, the figures are twice to four times as bad for children in Delhi than in other places. According to the Cancer Institute, these are not reversible.

So, it is actually true to say that bringing up our children in Delhi, is a crime against our children. Toxic air quality is a silent killer and today, in India, the air we breathe, has itself become a public health crisis -- one that is slowly, but surely crippling our country.

(1635/SNB/VB)

But at the same time, this is not politics. It is because honestly it is like what I have been saying for some time about our foreign policy. I always say there is no BJP foreign policy, or Congress foreign policy, there is only Indian foreign policy -- so too, with our air quality. Our political differences on the subject have to end where the stratosphere begins because you and I and all the other hon. Members from other political parties are breathing the same air. There is only one Indian air quality. Currently it is very bad and we need to address its toxicity together. It is a problem that can be addressed if the right kind of sustained campaign focuses on both short-term and long-term interventions on this issue.

Take for example, China's action. As recently as 2013 they had peak toxicity. They were higher than us. Beijing was worst ranked than Delhi. But public scrutiny mounting in the wake of Beijing Olympics, China formulated the National Air Pollution Action Plan which imposed stringent controls on emissions, strict guidelines for air quality checks and China's air quality strategy since, though in an incipient stage, has made a lot of difference and Beijing is no longer joining us or competing with us for the worst polluted city in the world. That is a valuable lesson we can learn.

Of course, India is not China. We are a democracy where the smallest voice matters and where the means are as important as the ends. So, we cannot have any compulsions or methods that the Chinese used. But we can certainly see what worked there that we can borrow here. Today somebody put on social media the video of the star that they have in Beijing. That soaks up the smog, converts it into carbon particles and then they are compressed into diamond and if you buy a diamond ring, you are actually donating to cure the smog of Beijing. Now, if they can do that in Beijing, is there a possibility of doing it in Delhi? That is worth finding out. I just feel that we should explore what others have done. We do not have to reinvent the wheel.

India, of course, has shown commitment and willingness by way of the National Clean Air Programme. It is important -- and as others have been saying that there is involvement of the Government in the Copenhagen Agreement, the Paris Agreement and so on. But still the pace of action at home in terms of what we are all breathing has been found wanting. Let us accept that our wealth of civil society stakeholders and technical experts have not been adequately consulted. There has been very limited public consultation by the Government on the plan and its targets. The timing is also a matter of concern because the plan was announced just as the previous Government, that is the Modi Government Part I, had just wound up its term and there was obviously immediately no follow up. We need to pick up the threads in now Modi Part II, or BJP Part II or NDA Part II is probably what you want me to say and actually resume concrete steps towards implementation. I think, this discussion alone is not enough. The Minister should really come to the Parliament and specify an Action Plan saying that the Government, and all of us, must do this by such and such timeline and only then, will we make measurable progress. Making speeches we can all do and that is what, we are here to do but we have to have concrete action. I do want to say that it is concerning that the National Plan, as I have read, has no legal measures incorporated within it to ensure accountability or penalise non-implementation which will limit the effectiveness of the Plan. If it was converted into an Act, into a New National Clean Air Act, debated in Parliament and voted in Parliament, it will have the force of law. That is something I strongly recommend to convey to the Environment Minister. So, to summarise, the Action Plan, in my view, must be ambitious; it must bring in

the best tech-based innovations and interventions wedded to our age-old heritage of sustainable practice and of course conservation because we have things worth conserving. We need to accept that our present infrastructure is insufficient. Even to monitor the scale of toxicity in air quality we have not done a great job. I know some of us have apps on our mobile phones that give us the AQI. But the fact is in many parts of India it is not available. Look at rural India where the *chulha* continues to burn out the lungs of citizens who have no affordable alternatives that they can use. There is a problem even in rural India. It is not that we only suffer in Delhi.

Secondly, the Plan must be courageous in its guidelines. There must be tough guidelines and targets. I have already mentioned that and I will not repeat it. We must, of course, be conscious not to weaken the weakest in our society. Some have spoken very emotionally about our farmers and how the burden should not be put on them because stubble burning is a cost saving practice and so on. Well, the Government has the money and resources to give them a viable and a cost-saving alternative. In a diverse democracy like us we have to take all stakeholders along.

(1640/RU/PC)

Thirdly, we must have a collaborative action plan. We must bring together the best minds in our country. We must take the civil society on board and use our technical resources and the vast knowledge pool which we are blessed to have. I must say that I met many very impressive experts on the question of air quality who are frustrated that they cannot even get an audience with the members of the executive dealing with this issue. It is important that we now work together in a collaborative spirit and that is why, I convened my round table all these years in order to create a platform that will strengthen these bridges. I hope that Parliament can be the right forum to take it forward.

We all realise that this is not going to change overnight or even in a year or two or even by the end of this Parliament in four-and-a-half years. But the fact is, we must sow the seeds of our campaign against toxic air now if we want to breath better air when we come back, if we come back, in the next term of Parliament. It is genuinely not too late. The fact is, that this national crisis cannot just be confronted after Diwali or in the winter months. It is extremely important

that we understand the urgency of this as well as the widespread impact that our actions need to have and should have across the country.

I do want to stress that it is not just an environmental issue and only the Minister for Environment, Forest and Climate Change is listening to our debate but it is also a national health issue. As I mentioned, the Director-General of AIIMS is an expert in respiratory illnesses. Doctors have testified on the health crisis of this issue. It is an economic and development issue as I gave you the figures from the World Bank. It is an issue of how India consumes, how India travels and it is also an issue that is central to the future of our country.

I hope, we will come up with equitable solutions, come up with collaborative solutions that refine the political will for a legislative approach to implementing an effective National Clean Air Policy. I do want to finally say that I believe that we have the will and the capacity for it. Do not forget what the British had reduced us to by 1947 and how we have climbed up from then to what we are today. We were a poster child of poverty, disease and destitution. Today, we are a thriving economy and society. We can find the same will power to conquer this challenge of toxic air.

I do believe that since this is something which affects all of us, we should work together and just as for John F. Kennedy, the moonshot was the great aspiration of his generation, I would urge that we make cleaning up of our air the moonshot of our times so that we are finally in a position to give our children and grandchildren decent air to breathe in a country which we can be proud to live with health and contentment.

Thank you and Jai Hind!

(ends)

1643 hours

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): Sir, I thank you for this opportunity to express my views on the need of the hour not only in Delhi but in the country and the world as a whole.

I would like to start with Shanti Niketan which has been started by the father of Rabindranath Tagore wherein they used to teach in the open with the nature saying that nature is the best teacher among all the teachers but today, the situation in our country is different. In Delhi, we have seen that because of environmental problems, the schools were closed. From open air schools, we have come to the level of closing down of schools. That shows the gravity of the situation.

The famous humourist and one of the greatest writers of this century, Mark Twain who is also a chain smoker said that he has taken a decision not to smoke at night. If he would have been in Delhi, he would have had to change that option also. Such is the situation in Delhi today.

I will speak about Delhi and then move on to other parts of the country. The main reason for the environmental problems in Delhi is because of North Westerly winds settling almost in Delhi and the power plants surrounding Delhi, especially coal based power plants, not having the perfect FGD.

(1645/KDS/NKL)

So, the SO_x and NO_x levels are a little higher compared to the international norms. The dust pollution, the SO_x, and all such pollutants, because of the lower wind velocities and because of the temperature in the winters, are getting settled here. So, ideally, we should look at the solution where power can be transmitted from a distance. Now, we also have the National Grid. We should dismantle the plants, as much as possible, in and around Delhi or within the 100 kilometres of radius, and move them away. The hon. Prime Minister is giving a lot of impetus to renewable energy, especially the solar and wind. Since we have the national grid, we should move more towards the renewable energy. We cannot avoid coal-based plants but we should move them far away from the habitations, especially from Delhi.

The other problem for Delhi is stubble burning which is done in Punjab and Haryana. There is a solution for that. All the Western Countries have banned stubble burning almost several decades back. For us, there is a solution. If we

provide the cutting machines to the farmers, where it can be cut into pieces and thus, can be spread over, it would really help. But the problem is, adequate number of cutting machines are not being provided. So, ideally, the Government should give a special subsidy or maintain a Budget to supply the cutting machines to the farmers. If that menace of stubble burning can be stopped, then, to some extent, it could be settled.

The main thing is that we must do the plantation as much as possible. If there is any new colony coming up for development in and around Delhi or anywhere in the country, you put a stringent stipulation that you have to come up with this much plantation. For example, if the area is 1 square kilometre, you stipulate that some 30,000 or 40,000 plants have to be planted there, and if there is any shortage, you put a penalty on them.

Last week, I had been to Varanasi and I had seen all the diesel vehicles plying around the Temple there. Wherever diesel is permitted, they are putting Kerosene too. That has to be banned. But in Varanasi, in general, all the vehicles plying were battery vehicles. We must improve public transport. We must promote electric vehicles. ...(*Interruptions*) Sir, please give me two more minutes.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude now.

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): I will conclude shortly. I know my limitations.

The initiative taken by the hon. Prime Minister, especially the fight against single use plastic, is a great move. ...(*Interruptions*) Here, I have one suggestion. Like Swachh Bharat Committees, we must go in for Paryavaran Parivartan Committees. If some impetus is given to that, and if we have these Committees at village level, a lot of problems can be sorted out at that level and they themselves could come up with good ideas.

My final request to the hon. Minister is this. Under the MGNREGA Scheme, if we can also bring in the issue of environment as a part of it, that would be better. There are several ways of doing it. The people can also take part voluntarily wherein they will also get the remuneration, and the Government can utilise the man days. By doing so, we can have the safest environment very soon. I hope that the hon. Minister would take at least some of these points into consideration. Thank you.

(ends)

1649 बजे

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस तरह के टॉपिक पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया- “एयर पॉल्यूशन एण्ड क्लाइमेट चेंज”। मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष से बनी। जब यह सृष्टि बनी, तो उसे बनाने के बाद परमात्मा ने यह सोचा कि इतनी सुन्दर सृष्टि बनाई है, पर्वत बनाए हैं, पेड़-पौधे बनाए हैं, पशु-पक्षी बनाए हैं, लेकिन इनको देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इंसान को बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वह भूल गए कि जिस इंसान को उन्होंने बनाया है, वह प्रकृति की सुंदरता को देखने के साथ-साथ इस प्रकृति को खराब करेगा, इसको पॉल्यूट करेगा। मुझे लगता है कि इसके बारे में वह सोचना भूल गए।

(1650/MM/SRG)

हम कहते हैं कि हर इंसान में आत्मा है और आत्मा में परमात्मा है। मुझे लगता है कि अब वह पछता रहा होगा कि थोड़ी सी समझ अगर हम इसके बारे में भी इंसान को दे देते कि वह इस प्रकृति को किस तरह से बचाकर रखे तो मुझे लगता है कि शायद उसको अब बैठकर पछताना नहीं पड़ता।

महोदय, जितनी भी गैसों का विसर्जन होता है, चाहे हम कार्बन की बात करें या सल्फर मोनोऑक्साइड की बात करें, उस गैस के उत्सर्जन को प्रकृति एब्जॉर्ब करती है। अगर हम सिर्फ उत्सर्जन की तरफ ध्यान देंगे और उसके एब्जॉर्प्शन की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो नेचुरल सी बात है कि इकोसिस्टम में गड़बड़ होगी और उसकी वजह से आज कोई इधर खांस रहा है तो कोई उधर खांस रहा है। मैं यह कहना चाहूँगी कि इसमें चार तरह के पॉल्यूशन के जरिये हैं। हम वाहन से पॉल्यूशन करते हैं, हम उद्योग से पॉल्यूशन करते हैं, हम कचरे से पॉल्यूशन करते हैं और स्टबल या कचरे की बर्निंग से पॉल्यूशन करते हैं। महोदय, मैं हर पहलू के ऊपर बात करके उसके लिए कुछ सुझाव भी देना चाहूँगी। हम सब यहां प्रॉब्लम की बात करते हैं लेकिन सॉल्यूशन की कोई बात नहीं करता है। दिक्कत के बारे में बात करते हैं, सरकार ने क्या नहीं किया, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन की बात नहीं करता है। हमारे प्रधान मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो हमें दीजिए और आपने देखा होगा कि वह उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सबसे पहले अगर मैं व्हिकल के पॉल्यूशन की बात करूँ तो 25 से 30 परसेंट तक लाखों वाहन हमारे हिन्दुस्तान में चलते हैं। उसकी वजह से जबरदस्त पॉल्यूशन होता है। इसलिए सरकार की तरफ से, जहां तक मुझे पता लगा है कि वर्ष 2014 में बीएस-3 ग्रेड का फ्यूल मिलता था। वर्ष 2016 में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई तो बीएस-4 का फ्यूल स्टार्ट किया गया। वर्ष 2019 से एनसीआर में बीएस-6 ग्रेड का फ्यूल उपलब्ध कराया गया है। हमें उम्मीद है कि वर्ष 2020 से बीएस-6 ग्रेड का फ्यूल और वाहन हमारी सरकार पूरे देश में लाने जा रही है। यह बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारी सरकार का है और मुझे लगता है कि आगे इसमें और भी तरक्की होगी। इसके साथ ही साथ सरकार ने ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस-वे बनाए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में आने वाले वाहनों में कमी आई है। अगर मैं उद्योगों की बात करूँ तो हमारे उद्योगों से भी बहुत पॉल्यूशन होता है। हमारे सिरसा में घग्गर नदी पंजाब से होकर आती है। पंजाब के जितने भी उद्योग हैं, चाहे वह

जूता फैक्ट्री हो या अन्य कोई हो, वह उसको इतना पॉल्यूट कर देते हैं कि सिरसा के आस-पास रहने वाले लोगों को जबरदस्त बीमारियां हैं, कैंसर है, और भी बहुत सी बीमारियां हैं। हमें यह चाहिए कि जिस प्रकार से ब्रिक क्लिन से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है तो उसमें एक जिग-ज़ेग सिस्टम है। अगर हम इस जिग-ज़ेग सिस्टम को लगाएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। पीएनजी गैस का प्रयोग हम शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे सुझाव हैं अगर हम अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से भी मिलकर सुधारने की कोशिश करें तो हम इसमें बहुत कुछ सुधार सकते हैं। कचरे से पॉल्यूशन होता है, जिसमें सॉलिड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की धूल है। सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कारखाने लगाएं तो मुझे लगता है कि हम इसको काफी हद तक रोक सकते हैं। इसके अलावा वन विभाग को बहुत ज्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। एनएच की हम बात करें तो सिरसा से डबवाली तक जो एनएच जाता है, वहां पहले बहुत ज्यादा पेड़ होते थे। उन पेड़ों को काटने के बाद उसको फोर लेन का किया गया लेकिन उसके बाद से अभी तक वहां पेड़ नहीं लगे हैं। अगर आप अभी जाकर देखें तो वहां बिलकुल खाली पड़ा हुआ है। वह इलाका है, जहां हमारे किसान जब धान की खेती करते थे तो वे पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते थे और उसका धुआं यहां तक नहीं पहुंचता था। यह बहुत बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि वन विभाग को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम स्टबल बर्निंग की बात करें तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। हम किसानों को सिर्फ दोष न दें। पराली में क्या है? पराली में दो तरह की धान होती है। एक बासमती और एक नॉन-बासमती होता है। जो बासमती है उसकी पराली को फॉडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

(1655/GG/RP)

लेकिन जो-नॉन बासमती है, उसी का ही पराली बनता है। तो इसमें दो तरह से हमारी हरियाणा सरकार ने कोशिश की है। एक इन-सीटू ऑपरेशन और एक एक्स-सीटू ऑपरेशन के माध्यम से। इनसीटू में कोशिश की जाती है कि हम किसानों को इसके बारे में अवगत कराएं कि आप अपनी पराली को वहीं पर ही इस्तेमाल कर लेते हैं तो वह खाद के रूप में इस्तेमाल हो जाएगी। उसको काटने की जरूरत नहीं है। एक्स-सीटू में क्या होता है कि अगर आप अपनी पराली को काटते हैं तो ऐसी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में उसका इस्तेमाल किया जाए, जहां पर ईंधन की जरूरत होती है। हमारे हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री ने छह ऐसी फैक्ट्रीज़ को चिह्नित को किया है। इसके साथ-साथ सभी किसानों को सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे देने की बात कही है। इसके साथ-साथ एक हजार रुपये ऑपरेशनल चार्जस के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है।

महोदय, मैं डाटा ले कर आई हूँ। आप देखें कि 55,523 लोकेशंस पंजाब में ऐसी हैं, जहां पर स्टबल बर्निंग हुई और हरियाणा में सिर्फ 6429 हुई है। लेकिन कहते हैं न कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो सब कुछ किया धरा पंजाब ने और नाम हरियाणा का आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, वह हमारा छोटा या बड़ा भाई है। क्योंकि सन् 1966 में पंजाब से ही हरियाणा अलग हुआ था। लेकिन फिर भी कोशिश यह है कि हम सब मिल कर इसका कोई न कोई समाधान निकालेंगे, तभी बात आगे

बनेगी। मैं कहना चाहूंगी कि एक पूसा-44 वैरायटी है। अगर इस वैरायटी की जगह पर हम कोई दूसरी उगाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पराली इसी से होती है तो क्यों न हम कोई ऐसी रिसर्च कर इसके ऑल्टरनेट ऐसी वैरायटी ले कर आए ताकि पूसा 44 को हम आगे से उगाएं ही ना इसी के साथ-साथ क्रैकर्स से भी होता है। हम दशहरे के उपलक्ष में जगह-जगह पर रावण जला देते हैं। लेकिन अपने अंदर के रावण को खत्म नहीं करते। क्या आपको लगता है कि रावण के पुतले जलाने से हम उन बुराइयों को खत्म कर देंगे? मुझे लगता है कि बहुत सख्त जरूरत है कि अपने अंदर के रावण को खत्म किया जाए। ठीक है रावण बनाइए, लेकिन उसके अंदर या तो ई-क्रैकर्स इस्तेमाल कीजिए या फिर कम से कम एक जिले का, एक ब्लॉक का मिला कर एक बना लीजिए। हम जगह-जगह पर जलाते हैं तो उस वजह से भी प्रदूषण होता है। क्योंकि समय यही है। पहले बच्चे कहते थे कि दिवाली फैस्टिवल कब आएगा हमारी छुट्टियां होंगी। अब कहते हैं कि पॉल्युशन फैस्टिवल कब आएगा, क्योंकि हमारी छुट्टियां होती हैं। बच्चों को अब पॉल्युशन फैस्टिवल का भी इंतजार होता है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पिछले दिनों पैरिस में समिट हुआ, उसमें यूएस के राष्ट्रपति साहब ने भाग नहीं लिया तो मेरी सभी सांसदों से गुजारिश है कि क्यों न हम सब एक लैटर लिख कर ट्रंप साहब को रिक्वेस्ट करें कि देखिए सबसे ज्यादा पॉल्युशन यूएसए करता है तो क्यों न आप उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अभी ब्राजील में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी गए थे। जो अमेज़ॉन जंगल है, उसके अंदर पांच हजार करोड़ का जंगल बिल्कुल भस्म हो गया है, जल गया है। मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए ये फेफड़े हमारे हैं।

मैं अपनी बात को दो ही मिनट में खत्म करना चाहूंगी। मुझे तो कई बार कष्ट होता है कि हमारे यहां पर सुप्रियो जी बैठे हैं, यहां पर रवि किशन जी, हेमा मालिनी जी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। कोई समय था कि हवा पर कितने गाने बनते थे। जैसे कि 'जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा'। अब आगे आने वाले समय में सुप्रियो जी कैसे करेंगे? 'हवा-हवा ए हवा खुशबू उड़ा दे'। अरे अब यह चारों तरफ पॉल्युशन रहेगा तो हम किस तरह से करेंगे? मुझे तो बॉलीवुड के लिए भी चिंता होती है। जिस तरह से हेमा मालिनी जी ने व्यक्त किया कि वे मथुरा-वृंदावन से आती हैं और उन्होंने बताया कि वृंदावन में किस तरह से बंदरों से दिक्कत आ रही है। वृंदावन का अर्थ होता है - वृंदा माने तुलसी, और वन माने वन, अब कहां वे वन रह गए हैं तो क्यों न हम कुछ न कुछ ऐसा करें। मेरा एक और सुझाव था। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Hon. Member, please conclude now. ... (व्यवधान)

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): सर, दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रही हूँ। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. You have to conclude now.

Shri Anubhav Mohanty. ... (व्यवधान)

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): ... (Not recorded) अभी क्लाइमेट चेंज पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। तुलसी का वन होने की वजह से वृंदावन कहा जाता है। मैं चाहती हूँ कि गांवों की ग्राम पंचायतों की गोचरण भूमि पर जंगल भी उगाए जाएं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सन् 2022

तक सबके पास छत होगी, सबका मकान होगा, लेकिन हम इसके साथ-साथ पशु-पक्षियों के मकानों को तोड़ रहे हैं। ... (व्यवधान)

(1700/RCP/KN)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please come to the main point and conclude. Come to the last point.

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): सर, मैं अंतिम बात के साथ कहना चाहती हूँ कि-

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः।

नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्॥

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(ends)

1700 hours

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Thank you so much, Sir, for giving me the opportunity. As a young man of India, I feel very much responsible because we are talking about a healthy India for ourselves as well as for our next generations.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): सर, मैं यह कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने लास्ट में मेरा नाम भी लिया। हम सारे प्रयत्न कर रहे हैं...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मिनिस्टर का माइक ऑन कीजिए।

श्री बाबुल सुप्रियो : सर, बहुत सीरियसनेस के साथ और बहुत दिल से हम यह कोशिश कर रहे हैं। आपने गानों का जिक्र किया, आपने मेरा भी नाम लिया। आप बहुत जल्द, भले ही दो साल में हो, लेकिन जितनी जल्द से जल्द आप गा सकें कि 'हवा के साथ-साथ, घटा के संग-संग हो साथी चला' यह मैं बताना चाहता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Minister. Mr. Anubhav, please continue.

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): क्या बात है दादा, आपने तो पूरा माहौल ही बदल दिया।

Sir, clean air costs money all over the world. In other words, there has to be a cost to keep your city or your country clean through proper pollution control measures, as we are doing, like planting trees, reviving waterbodies, odd-even formulas, clean environment technology, etc.

Clean energy cess is imposed by the Government but I wonder if there is any kind of annual target set for this so that, every year, they check that this is our achievement; this was our goal; this is where we had to reach; and whether we achieved that goal.

Similarly, to persuade farmers to wean away from the age-old practice of stubble burning, a cost has to be borne by the Government in the form of direct cash incentive or incentivising them to use the stubble to generate additional incomes. For example, the noted agricultural scientist Swaminathan ji – I was just going through one of his articles yesterday – has suggested development of bio-parks and conversion of stubble to very rich manure. This manure can be sold in the market or either bought by the Government itself giving additional income to the farmers. Similarly, the students of Bennett University in Greater Noida have innovated a technology to convert stubble to very high energy fuel. The market value of such fuel could be passed on to the farmers to encourage them and give them additional income. Basically, I want to emphasise that for sorting out the current environmental problem in Delhi or anywhere in the country, merely coercive measures on farmers would not be enough. This problem would not be sorted out by this. We cannot be so much coercive towards the farmers. Rather, we have to adequately compensate them as a cost for getting clean air in Delhi. I am sure, this cannot happen overnight.

For this, I would request the Government that they should extensively join the communities in villages. जैसे गाँव में होता है, पंच होते हैं या सरपंच होते हैं, उनके साथ अगर एक्सटेंसिवली गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करे, जॉइन करे, सब के साथ में एक अवेयरनेस क्रिएट करे कि we will incentivise you through this. आप जिसको जला रहे हैं, उसको न जलाएं। उससे मेन्योर बना कर बेचा जाएगा या हम आपसे जो खरीदेंगे, उससे पैसा आएगा, it can be added to your income as a bonus. So, they might slowly and gradually change this age-old practice for a healthy today and tomorrow and to convert negative income into positive income.

Air pollution due to vehicles at traffic arises because of movement of freight vehicles and highly polluting heavy and ultra-heavy motor vehicles over long distances. A time has come to seriously consider, in a phased manner, shifting to inland water corridors to substantially reduce this pollution. I would request the hon. Minister to kindly think on this. May be, inland water corridors substantially reduce air pollution in certain ways and in future in a bigger way.

(1705/SMN/CS)

Sir, development of carbon sinks in urban cities is a must and these carbon sinks are not just to be developed in gardens and parks. This requires careful selection of different varieties of carbon sequestering plants and trees.

The Government of Odisha under the dynamic leadership of Shri Naveen Patnaik Ji is actively considering to set up carbon sinks in different parts of the State and encouraging private sectors to do so. Some of the outstanding researches in recent times have revealed that a particular type of algae is most suitable for sequestering carbon emissions. We could explore the possibilities of using such algae over non-religious water bodies and ponds. We can use it in parks and tourist spots which are highly polluted in urban cities.

I would like to thank you for giving me an opportunity and at the same time, I would like to express my gratitude for such a wonderful debate by so many wise people. I expect hon. Minister's reply would assure us a healthy and safe place to live and develop together.

Long live India. Jai jawan, jai kisan.

(ends)

1706 hours

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Thank you very much Chairman Sir for letting me speak on this subject.

So far as ecology is concerned, in the modern times with the modern civilizational issues, it has been a subject since 1866, and it has been defined by Ernst Haeckel only in 1866. We all come from a country, a country of Vedas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata which is actually based on nature-based religion.

Our religion itself is nature-based because when I look at the hymns of Rig Veda, 1066 hymns are there which are all about nature. You look at Yajur Veda and Atharva Veda. They are all about earth and how I am a son of the earth. *Bhoomi sukta* says that earth is *vishambara*, that is all bearing. Earth is *vasuda* - all propitiating and earth is mother earth which is life to everyone. That is my religion.

So, Vedic to Indic civilization is all about nature. That is my culture. If I look at my own country, I see that in the past 15-20 years, we have wasted our country.

1707 hours

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

It has been a waste of our nation. When I say 'waste', we have, instead of progressing which we did, we have progressed economically. We did make progress but we polluted it. In terms of pollution, today, the climate change is a change which is impacting not only the ones who have polluted but also all these civilizations which are talking of carbon emission, how neutral ideas need to be brought in and how solar energy needs to be saved and secured. They are the ones who have polluted the earth; they are the ones who have exploited the earth; and they are the ones who used the most the resources and yet, they are high consumption resource-based technologies which they have used in the past. Today, we talk unscientifically.

I am sorry to say this. It is not that the pollution is not caused by fire-crackers alone. Pollution is caused by fire-crackers. But I heard one of the Members saying that in Hong Kong, the atmosphere is very good because they use cold technology. On the contrary, it is opposite. The Cold technology and other technologies used for fire-crackers are far more poisonous because they

are leading to gaseous pollution which cannot be seen by eyes but it is responsible. The entire debate about fire-crackers has led to a lot of unemployment in Tamil Nadu, and Sivakasi has lost a great deal of employment, whereas pollution in Delhi remains the same as it was before the fire-crackers and after the ban has been imposed.

The fact is that we are today talking as if we are in dark ages. There is unscientific connotation to a scientific subject. I think, it is time for us to think of science and find scientific solutions with scientific technologies. The cultural heritage of this country is so strong that we are taught earth is not meant for humans alone, unlike many other religions which say earth is manned to be exploited by the human-beings and man is the superior most in this world, not even an animal being.

(1710/MMN/RV)

In our country, in our religion, in our ethos, we are told earth is not meant for humans alone but earth is meant for plants; earth is meant for animals; earth is meant even for inanimate objects. 'हर कण में राम', 'कण-कण में राम' - this is what Tulsidas says. सर्वं खल्विदं ब्रह्म - that means everything is Brahma. The interaction between living and non-living is as important. *Parvat* is my *pita*. Earth is my *mata*. With every God, we have a plant. अगर विष्णु जी की पूजा करनी है तो तुलसी है और शिव जी की पूजा करनी है तो बेल है, बेलपत्र भी है। अगर गणेश जी की पूजा करनी है तो उनका वाहन मूषक भी है, गरुड़ भी है।

So, there is a connectivity which is established and by that connectivity, you have revered everything that is spiritual. This thought is what is missing in the entire discussion. With this kind of ethos, with this kind of background, I think it is time to address the issue of integral humanism. Integral humanism means that we are all connected. The animate and the inanimate has a deeper connection. When we discuss ecology, we come to Millennium Development Goals which were, of course, unsustainable. So, we came out with Sustainable Development Goal which is nothing but simplified integral humanism. Then, we put all this together.

I heard one of my friends discuss the coughing. When he is out from Thiruvananthapuram to Delhi, he starts coughing. So, I said, कि ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया) का असर दिखाई देता है कि अगर मुझे खाँसी है तो पूरी दिल्ली को होनी चाहिए, ऐसा लगता है। जब दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली के विषय में, खास तौर से अगर मैं बात करूँ तो क्लाइमेट चेंज एक इंटरनेशनल, ग्लोबल इश्यू है। चाइना की बात की और चाइना के अन्दर बोला गया कि अगर हम पॉल्यूशन से बचे हुए कार्बन को इकट्ठा करते हैं, if we collect the ash, we are able to produce diamonds. Now my point is, when we are able to produce diamonds out of collecting ash from the air, why are we not producing diamond from the coal which is being used by our power stations for the production of energy? So, at the end of the day, it is about replacing technology or integrating technologies. The idea is not against using coal but how we manage the coal air and the effluents from coal. That is the issue. The issue is not that, stop using coal. The issue is, when we use coal, what do we do with the effluents? That is where we are missing in action. On the contrary, a pressure is built on India to stop using coal. If you can make diamond out of the emissions of air and make diamond out of the air in Beijing, you might as well keep on making diamond out of all the coal that is being utilised by the power stations. Then, I think everyone will make more money.

The idea is replacing technologies and not to get trapped in the issue. We are the least consuming country in the world and let us not get trapped by these kinds of conversations. I am happy that when the Prime Minister represented the country in the UNGA, we are an ODF, Open Defecation Free, country. We have recently achieved the status of an ODF, Open Defecation Free, country. Who thought India will achieve this in five years? But we did it. When we are cleaning Ganga and cleaning other rivers, then it has been done in a mission mode. The entire railway tracks have been cleaned up by using bio-toilets. So, if we decide to achieve, I am very sure we are going to achieve it.

When we start discussing Delhi pollution, I think every urban city in the world has gone through the same process and we need to work at finding the solutions. Now, when I look at Delhi, I feel very sad because we are again having some unscientific conversation. When our Chief Minister spends Rs.700 and odd crore on advertising his own face, that is not worth it. I think the 'worth-it-effort' should be, how do we deal with the C&D waste of Delhi? It is because when you look at the Delhi pollution, you find PM-2.5 particles; you find PM-10

particles in the air and that is the dust which we need to control. That is where we need to work in controlling the dusts. When I discuss the dust pollution, it was very rightly pointed out by my friend from YSRCP. He said that it is the North-Westerly winds which have resulted in pollution in Delhi. That is partly true but partly it is the amount of construction in Delhi. As a city which is coming up and where people from across the country and the world land up, the facilities and amenities need to be provided. Unfortunately, we have seen disoriented urbanisation of the city. It is not a planned city.

(1715/VR/MY)

When I look at the dust, the thing which comes to my mind is that soil becomes dust when it loses its humus content. How does it lose its humus content? It loses its humus content because whatever we take from earth needs to be replenished that is what the *Vedas* say. Unfortunately, we are not replenishing it. The humus content in the soil is going down by the day and that top soil is getting lost by the air. If the humus content is high in this soil even by 5 per cent, we will get all the *kharpatwar* (weeds) and all kinds of plants growing over it. When the plants grow over it, the top soil will remain in the earth and there will be less dust. The moisture or water content of the soil will go up.

Sir, I just want to mention one point. Everybody has discussed Delhi. Unfortunately, the Delhi's MPs have not got the proper time. So, I request that I should be given adequate time to represent Delhi. Otherwise, people in my constituency will say that while I was sitting in Parliament, what did I do about pollution in Delhi.

Air pollution is one aspect in which increasing the humus content of earth in a strategic manner across the country is the work we need to do. The Aravalli jungle which provides green cover to the whole region has been cut and we need to work at that strategy.

So far as water table and water pollution is concerned, all the heavy metals like arsenic, cadmium and chromium, ये सब जमीन के ऊपर आए हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वह यह है कि आपने लोगों को पानी नहीं दिया है। आपने न उसकी मात्रा ठीक की और न ही उसकी क्वालिटी ठीक की। जब मात्रा और क्वालिटी दोनों ठीक नहीं हैं, तो लोगों की मजबूरी होती है कि वे ग्राउंड वाटर को खींचना शुरू करते हैं। इसलिए सभी को पाइप वाटर सप्लाई मिलनी चाहिए। यदि एसटीपी प्लांट पूरी कैपेसिटी से अधिक काम कर रही हैं, तो जाहिर तौर पर वह आपको खराब पानी दे रहा है जब हम बी.आई.एस. की बात करते हैं, तो वह ब्यूरो ऑफ इंडियन

स्टैंडर्ड्स है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर शक करना गलत होगा, क्योंकि वह पूरी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस कर रहा है।

जहां तक पानी का विषय है, जब हरियाणा से दिल्ली में पानी एंटर करता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिडिंग कैपेसिटी अधिक होती है और उसमें जो ई.कोलाई की मात्रा है, वह कम है। जब वह पानी दिल्ली छोड़कर हरियाणा जाता है, तो ई.कोलाई की मात्रा भी आठ गुना हो जाती है, कई सौ गुना बढ़ती है और उसकी ऑक्सीजन कैरिडिंग कैपेसिटी समाप्त हो जाती है।

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Please conclude.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): This is not fair on Delhi. I represent Delhi and we have all been discussing Delhi.(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You represent the whole country and not Delhi only.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Let me say that one and a half to two minutes is the time that Delhi MPs have taken. I request you to give me adequate time because there is a constant discussion in Delhi about pollution. I need that time. I have a request to make.(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: This is not a discussion on Delhi. The discussion is on Delhi's pollution.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, it is not just the entire country but the world is talking about Delhi's pollution. Wherever we are going, everybody is talking about Delhi's pollution.

Sir, let me just complete in a few words. When we discuss economics, it is about managing the deficit resources. But every time there is economics, commerce comes with it. When commerce comes with it, in Delhi the commerce of water tankers is what is working. दिल्ली में माफिया वाटर टैंकर का काम करते हैं। जब पानी नहीं होगा, तो उसका कॉमर्स व्यापार चालू हो जाता है। जब व्यापार चालू होता है, तो अनअथोराइज्ड लोग उसमें पैसा कमाने का काम शुरू कर देते हैं। वही हाल आज हवा के साथ हो रहा है। जब हवा के लिए काम नहीं किया जाएगा, आप सिप्रिंकलर सिस्टम पर पैसा नहीं खर्च करेंगे, 700 करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च करेंगे, आप पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, हवा की सफाई करने की व्यवस्था नहीं करेंगे, सी एंड डी वेस्ट की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा विज्ञापन चला था, कई होर्डिंग्स लगे थे कि जहां भी सी एंड डी वेस्ट होगा, आप उसका फोटो खींचकर भेजिए, हम सी एंड डी वेस्ट हटाएंगे। आज न तो वह सी एंड डी वेस्ट हटा, न ही हवा ने उसको सक किया है और न ही कोई काम हुआ है। इतना जरूर है कि वहां विज्ञापन के लिए पैसा निकल गया। दिल्ली में जो वाटर सिप्रिंकलर सिस्टम शुरू होना चाहिए था, वह भी शुरू नहीं हुआ।

माननीय सभापति: प्लीज, अब आप कंकलूड कर दीजिए। अभी यहां पर काफी लिस्ट हैं।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): महोदय, अगर आप कहेंगे, तो मैं एक-दो लाइन में कंकलूड कर दूंगी।

HON. CHAIRPERSON: It is a national issue and not an international one.

(1720/CP/SAN)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): आदरणीय चेयरपर्सन सर, अंतराष्ट्रीय विषय दिल्ली को बनाया गया है, इसलिए मैं अधिकृत रूप से आपसे दरखास्त कर रही हूँ कि दिल्ली का विषय, जिसमें भारत की बदनामी होती है, उस पर कम से कम दिल्ली के सांसद को तो पूरा समय मिलना चाहिए।

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): You are in the Panel of Chairpersons also. Please cooperate.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): मैं कोआपरेट कर रही हूँ। मगर इस बात का दुख कहीं न कहीं लगता जरूर है कि आखिरी में बोलने को कहेंगे और मेरे बाद एक या दो स्पीकर हैं, मंत्री जी आ गए हैं, तो वह तकलीफ होती है।

Anyway, I am concluding. If we are talking of Sustainable Development Goals and if we are talking about climate change, enough conversation has happened. I think, इस संसद का हर एक व्यक्ति क्लियर है, स्पष्ट है अपने काम की तरफ और स्ट्रेटिजी की तरफ।

We have to talk global, but we have to think local and we have to act local. मैंने अपने क्षेत्र के अंदर कंपोस्टिंग प्लांट्स लगाकर, जो आर्गेनिक वेस्ट है, उसको मैनेज किया है। हम लोगों ने प्लास्टिक कलेक्टिंग मशींस कई जगहों पर सीएसआर फंडिंग और अन्य माध्यमों से लगाई है, ताकि प्लास्टिक को अलग किया जाए। एक बार प्लास्टिक अलग हो जाए और अगर हम जीरो प्लास्टिक शहर बना दें, तो बहुत तक पोल्यूशन कंट्रोल होगा। यह समय है कि हम अपनी पुरानी पद्धति पर चलें।

(इति)

1721 hours

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on such an important subject under Rule 193.

Pollution and climate change have definitely been one of the most important problems not just for this country but for the entire world also. I am glad that this discussion is happening today because it is the need of the hour. It is very delightful to see some of the suggestions and the way people have responded towards this debate. They were showing hope that there is still a chance for us to act and to show a better way forward to the future generations also. I would like to be a part of the bigger debate of helping this country move forward in the right direction.

Definitely, the alarm bells went ringing after the recent Delhi scenario that has happened. I do not think anyone would disagree when I say that the smoke that has come up in Delhi is not just happening here; the fire has lit all over the country. Maybe the situation that is happening in Delhi is slightly ahead of times here because of the population, because of the way things are moving forward, but definitely we see this scenario hitting even the rural villages of this country. So, definitely, it is time when we need to act on this on a very serious note.

More than that, the attitude of this country, the Government and ours has to change. Definitely, we can speak on this issue. We have seen many good solutions that have come forward. So, the attitude should be not about what we are saying, but the attitude should change to what we are doing for this. That is the need of the hour today that we move into how we address this and what we do in terms of this.

Environmental consciousness is present across the world and it has been a very primary concern for the last 40 to 50 years, but if you consider India, it is there in our DNA and we in the Indian culture have respected environment. Even if you look at our traditions, our culture and everything, it comes with a basic connection with the nature. So, we are proudly associated with the nature, but somewhere in the last 30-odd years, in terms of achieving growth, in terms of achieving development, and in terms of copying the western world, we have somehow missed the link with nature and we have not been on the right path.

We can say that much. That is why, there is a responsibility on the Government of the day to take some extreme steps also.

I would like to quote a couple of lines, a couple of ideas from our Father of the Nation, Mahatma Gandhiji where he said that nature has enough to satisfy one's needs, but not to satisfy everyone's greed. These are the important words coming from Mahatma Gandhiji. He also pointed out in *Indian Opinion* dated 1st February, 1913. He said this in 1913 – 'The structure of the human body requires three kinds of nourishment – air, water and food. Of these, air is the most essential aspect. Consequently, nature has provided it to us to such an extent that we can have it at no cost, but modern civilisation is putting a price even on that.' That is happening today also that there is a price on air.

If you look at this in depth, the country or the society was divided because of the economic, financial situations. There are the rich, there are the poor, there is affordability and there is standard of living. Now, you see that in terms of environment also, this economic divide is creeping in. A hard-working labourer cannot even have access to fresh air where he is not even responsible for creating any kind of pollution.

(1725/RBN/NK)

He is just sweating it out day in and day out and working hard to earn money. He is just sleeping outside to get fresh air and good sleep. He is not able to do that. The rich are able to buy oxygen chambers and air purifiers. They are able to take detox vacation to some islands, etc. where they can get some fresh air. But what about poor people of this country?

The recent situation in Delhi is a very big example of children not being allowed to go to school, not being allowed to play. That is the kind of situation this environmental effect will have on the society and on the future generations also. So, that is why this should not be just looked upon in a very narrow way. Things are much broader than the way they look.

My request to the Central Government would be to create a national action plan or some environmental policy. If the Government is willing enough, it can come out with some kind of law by which the people of this country are made to follow strict measures. I would like to appreciate the efforts of hon. Prime Minister. He has been going across the world, telling them that we are committed

to this and that we are going to be the role model. But look at the situation. ...(*Interruptions*) Please allow me to speak for five more minutes.

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Please conclude. So many Members want to speak on this subject.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): I understand. I am a constant victim of this time constraint.

Let us create a law and let us use the principle of 'polluter pays'. It is because whenever an environmental policy is adopted, the core of that policy has always been whoever is going to pollute he is going to pay the price and whoever is going to help in saving the nature or in helping to combat this kind of problem he is going to be incentivised. So, let us go with this kind of principle.

We have to keep in mind some of the stakeholders. One is the farmers. Many hon. Members made this point. Farmers are being affected by this problem. We have seen this recently in Maharashtra. It happened in my constituency, Srikakulam in Andhra Pradesh. Due to unpredictable rains, the farmers had to pay the price. He has no solution to this kind of unseasonal rains or cyclones or natural disasters that are happening because of the climate change. So, definitely the Government has the responsibility to take them in account and to take sustainable measures.

The other stakeholder is the fishermen. I have to wish them because today is the World Fisheries Day. Definitely there has to be a discussion on them also. Due to the rising sea levels because of the climate change, the most affected will be the fishermen. Their livelihood, their security of having a home are all affected. So, when we create a policy, definitely we should keep these stakeholders in mind.

Like we are discussing pollution today, we have to discuss the issue of population also. In the last 30 or 40 years, population has been increasing at an exponential rate.

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): I am concluding within two minutes. I am left with just one page. We will come up with a bigger number next time. We did not know that our time will be so much affected.

Due to increase in population, there is a lot of stress on the environment and on the resources that we have. The rate at which the population is increasing, in the next 30 or 40 years, it is very difficult to even imagine the kind of scenario that the country would be facing. So, that is why I request that in terms of being a world leader, we have to take some strong steps in dealing with this problem.

There is one other important issue. When you create this policy, the States need to be taken on board. By way of an example, I would like to cite the case of Andhra Pradesh. Previous Chief Minister, Shri Chandra Babu Naidu *garu* came out with PPAs with some companies to generate renewable energy. Those PPAs are being revisited by the present Government because it is not able to understand that ultimately it is going to benefit the Government and the people of Andhra Pradesh. They are getting into nitty-gritty which is helping neither the Government nor the investors. Everyone should fall in line. The Central Government has the primary responsibility. Now, you cannot just say that Gujarat is producing so much of solar energy and that Andhra Pradesh is producing so much of wind energy. We have to see a situation where all the brothers and sisters of this nation are made part of it. Even Himachal Pradesh and North-East should become part of this. This will happen only with effective policy.

(1730/SM/SK)

That is the responsibility of this thing. From where will we start? Sir, we will start right from here and right now. We already have a proposal of building a new Parliament. Let us build a new green building. Let us start from here. Let us have a good concept which can be a role model not for the Parliament Secretariat only ...(*Interruptions*). Wherever there is a building, let us have a new green building ...(*Interruptions*). I am just concluding.

It has been a wonderful debate and I appreciate all the comments that have come from the all the sides. I hope that the Government is going to take it seriously and come up with innovative steps which are going to make our future generations proud because they are all so much worried and it is our responsibility.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Shri Ritesh Pandey. You have only four minutes as you are the second speaker.

1731 बजे

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय सभापति जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एयर पॉल्यूशन मुद्दे पर मैं आदरणीय राम जी और शशि थरूर जी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अब एक नेशनल एयर पॉल्यूशन एक्शन प्लान की जरूरत है।

इस चर्चा का दूसरा मुद्दा जलवायु परिवर्तन है। मैं इस पर जरूर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। संसद में इस विषय पर चर्चा हो रही है, देश के लिए यह बड़ा मुद्दा है और भविष्य में बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

आतंकवाद और पाकिस्तान से ज्यादा अगर किसी चीज से खतरा है, तो वह जलवायु परिवर्तन से है। यह भी सच है कि आतंकवाद से ज्यादा जलवायु परिवर्तन से ज्यादा मौतें हो रही हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर बहुत ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अगर हम इस पर ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तो हम कहीं न कहीं भारतवर्ष के अस्तित्व को खतरे में डालने का काम करेंगे।

जलवायु परिवर्तन से किसानों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम किसानों के बारे में जीरो आवर, क्वैश्चन आवर, नियम 377 के अधीन चर्चा करते हैं। किसानों की कल्याणकारी नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं। जलवायु परिवर्तन किसानों पर सबसे बड़ा संकट बनकर सामने आ रहा है। आपको पता है कि नियमित मानसून में जो होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। अनियमितताओं की वजह से मानसून या तो बहुत लंबे समय में आता है या सूखा पड़ जाता है। यहां बिहार के सदस्य कह रहे थे कि उनके यहां मानसून आया, बहुत लेट आया, बाढ़ आ गई और पटना डूब गया। विदर्भ, महाराष्ट्र के सांसद कहते हैं कि इतने सालों से वर्षा नहीं हुई थी और इस बार इतनी लेट वर्षा हुई कि कपास और अंगूर की खेती बर्बाद हो गई। इसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है, सदन को इसका संज्ञान लेने की जरूरत है।

देश का 60-70 परसेंट किसान सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करता है। जलवायु परिवर्तन से अगर मानसून अनियमित काल में आएगा तो किसानों का कहीं न कहीं बड़ा नुकसान होगा। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में सरकार क्या कर रही है, इस पर विचार करना चाहिए। सरकार ने क्लाइमेट रिसीलिएंट एग्रीकल्चर इनीशिएटिव चलाया है। इसके तहत फसलों को और सहनशील बनाने के लिए रिसर्च हो रही है और सरकार ने करीब 47.56 करोड़ रुपया दिया। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि आज सदन में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा पांच करोड़ रुपया और खर्च किया गया। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है। किसानों पर जलवायु परिवर्तन का इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसे लेकर सिर्फ दिखावा हो रहा है। इस पर काम नहीं किया जा रहा है। आपको जानकर अत्यंत ही दुख होगा कि 47 करोड़ रुपये का बजट अधने से पेट्रोल पम्प के टर्न ओवर से, छमाही टर्न ओवर से भी कम है।

दूसरा विषय है, कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन का है। हमें इसके उत्सर्जन को कम करने के बारे में सोचना चाहिए। इस पर अच्छी नीति बनाने की जरूरत है। वर्ष 2016 में भारत ने पेरिस

क्लाइमेट एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए थे। इसे फॉलो करने की जरूरत है। इस पर पूरी ईमानदारी से चलने की जरूरत है।

हमारी अर्थव्यवस्था को क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की जरूरत है। सोलर इनीशिएटिव लिए जा रहे हैं, यह अच्छी बात है। वायु इनीशिएटिव भी लिए जाएं। इसके साथ हम परमाणु ऊर्जा की तरफ बढ़ें। आज हम देख रहे हैं कि भारत कोयले पर निर्भरता को बढ़ा रहा है।

(1735/MK/AK)

हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहां की तमाम कोयले की खदानों से यहां कोयला ला रहे हैं। यहां तक कि मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में एनटीपीसी का विस्तारीकरण हो रहा है और मुझे आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुःख होता है कि कई बार इस विषय को सदन में उठाने के बाद भी वहां के गरीब किसानों को खुजली हो जा रही है, वायु प्रदूषण से उनके ऊपर जो प्रकोप हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज वह समय आ गया है। हमारे देश में आज इसके ऊपर चर्चा हो रही है। यह बेहद और अत्यंत जरूरी है। हमारे मंत्री जी यहां बैठे हैं। जब यह डिबेट कन्क्लूड हो तो इससे एक ठोसी नीति निकलकर आए और एक कानून बने और हमारा देश आने वाले भविष्य को एक सुनहरा भारत देने का काम करे।

(इति)

1736 बजे

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि इस मामले में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है। इससे कोई घर, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई पत्ता, कोई झाड़, कोई चीज आज महफूज नहीं है। यह एक ऐसी चीज है, जिससे आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, परीदे सांस नहीं ले पा रहे हैं। लोगों को अपने बच्चों की जानों का खतरा है। इससे नई-नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी पैदा हो रही है। चूंकि समय कम है, पॉल्यूशन की वजह से बच्चों में हार्ट, लंग्स, गले और कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा बच्चों में पर्यावरण के कारण अनेक बीमारियां हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में तकरीबन 12 लाख लोगों की मौत एयर पॉल्यूशन की वजह हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में तकरीबन 76 मिलियन लोगों को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं है। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि अब जब भी थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो वह पानी की वजह से होगा। पता नहीं यह कहां तक हकीकत है, लेकिन यह डरने की चीज है। आज पूरे हिन्दुस्तान में हमारा मुल्क वाटर पॉल्यूशन और पॉल्यूशन की वजह से 1 से 10 नम्बर तक मुतासिर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल तक हमारे देश के तकरीबन 21 बड़े शहरों में ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा। आज बहुत परेशानी है, लोग पानी के लिए मारे-मारे फिर हैं, जंगलों में फिर रहे हैं। हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली को गैस का चैम्बर कहा जा रहा है क्योंकि घर से बाहर निकलकर सांस लेना मुश्किल हो गया है। यहां रहने वाले लोगों के लिए जिन्दगी गुजारना मुश्किल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। इसके अलावा दुनिया के 10 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से 6 हिन्दुस्तान में हैं। ऐसा नहीं है कि यह अचानक पैदा हो गया। यह इस वजह से भी पैदा हुई है कि हम लोग पॉल्यूशन के लिए जो कुछ करना है सब कर रहे हैं, वाटर लेवल को गिरा रहे हैं, लेकिन इसके इलाज के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इसको बहुत सीरियसली लें, उन्होंने इसको लाया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। चूंकि यह लोगों के जीवन का मसला है और आज आबु हवा कोई चीज इससे बची हुई नहीं है। इसलिए हम पूरे हिन्दुस्तान की, पूरे लोगों की तथा जानवरों पर भी रहम करना है। क्योंकि वे बोल नहीं सकते लेकिन वे हमसे ज्यादा घुटन में हैं। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): अजमल साहब का विशेष धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने समय-सीमा के अंदर समाप्त किया।

1739 hours

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak during this discussion under Rule 193.

It is learnt that a High-Level Task Force was constituted under the Chairmanship of Principal Secretary to hon. Prime Minister for the management of air population in Delhi in November, 2017. Accordingly, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change launched a National Clear Air Programme as a national-level strategy to tackle the increasing air pollution in Delhi.

Taking this into consideration, being the Member of Parliament residing in and representing Mumbai South-Central Constituency, I would request the Central Government to plan and implement efficient management programmes to abate the rapidly rising air pollution in Mumbai city, especially, in South-Central part as the concentration of industries and refineries are more in areas like Mahul.

(1740/SPR/RAJ)

The Mumbai City is currently facing tremendous problem of increasing air pollution along with unpaved dust, which has simultaneously given rise to acute diseases to the people of the city. Major sources contributing to air pollution are industrial emissions, vehicular emissions, road and soil dust, unpaved dust, construction and demolition activities, biomass and garbage burning, etc.

I urge the Central Government and the Minister of Environment, Forest and Climate Change to consider this rising issue and appoint a Committee to plan and implement measures for abatement of air pollution and unpaved dust in my Mumbai South-Central constituency.

Sir, Mumbai city's air is the most toxic in Maharashtra State. The rampant amount of unplanned construction supported by the rapid rise in vehicular emissions has resulted in Mumbai's air quality hitting toxic levels, with high concentrations of major air pollutants like sulfur dioxide, carbon monoxide, oxides of nitrogen etc. Out of 72 air quality stations in Maharashtra, only four have reported the Respirable Suspended Particulate Matter (RSPM) to be within the safety limits. The intake of RSPM beyond the safety levels is a matter of serious concern as the particles could get deep into the lungs leading to pre-mature death and respiratory and cardio-vascular diseases.

The Central Pollution Control Board set the permissible level of RSPM to be 60 Micrograms Per Cubic Meter (mpcm), while in my constituency, Sion

area in Mumbai recorded an average RSPM of 147 MPCM, which is the second worst in the State.

Rising pollution levels is not just the case of Mumbai but has become a growing phenomenon today across the metropolitan cities of the country. It is the urgent need of the hour to take immediate cognizance of the problem and develop solutions that would curb the rising pollution level without hurting the energy requirements of these growing cities.

We must develop more affordable, comfortable and eco-friendly modes of public transportation and invest in environment-friendly energy resources all over the country. This is essential not only for the coming generation to be able to breathe in clean air but also for the thousands of lives that are lost every year due to respiratory problems caused due to air pollution.

Hence, I would like to request the hon. Minister for Environment to help Maharashtra in developing and implementing a holistic plan focused on curbing the rising levels of air pollution in Mumbai.

Now, I would like to suggest some solutions to the problem of air pollution so that the Government would take care of it. Over 674 million Indians are likely to breathe highly polluted air in 2030. According to the studies of the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Austria and the Council on Energy, Environment, and Water (CEEW) in New Delhi, only about 833 million citizens would be living in areas that meet the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) in 2030.

In January 2019, the Government had launched the National Clean Air Program (NCAP), a five-year action plan, to curb air pollution, build a pan-India air quality monitoring network, and improve citizen awareness. The programme focuses on 102 polluted Indian cities and aims to reduce PM 2.5 levels by 20-30 per cent over the next five years. But the program lacks any form of legal mandate to ensure proper ground level implementation.

The study also found that the Indo-Gangetic plain, covering parts of states such as Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal, has the highest population exposure to significant PM 2.5 concentrations.

Transport emissions need a mix of public transport investments, behavioural change in transport patterns, and new transport technologies such as electric vehicles. Reactive solutions such as

banning waste burning or certain forms of transport are nothing but band aids.

A city-by-city approach is invariably limited. Much pollution occurs outside cities - by industry, brick kilns, power plants and crop burning. City boundary-based regulation only encourages emissions leakage such as relocation of industries to the outskirts. India has to develop regulatory institutions that operate at the level of the regional "airshed".

(1745/UB/VB)

A US based study that has been widely reported in the media over the past two weeks has projected that parts of Mumbai, Surat, Chennai and Kolkata would go under water by 2050 or be ravaged by recurring floods. Global sea levels have risen by eleven centimetres to sixteen centimetres, and under the best circumstances, they would further rise by another one-and-a-half metres. Additionally, the farm sector has been ravaged by untimely rainfalls, which is also the effect of climate change, resulting in the drowning of hundreds of villages and death of thousands of farmers. We can no longer afford to not take a strong stand against climate change.

It is true that India is a developing country, and we have pressing energy requirements for which we need coal. However, we need alternatives to counter the use of coal and reduce our carbon emissions. We also need to take a strong stand on the global stage against carbon emitting countries like the US, UK and China whose rapid emissions have resulted in the existential threat that we are facing today.

I would request the Government to come up with a legally binding mechanism to counter climate change and reduce the country's carbon emissions as climate change and its effects determine the existence of us and of our children.

(ends)

1746 hours

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I am glad that the two most important people who are required in this debate are here, the hon. Environment Minister and the hon. Health Minister because I think today's entire debate also connects both of them deeply.

The hon. Health Minister has substantially contributed. A lot of data has been sent. I will not get into this but he and I have worked closely for tobacco control. He has been a guiding light for us. Today's data says that air pollution kills a lot more people. I would urge him to take up this cause because when it was about tobacco control and polio, Dr. Harsh Vardhan made a substantial contribution over the last three or four decades. It is very, very important today to have this debate. I would even like to highlight to Prakash Javadekar ji that the District that both of us come from, and Meenakashi Lekhi ji was talking about Delhi at length, is Pune in Maharashtra. You will be surprised to know that both Prakash ji and I come from that area. In the area called Hinjawadi is the large Rajiv Gandhi Infotech Park. I just checked the pollution today, it is 427 there which is severe. There is nothing burning. Yes, there is a lot of traffic, but there is no factory anywhere around, still it is absolutely in the severe pollution range. I think we really need to put our minds that it is not just one thing in isolation which is deteriorating the entire air.

Since Dr. Harsh Vardhan is here, I would like to bring to his notice that the Health Report of 2015 said that the Air Act of 1986 needs to be integrated in the Health Policy. So, when you are expanding such a big Health Policy, if we can integrate this Act into it, I think it will really make a big change. We can put all our minds together and give you a lot of recommendations. But I think this Air Act has to be integrated with the Health Policy. A lot of countries like Brazil, New Zealand, Canada and Philippines are doing much better than us. They have an integrated plan with health and pollution.

I would also like to highlight a point which Ritesh Pandey ji made. He talked about the State Action Plan to control pollution. As a matter of fact, we just finished Maharashtra election and, in our manifesto, made by the Congress and the NCP, this is probably the first time, we have given three full pages to climate change and, in that, we have the entire plan ready to implement the State

Action Plan. It is there in the manifesto. If anybody would like to visit it, I would be happy. If you need any more information, I would be happy to share with you.
HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Please share it with everyone.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I have two-three quick points and questions. I would not repeat any points that everybody has made earlier. I would just like to ask the hon. Minister about the status of the CAMPA fund. The amount of Rs. 30,000 crore is given to the States for plantations. In our own State, the Government which is incumbent right now, has told us that it has planted millions of trees. I do not see them because in my own constituency, I would not talk about the State, I do not see a big change. So, how is the Government of India monitoring this exceptional amount of money? It is over Rs. 30,000 crore in the CAMPA funds which is going to all the States.

(1750/KMR/PC)

Who is spending it? How are they spending it? If so much money is going into the environment and the CAMPA fund, then how are we not seeing any change, any result? This is not about 'you vs. us'. I think this is a subject that we all need to put our mind to, whichever government it is.

There are two quick points I want to make. Everybody talks about renewable energy. With so much intervention in the renewable energy, how come we are not seeing a big change? Is there a problem with the kitty? Have we ever done a study? There are a lot of conferences on environment; lot of signatures have happened. Even in the Paris Convention, the 'big boys' have left and we are the only countries, the developing countries, who are left in it. So, what will be our stand?

A lot of people talked about Bharat Stage VI. Parvesh Verma said that people from Delhi go next door to fill their gasoline because it is cheaper there. Delhi is Bharat Stage VI now. It is a programme of this Government that by April the entire country is going to be Bharat Stage VI. I would like the hon. Minister to confirm this to us that we are going to be at BS VI level by the time we get there.

In pollution control, there is a commitment. In the last six months, how much of the Budget estimates have been spent on pollution control? I do not see that happening in my State. There are so many reports in this regard. In 2000, there was the Shah Report. In 2002, there was the Reddy Report. In 2004, there was the Gurjar Report. And in 2006, there was the Garg Report. These are all reports on pollution and air pollution and we all are still discussing this. I really do not see how we further deteriorated. I think we really need to introspect. Enough dialogue has happened, a lot of debates have happened, but no change has happened in this entire situation.

1752 hours

(Hon. Speaker *in the Chair*)

I will not repeat the points of lawyers but I would definitely like to make one point to Meenakashi Lekhi Ji. She said that several Chief Ministers, especially hers because she lives here more than I do, are spending a lot of money on advertising. I think he probably learnt it from ours because he became a Chief Minister earlier and he has spent double the amount. So, why do we not all put our minds together? ...(*Interruptions*)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Maharashtra's area is far greater than the area of Delhi. So, if you take into account the population and the geography, no one can break Delhi's record.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Anyway, I am of the belief that Governments are not commodities and they do not need to waste money on advertising. They do not need to market themselves. In Marathi we say, '*Maai baap sarkaar*'. *Sarkar* is your *maai baap*. They have to do everything. They are not a soap that they need to advertise. So, they could put all this money into controlling pollution. Why do we not all send a note to all the Governments that instead of wasting money on advertising, all the Central and State Governments should spend this money to improve all the social sector numbers? Social sector numbers in India are not doing well. health is not doing well, and we do need more money for all this. So, instead of wasting money on doing full-page ads in newspapers, if we put all this money in social sector, especially healthcare, I think it would be a great contribution.

I thank Prakash Ji and I am very hopeful, he is a very learned man and he does not need too many suggestions, that he would kindly clarify my point on all the reports and on CAMPA fund because that is my most important concern in this. Thank you.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल माननीय मंत्री जी का जवाब होगा।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सर, मंत्री जी का रिप्लाई कितने बजे होगा? क्या 12 बजे होगा?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : 12:30 बजे तक रिप्लाई होगा।

मेरा आग्रह है कि कल सदन के नेता प्रतिपक्ष, बड़े दल के नेता अधीर रंजन चौधरी जी के बाद मंत्री जी का जवाब होगा। जो माननीय सदस्य बचे हैं, वे पांच-पांच मिनट में अपनी बात कह दें। बाकी सारी सामान्य चर्चा तो हो ही चुकी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप पांच-पांच मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : सर, दस मिनट दे दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दस मिनट का तो लोगों को ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए, सब अपनी बात पांच मिनट में कह दें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भोला सिंह।

1744 बजे

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, आपने मुझे वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया। आज और परसों, इस विषय पर जो डिबेट हो रहा था, उसमें हमारे साथियों ने, वरिष्ठ वक्ताओं ने दिल्ली में पॉल्यूशन के बारे में चर्चा की।

महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मेरा लोक सभा बुलंदशहर भी दिल्ली से लगा हुआ है, वह 70 किलोमीटर है और एनसीआर का हिस्सा है।

(1755/KDS/SNT)

जितना पॉल्यूशन दिल्ली में है, जितनी समस्या दिल्ली वालों को होती है, उतनी ही समस्या मेरे क्षेत्र के निवासियों को होती है। एनसीआर का हिस्सा होने के बावजूद भी वहां पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। न अच्छे विश्वविद्यालय, न अच्छी मेडिकल सुविधाएं और न ही लोगों को आने-जाने के लिए ट्रेन या मेट्रो की कोई व्यवस्था है। इसके बावजूद जो पॉल्यूशन की मार है, वह मेरे क्षेत्रवासियों को झेलनी पड़ती है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे यहां के जो किसान हैं, उन किसानों को, जो छोटे-छोटे किसान, जो गुड़ बनाने का काम करते हैं, जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं, जो भट्टे चलाते हैं, उनको दिल्ली के पॉल्यूशन की वजह से बुरी तरह से शोषण झेलना पड़ता है। उनके कोल्हू बन्द कर दिए गए हैं। प्रशासन ने इसलिए उन्हें बंद करा दिया, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन है। किसान इसके लिए दोषी नहीं हैं, क्योंकि आज से पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी थीं, जब हम गांव में रहते थे और सोते समय देखते थे तो नीला आसमान और तारे नजर आते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसके और बहुत सारे कारण हैं। यह जरूरी नहीं है कि किसान ही उसका जिम्मेदार है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर किसानों पर जो अत्याचार होते हैं, खासकर दिल्ली-एनसीआर के पास के किसानों पर, वह बहुत ही गलत है। छोटी-छोटी चीजों के लिए पहले किसानों को पकड़ा जाता है, बाकी लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की सरकार की बात करें तो हम देखते हैं कि यमुना की हालत कितनी बुरी है। यह बिल्कुल गन्दा नाला लगती है। दिल्ली की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन को ठीक करने के लिए हर जिले में लाखों की संख्या में पौधे लगाए हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार सोई हुई है। अगर यमुना के किनारों पर पौधे लग जाएंगे तो दिल्ली की हवा भी शुद्ध होगी और उसकी सफाई भी होगी। यह एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात से अवगत कराना चाहूंगा कि किसान जो पराली जलाता है, गन्ने की पताई जलाता है, उनका इसमें उतना योगदान नहीं है, जितना की दिल्ली-एनसीआर की जनसंख्या का, जो इतनी बढ़ रही है। दिल्ली में इतने ज्यादा लोग हैं। पहले हम दिल्ली से बुलंदशहर आते थे तो जंगल ही जंगल दिखता था, लेकिन आज बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें नजर आती हैं। दिल्ली की जनसंख्या जितनी बढ़ रही है और दिल्ली-एनसीआर के आसपास लोग होने की वजह से और दिल्ली में आसपास के जो लोग रोजगार की वजह से आकर बसने लगे हैं, वह एक बड़ा कारण

है। अतः मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण देश में बढ़ती हुई जनसंख्या है। संसाधनों के मुकाबले जनसंख्या ज्यादा है। बहुत सारी चीजों को लेकर हमारी सरकार द्वारा सोलर एनर्जी, वृक्षारोपण, जल संरक्षण पर बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। दिन-प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पहले यह समस्या नहीं थी। सुविधाएं कम थीं, लेकिन ये समस्याएं नहीं थीं। इन समस्याओं के कारण ही जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण फैल रहा है। अतः मुख्य कदम उठाने के साथ-साथ जनसंख्या कन्ट्रोल पर भी हमें विचार करना होगा और उस पर रोक लगानी होगी, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, उसको इस समस्या का सामना न करना न पड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह से अपनी बात कह रहे हैं, पर मेरा इतना आग्रह है कि इसी बात को संक्षेप में कहें। सारगर्भित तरीके से बात न कहकर संक्षेप में कहें। मैं चाहूंगा कि 6:00 बजने वाले हैं, इसलिए 6 बजकर 25 मिनट तक यह सदन स्थगित कर दिया जाए, फिर 6:25 मिनट पर देखते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हां, बोलने के बाद माननीय सदस्यगण एकदम सदन से बाहर निकलें। नियम और प्रक्रिया की किताब में लिखा है।

1759 hours

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you Sir, for giving me this opportunity to speak on this subject. It is great that hon. Minister is also here. Sir, all my colleagues have been very passionately giving their suggestions about pollution and how we can control it. In the last Session, which was my first Session, I was here and everyone was so passionate and everyone was talking about not having drinking water in their constituencies or in their districts. Had we had a Session in the month of October, I am sure, all of us would have been as much passionate as we are right now and we would have been talking about how our cities are drowning in the torrential rains.

(1800/RK/MM)

We cannot take each one in silos. We cannot take each problem, either pollution, waterlogging in cities or lack of water in various States, individually. It is all related to environment. We have to take everything in a unified manner.

As the Minister for Environment is here, we have all the solutions also here. I was listening in the morning to the Jal Shakti Minister. He was saying that if we could bring down ten per cent of water usage, we can actually give drinking water to most of the people in this country.

If you look at the issue of Maharashtra, if we could bring down the cultivation of sugarcane by ten per cent, we would not be having the problem of ferrying water in the tankers to the distant lands.

With regard to waterlogging also, in cities like Mumbai and Chennai we are seeing that whenever there is a torrential rain the water gets logged in the cities and no one can move out. We are not following the FSA rules. We are not planning the cities in such a way that water gets absorbed into the ground. These are all the issues that we have to take in a cohesive way. We have to take them in a way that we find solutions to all these things.

If we look at the pollution problem right now, a lot of people have given solutions to it, like green energy, cutting down on cars or increasing the metro transport. All these solutions are there but somehow, we are not acting.

A lot of Members yesterday quoted the Chinese example. A lot of Members have quoted how Beijing has come down on pollution. Let me quote the experience that I had. I have made a lot of visits to a place called Guangzhov in China. It is an industrial town which exports a lot of stuff to many countries

across the world. Once they figured out that a lot of pollution is happening because of the industries, they were ready to let go of those industries. They were clear that they did not want any of those industries which was polluting the country. They were ready to let go of their economy and their employment also. Most of the industries were moved to Vietnam and other countries. They were ready to act on it. That is exactly what we have to do. We need to act on it. We have all the solutions but somehow, we are not ready to act.

I would, therefore, urge the Minister to have a National Environment Policy. We have solutions. Let us have those solutions implemented by drafting the National Environment Policy. Just the Minister for Environment cannot bring solutions. We should bring in Health Minister, Jal Shakti Minister and Transport Minister together.

Let me give another example and conclude. In 1960s Japan had huge smog. Vehicles were creating a lot of smog. Let me tell you, Sir, it is the first country in the world which has started BS-III or BS-IV mark, which we are seeing right now. They were ready to burden their economy and start BS-III and BS-IV marking and they made innovations because of that. Right now, if you see cars like Honda, Toyota, they are much more fuel efficient. It is because they were ready to take hard decisions.

I would urge the Minister for Environment to take hard decisions, not just for Delhi but for the country so that our future generations will thank all of us, here.

Thank you very much for giving me this opportunity.

(ends)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, I must appreciate that without looking at a piece of paper, he has spoken extempore and has spoken outstandingly.

माननीय अध्यक्ष : नये माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोले हैं।

(1805/PS/GG)

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri D.K.Suresh in Kannada,
please see the Supplement. (PP 394A to 394B)}

(1810/SNB/KN)

1810 hours

DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA): Respected hon. Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to speak on serious issue like Air Pollution and Climate change. I am also thankful to my party high command to nominate me as speaker on such an important topic. Many hon. Members, my fellow colleagues from both sides of the House have discussed different aspects of air pollution and climate change. Most of them have highlighted vividly the ill effects of air pollution and climate change and the condition of Indian metro cities in comparison to other cities of developed countries of the world.

Preventive measures were started in India in 1981 and 1986 through Air (Prevention and control of Pollution) Act and Environment (Protection) Act. Those laws were formulated by hon. Members of the then Parliament for a noble cause. Who ran the Governments in 1986 till 1999 and again from 2004 to 2014? They were the ancestral leaders of the hon. Member who has raised this subject under Rule 193.

Sir, it is easy to recite the bad effects of air pollution as written in reference desk from 1 to 8 and also about the sufferings of glaciers but why did not any specific and capable agency be developed during that period? But during this period, under the leadership of our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, the Government has taken excellent measures which include 8 National Missions and initiated very important steps including Prime Minister's Council on Climate Change in the last five and half years. There is also a High-Level Task Force and so many other initiatives have been taken by this Government.

I would conclude with a statement – success will come through coordination of Central, State, local bodies along with mass awareness.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : श्री गिरीश चन्द्रा तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

1812 बजे

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में चल रही अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदूषण से केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरा देश खास कर यूपी में बहुत बड़ा संकट है, जहां पर 14 जिले प्रदूषण से प्रभावित है। जिस जिले में हम लोग रहते हैं, जहां से चुन कर हम आए हैं, वहां भी प्रदूषण बहुत है। इसके कारण वहां पर तमाम बीमारियां, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों की समस्या, हार्ट की समस्या, अगर हम दिन में एक घंटा कार्यालय में बैठते हैं तो बीमारी के कारण तमाम लोग वहां पर हमसे पर्चा लिखाने के लिए आते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल जनसंख्या वाले प्रदेश के ज्यादातर शहर इस भयानक समस्या से पीड़ित हैं। इसके मूल कारणों को समझ कर इस पर समुचित ध्यान देना अब बहुत ही जरूरी है। सरकार इस पर तुरंत प्रभावी ध्यान दे तो बेहतर है। वैसे तो सरकार की लापरवाही आदि के कारण प्रदूषण व्यापक जनसमस्या का रूप ले चुका है तथा लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। इसलिए प्रदूषण पर संसद में चर्चा के बाद इस पर ठोस नीति बने और एक कार्यक्रम बनाकर इसको सख्ती से लागू कराने का प्रयास माननीय अध्यक्ष जी आपको करना चाहिए। जनहित में यह कदम अति महत्वपूर्ण कदम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से हमारे यहां वृक्ष लगाए जाते हैं, सरकार का पैसा भी उसमें जाता है, जिला हैडक्वार्टर्स में जाता है, ब्लॉक और ग्राम सभा में भी पेड़ लगते हैं। लेकिन पेड़ लगने के बाद, यदि एक लाख पेड़ हमारे जिले में लगते हैं तो मात्र 20 परसेंट पेड़ ही जीवित रहते हैं, बाकी पेड़ खत्म हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा कि पेड़ भी लगें और ऐसी कोई नीति भी हो, जिससे पेड़ सुरक्षित रहें। अगर पेड़ सुरक्षित रहेंगे तो पेड़ निश्चित तौर पर प्रदूषण को समाप्त करने का काम करेंगे। हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स के प्रांगण हैं, वहां पर ऐसे पेड़ लगाए जाएं, जिससे ऑक्सीजन आए। इससे वहां पर जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका भी स्वास्थ्य बेहतर होगा। ऐसी मैं माँग आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : श्री दुर्गा प्रसाद जी, आप एक मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं?

श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राँव (तिरूपति): सर, एक मिनट में क्या होगा?

माननीय अध्यक्ष : आप फ्राइडे को अपनी बात रखिएगा।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रना

(1815/RU/CS)

1815 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker Sir, I thank you very much for affording this opportunity to speak on a very important subject. I would like to appreciate the hon. Speaker for having taken the initiative in having this discussion because wherever we go to participate in the international fora, we find that they are all having a debate on climate change. And now, we are discussing the issue of climate change in the light of highest toxic air pollution in the city of Delhi, the capital of our country.

Climate change is one of the greatest threats to global prosperity and development. Due to human activities contributing to emission of greenhouse gases, the international community is on a warming trajectory that will leave the world irrevocably changed. It may result in unimaginable sea level rise, vastly different climates and persistent droughts, devastating heat waves and unprecedented floods.

According to the Foundations of Human Society, food and health security, infrastructure and eco system integrity would be in jeopardy and the most immediate impact would be on the poor and vulnerable sections of the society. Sir, the immediate worsening impact of climate change would be on the marginalised sections of the society.

What is the response to the climate change? The urgent need is to reduce the green house gas emissions in order to limit global average temperature rise to below 2 degree Celsius from pre-industrial levels and pursue earnest efforts to limit the temperature rise to below 1.5 degree Celsius above pre industrial levels. This would significantly reduce the impact and risk of climate change in our country and the world as a whole.

In response to this, the new International Agreement has come into effect. We know that Paris Agreement is globally accepted but unfortunately, recently, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump has declared that they are going to withdraw from the Paris Agreement. When that situation is there, this Paris Agreement has to be applied from 2020 onwards. The world has already adopted a new universal carbon emission cutting regime from 2020 onwards. The main question which I would like to ask the Government is this. Is India, through the national legislation as well as the national platform of action,

able to honour the commitments which we have made in the Paris Agreement so that carbon emission could be reduced to the international level or to the standard which has already been agreed upon by the Paris Agreement?

Sir, US always alleges that India and China are the most polluting countries in the world. It is absolutely a wrong notion on the part of the US. The per capita carbon dioxide emission of US is 16.8 tonnes. Per person, per year, it is 16.8 tonnes. As far as India is concerned, the per capita carbon dioxide emission is only 1.67 tonnes. That means it is only one-tenth of the US emission. Highest emission is depending on the highest consumption. But still they are alleging that India and China are the most polluting countries. The negotiation is still going on in the United Nations Framework Convention on Climatic Change that developed countries have to compensate the developing countries because they have already been saturated. The compensation is based on the principle, "Common But Differentiated Responsibility". That is the globally accepted principle as far as the compensatory course for environment protection is concerned. The main point which I would like to say once again to the hon. Minister as well as to the Government is that ease of doing business and environment protection will never go together. That is the point which you have to address. We are all for sustainable development. Even as per the Sustainable Millennium Development Goals enunciated by the UN Convention, environment protection means sustainable development.

Sir, firstly, I would like to talk about the Forest Conservation Act. In order to have non-forestry activities in the forests, prior permission and confirmation are required. Unfortunately, as part of the recommendations in the Subramaniam Committee Report, you have already diluted the Forest Conservation Act for non-forestry activities in the forests.

The National Green Tribunal Act is one of the very important enactments made by the Parliament. This National Green Tribunal Act is also diluted through a Money Bill by which the tooth and nail of the NGT has already been taken away.

(1820/NKL/RV)

That was the best instrument by which the Environmental Protection Laws were implemented in the country. The powers and also the authority of the National Green Tribunal were diluted.

Coming to the third point which I would like to make is regarding the Coastal Zone Management Act. That also, by virtue of a notification, has been diluted.

Coming to the issue of forest conservation, if you see, I will just cite an example. As far as the State of Gujarat is concerned, now, we are having 14,000 square kilometres of forest area. During the last one and a half decades, 10,000 square kilometres of forests were destructed in Gujarat. The State is now left only with 4,000 square kilometres of forests. The total forest area is 7.5 per cent. The National Forest Policy of 1998 says that there should be an average of 33 per cent of forest coverage across the country. In my State, we have enhanced the forest coverage area. We are having 52 per cent of forest coverage area. As far as the developed State like Gujarat is concerned, it is only having 7.5 per cent of forest coverage area. That is the way in which we are dealing with this subject.

The fourth issue is regarding the Forest Rights Act. In case of linear projects, as far as the Forest Rights Act is concerned, no public hearing is required as per the new notification. All these laws – Forest Rights Act, Forest Conservation Act, Environmental Protection Act, National Green Tribunal Act, Coastal Zone Management Act – if you see, in the name of ease of doing business, we have diluted them, we have amended them, and we have issued so many notifications. As a result, definitely, this environmental protection will be compromised. So, I would like to say that environmental protection shall not be compromised for the sake of ease of doing business. That is the point which the Government has to take into consideration for which a political will is required.

Sir, we all know the causes of the climate change. We all know what are the reasons by which the air pollution is becoming very toxic in the National Capital, Delhi. There are so many reasons. We are well aware of them. We are also well aware of the solutions. So, we have to act very stringently in this regard. We have to have a political will so as to address this issue, by implementation of the environmental laws without compromising, for the sake of development. Otherwise, we will be in a precarious condition. That will be very adversely affecting our country in total.

Sir, the Report of Inter-Governmental Panel on Climate Change, 2007 states that formerly, periodicity of the floods was 100 years. In my State of Kerala, in 2017, there was Ockhi; in 2018, there was a big flood; in 2019 now, there are landslides and so many other natural disasters. So, these are all the consequential effects of climate change which we are also facing. A God's Own Country like Kerala is also facing such a severe and adverse conditions. So, we have to have a strong policy, a national platform of action, not to compromise with the environmental laws, not to compromise with anything, as far as air pollution and environmental protection are concerned.

Regarding, the Delhi issue, there are five to six reasons of it. I am not going into all. The issue of agriculture and paddy is the main issue which we always are blaming. It is quite unfortunate to blame the farming community in the country.

Regarding the thermal power stations, an hon. Member has already stated that the operation of thermal power stations surrounding Delhi have to be relooked. Regarding the construction industry, today also, we have received so many complaints. Nowadays, there is an environmental terrorism by the NDMC Officials. Even painting is not allowed; repair is not allowed. NDMC is taking advantage of this issue. The vehicular population and industrial pollution also need to be checked.

I conclude by saying that the Environmental Protection Laws and related rules, notifications have to be strictly implemented, and stringent action is required in this regard. With these words, I once again take this opportunity to congratulate the hon. Speaker Sir for having taken the initiative to have a discussion on climate change and air pollution. Thank you very much.

(ends)

(1825/MY/SRG)

माननीय अध्यक्ष: आजकल अगर पूरे विश्व में किसी विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, तो वह क्लाइमेट चेंज पर होती है। मैं भी जिस देश में गया हूँ, वहाँ पर भारत की तरफ से क्लाइमेट पर एजेंडा दिया गया और हमारा एजेंडा स्वीकार हुआ। जो एन.के.प्रेमचन्द्रन जी बोल रहे हैं, उसमें काफी सत्यता है। हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी भी सदन में हैं। आज सदन में इस विषय पर बहुत अच्छी चर्चा हुई, इसलिए सभी को धन्यवाद है। कल औपचारिक धन्यवाद दिया जाएगा और आप सब की उपस्थिति में रिप्लाइ होगा।

सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 22 नवंबर, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1826 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 22 नवंबर, 2019/1 अग्रहायण 1941 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।